Queen Mary
University of London
Global Policy Institute

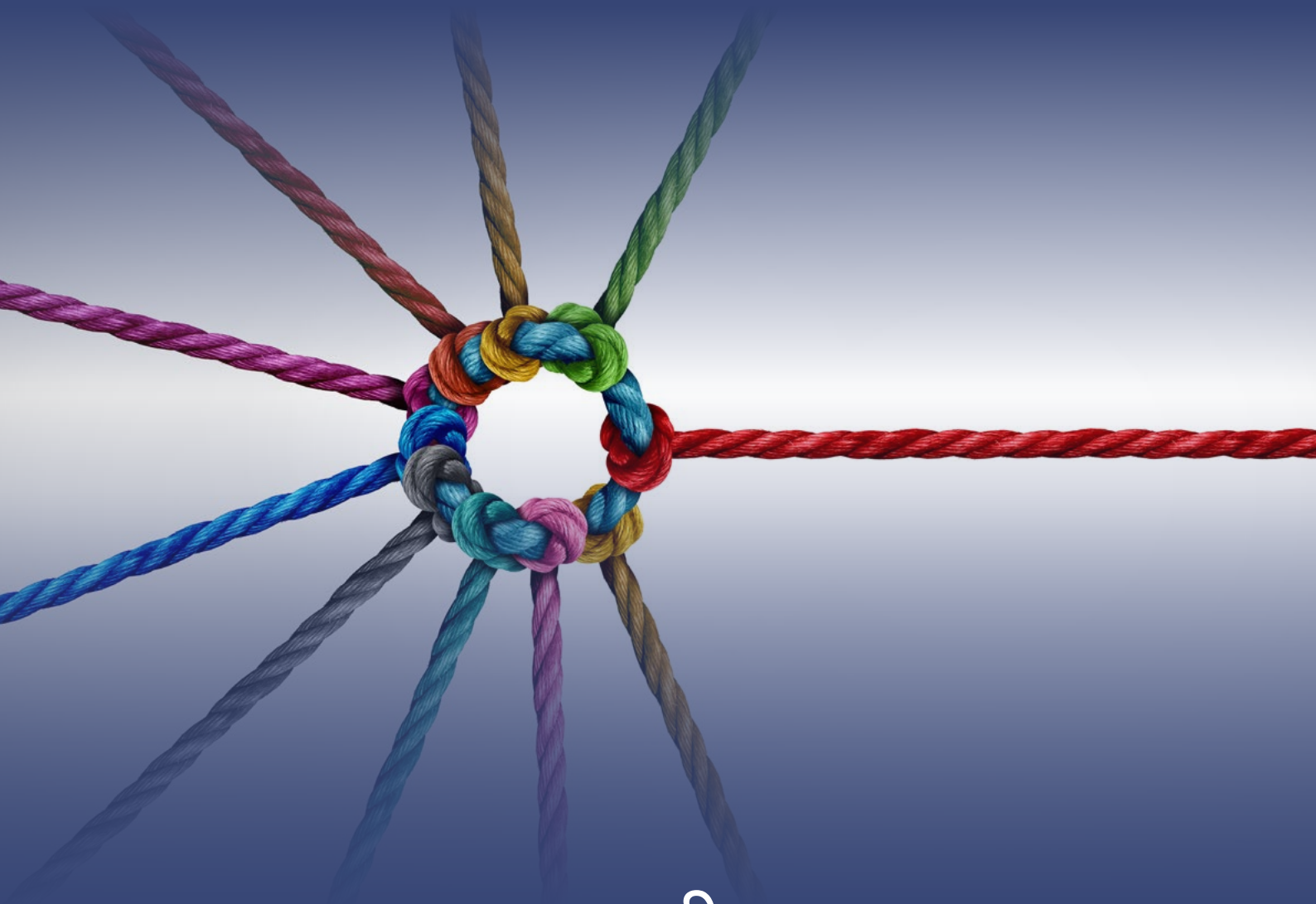

प्रवासन, महामारी और तीसरे सेक्टर की प्रतिक्रियाएँ: ब्राज़ील और भारत के उदाहरण

लेखक-गण:
पार्वती नायर, मार्सिया वेरा ऐस्पिनोज़ा, जिसेला पी ज़पाता, स्मिता तिवारी, फ्लाविया आर कास्त्रो, अर्सला निज़ामी, नुनी जोर्गेनसेन, अभिषेक यादव, एकता ओझा, फ़िरोज़ ख़ान, राकेश रंजन, बेनेडेट्टा जोस्ची, सुयश बार्वे, मारिया बर्राको

qmul.ac.uk/gpi

यह रिपोर्ट उन प्राप्त परिणामों की चर्चा करती है जो प्रोजेक्ट 'प्रवासन, महामारी और तीसरे सेक्टर की प्रतिक्रियाएँ: ब्राज़ील और भारत के उदाहरणसे प्राप्त हुए हैं। इस शोध को क्यू एम् यु ऐल (QMUL) ग्लोबल

पॉलिसी इंस्टिट्यूट (GPI) के रिसर्च इंग्लैंड क्यू आर स्ट्रेटेजिक रिसर्च प्रिओरिटीज़ फण्ड से प्रायोजित किया
गया है।

इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व और संचालन क्वीन मैरी युनिवर्सिटी, लंदन (QMUL, UK), मिनास जेराइस फ़ेडरल
यूनिवर्सिटी, ब्राज़ील (UFMG), और ग्लोबल रिसर्च फोरम ऑन डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनलिस्म
(GRFDT), भारत के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है।

लेखक-गण और शोध टीम
प्रोफेसर पार्वती नायर, प्रोजेक्ट सह-प्रमुख जाँचकर्ता, QMUL
डॉ मार्सिया वेरा ऐस्पिनोज़ा, प्रोजेक्ट सह-प्रमुख जाँचकर्ता, QMUL
डॉ जिसेला पी ज़पाता, प्रोजेक्ट सह-जाँचकर्ता, UFMG
डॉ स्मिता तिवारी, प्रोजेक्ट सह-जाँचकर्ता, GRFDT
डॉ फ्लाविया आर कास्त्रो, शोध सहयोगी, UFMG
डॉ अर्सला निज़ामी, शोध सहयोगी, GRFDT
नुनी जोर्गेनसेन, शोध सहायक, QMUL
अभिषेक यादव, शोध सहयोगी, GRFDT
एकता ओझा, शोध सहायक, QMUL
डॉ फ़िरोज़ ख़ान, शोधकर्ता, GRFDT
डॉराकेश रंजन, शोधकर्ता, GRFDT
बेनेडेट्टा जोस्ची, शोध सहायक, QMUL
सुयश बार्वे, GPI शोध सहयोगी, QMUL
मारिया बर्राको, GPI शोध सहयोगी, QMUL

सलाहकार बोर्ड: सुश्री सिंटीया संपाइओ, प्रोफेसर कविता दत्ता, प्रोफेसर बिनोद खादरिया और डॉ ए दीदार सिंह

इस प्रकाशन को यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है
https://www.qmul.ac.uk/gpi/projects/migpanbrin/
यह रिपोर्ट क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन-नॉन-कमर्शियल (Creative Commons Attribution-NonCommercial) 4.0 लाइसेंस की शर्तों के अंतर्गत उपलब्ध है।

आवश्यक संदर्भ: Nair, P., Vera Espinoza, M., Zapata, G.P., Tiwary, S., Castro F.R., Nizami, A., Jorgensen, N., Yadav, A., Oza, E., Khan, F., Ranjan, R., Zocchi, B., Barve, S., and Barraco, M. (2021) प्रवासन, महामारी और तीसरे सेक्टर की प्रतिक्रियाएँ: ब्राज़ील और भारत के उदाहरण। QMUL: लंदन।

विषय तालिका

कार्यकारी सारांश 4
1. परिचय 5
2. सन्दर्भ 6
2.2. ब्राज़ील
2.3. भारत
3. कार्यप्रणाली 12
4. ब्राज़ील और भारत में नागरिक समाज और प्रवासन 13
4.1 ब्राज़ील में नागरिक समाज का एक संक्षिप्त इतिहास
4.2 भारत में नागरिक समाज का एक संक्षिप्त इतिहास
5. प्राप्त परिणामों पर चर्चा 22
5.1 ब्राज़ील से प्राप्त परिणाम
5.1.1 महामारी के दौरान प्रवासियों के सामने आई चुनौतियाँ
5.1.2 नागरिक समाज संगठनों की भूमिका: उदाहरण और अच्छे कार्य
5.1.3 नीतिगत सुझाव
5.2. भारत से प्राप्त परिणाम
5.2.1 महामारी के दौरान प्रवासियों के सामने आई चुनौतियाँ
5.2.2 नागरिक समाज संगठनों की भूमिका: उदाहरण और अच्छे कार्य
5.2.3 नीतिगत सुझाव
6. निष्कर्ष 42
अनुलग्नक 43
संदर्भग्रंथ सूची 45

कार्यकारी सारांश

यह रिपोर्ट कोविड-19 के संदर्भ में ब्राजील और भारत में प्रवासियों और शरणार्थियों की सहायता करने मेंगैर-सरकारी संगठनों, पंथ /आस्था पर आधारित संगठनों तथा प्रवासी-नेतृत्व वाले संगठनों सहित नागरिक समाज संगठनों (CSOs) की भूमिका की एक व्यापक समीक्षा और अंतर-क्षेत्रीय विश्लेषण प्रदान करती है।

इसके अंतर्गत, दोनों देशों से 52 नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ अर्द्ध-ढांचागत साक्षात्कारों
के जरिए, हमनें उन चुनौतियों और अच्छे कार्यों की पहचान की है जिनका उत्थान मार्च 2020 और फरवरी
2021 के बीच आपदा के काल के दौरान हुआ था। अग्रिम-मोर्चे के कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए,
यह अध्ययन प्रवासी जनसंख्या के आधार पर संदर्भों, आवश्यकताओं और जोख़िमों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता
है। उन नागरिक समाज संगठनों द्वारा उनको उपलब्ध कराई गई सहायताओं के स्वरूपों और उन तरीकों की
पहचान करता है जिससे सरकारें सुरक्षा, एकता, समावेशन और लंबी-अवधि में सामाजिक बंधुत्व के लिए
नागरिक समाज संगठनों के मानवीय कार्य को समर्थन कर सकती हैं।

मुख्य परिणाम:

- कोविड-19 ने ब्राज़ील और भारत में आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों को व्यापक रूप से बहुत प्रभावित किया है। सीमा की बंदी (ब्राज़ील में) और अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के प्रतिबंध (भारत में) के प्रभावों के साथ ही साथ दोनों देशों में अपनाए गए विभिन्न राहत के उपायों ने, प्रवासियों के निजी स्वास्थ्य और जीवन स्तरों में एक बड़ी चुनौती को जन्म दिया है।
- प्रवासियों और शरणार्थियों ने, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, महामारी का सामना करने के लिए रणनीतियों और कार्यवाईयों का विकास किया है।
- नागरिक समाज संगठनों ने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने और आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराने के लिए नई गतिविधियों की व्यवस्था का अनुमान करते हुए, नई चुनौतियों से निपटने के लिए तेजी से काम किया है।
- महामारी के चलते नागरिक समाज संगठनों के कार्य के डिजिटलीकरण और तकनीकीकरण में वृद्धि हुई और इससे काम करने के हाइब्रिड तरीकों को बढ़ावा मिला। कुछ मामलों में डिजिटलीकरण के कारण, सेवाओं का लाभ अपनी भौगोलिक सीमा के बाहर भी लोगों को मिला, जबकि कुछ अन्य मामलों में, इन उपकरण और नई तकनीकों के ज्ञान की कमी के चलते उनकी प्रभाव क्षमता सीमित रह गयी।
- नागरिक समाज संगठनों का एक दूसरे के साथ, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, कुछ स्थानीय सरकारों और निजी क्षेत्रों के साथ भी सहयोग बढ़ा है । हालाँकि, सभी भागीदारियों का परिणाम आय के अतिरिक्त स्रोतों के रूप में नहीं निकला है।

मुख्य सुझाव:

- नीतियों और कार्यों के बीच सामंजस्य विकसित करें जो धरातल पर नीतियों के एक बेहतर क्रियान्वयन के लिए अनुमति देती हैं। हो सकता है यह प्रवासन के राष्ट्रीय और स्थानीय प्रशासन में कुछ अंतरों को सुलझाने में सहायक हो जो प्रवासियों के समावेशन को सीमित करते हैं।.
- राज्य और नागरिक समाज संगठनों के बीच, स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर संवाद के स्थानों को बढ़ाएँ और उनका निर्माण करें, साथ ही साथ मौजूदा संवाद को मज़बूत करें।
- निर्णय लेने में प्रवासियों के प्रतिनिधित्व और भागीदारी को बढ़ाएँ।
- प्रवासियों को नियमितिकरण को बढ़ावा दें। ब्राज़ील के मामले में, सभी प्रवासियों को नियमित करने के लिए ध्यान दिलाना है जिससे राज्य-गारंटीड सामाजिक सुरक्षा और सुविधापूर्ण समावेशन के लिए उनकी पहुँच सुनिश्चित हो। भारत के मामले में, नागरिक समाज संगठनों नें श्रम के अनौपचारिक स्तर को नियमित किए जाने या इसका दस्तावेज़ीकरण किए जाने की मांग की है, जिससे प्रवासी मज़दूरों को सुरक्षा मिले।
- इसके अतिरिक्त बतौर साझीदार, प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए रणनीतिगत योजना बनाने में सरकार के साथ, अन्य गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर उनको शामिल करने के लिए नागरिक समाज संगठनों के ज्ञान और अनुभव की गहराई और सीमा की पहचान करें।

परिचय

कोविड-19 महामारी ने इस बात को सत्यापित किया है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वह काफी गहराई से चलायमान और आपस में जुड़ी हुई है (Guadagno 2020)। इसका प्रसार महाद्वीपों के पार है जहाँ चलायमान लोगों के अनगिनत समूहों के पास पहले से ही गंभीर जोखिमों भरी समस्याएँ थीं (UNHCR 2017; IOM 2019)।

प्रवासन की नाजुक स्थितियों की गंभीरता और क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय समाधानों की विविधता ने भी उन उपायों को गहराई से प्रभावित किया है जिससे महामारी ने राज्यों के भीतर प्रसार पाया है (विश्व बैंक 2020)। ब्राज़ील और भारत में, दो उभरती हुई क्षेत्रीय शक्तियाँ पहले से ही ढांचागत असमानताओं के उच्च स्तर से पीड़ित हैं (Couto Soares & Scerri 2014), और इन देशों में कई प्रवासी समूहों ने अपने आप को विशेष तौर पर महामारी के दौरान जोखिम की स्थिति में पाया है। दोनो देशों में, राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारें कमज़ोर स्थिति वाले समूहों की आवश्यकताओं का समाधान करने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हैं, कई नीतियों और/या क्रियान्वयन में कमी इस बात का खुलासा करते हैं। (Lotta et al. 2020; Sircar 2020)। दोनों देशों में, नागरिक समाज की ओर से दिए गए तुरंत के उपचारों ने कई प्रवासियों को बहुत-आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई है (Vera Espinoza et al. forthcoming; Bengochea et al. 2021; Ramachandran 2020)।

यह रिपोर्ट नागरिक समाज, जिसमें गैर सरकारी संगठनों, पंथ-आधारित और प्रवासी-प्रमुखता वाले संगठनों की भूमिका का एक संपूर्ण-क्षेत्रीय विश्लेषण प्रदान करती है, जिसका संदर्भ कोविड-19 की महामारी के

दौरान, ब्राज़ील और भारत में प्रवासियों और शरणार्थियों की सहायता करने से है। ब्राज़ील और भारत, बहु-जातीय लोकतंत्र होने के साथ, स्वयं को बतौर विकासशील देश की स्थिति में रखते हैं (IBSA 2020)। यह दोनों BRICS संगठन के अंतर्गत एक समूह में है, उनको विकासशील दुनिया के दो आर्थिक महाशक्तियों के रूप में जाना जाता है तथा ये दोनों देश कमर्शियल और वित्तीय सहयोग के एक अंतर्राष्ट्रीय ऐजेंडा को साझा कर रहे हैं (Formici 2019), और उनका अपने-अपने महाद्वीप में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रभुत्व है। दोनो देशों के केंद्रीय शहरी इलाकों में उद्योगों और मूलभूत सुविधाओं का संघनन सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रवासियों को आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रूप से आकर्षित कर रहा है (Korobkov 2015)।

ब्राज़ील लैटिन अमेरिका में क्षेत्रीय और क्षेत्र से बाहर के प्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें अन्य कारणों के साथ बोलीविया, वेनेजुएला के लोगों का आर्थिक और सामाजिक-राजनैतिक समस्याओं से, और हैती के प्रवासियों का आर्थिक और मानवीय कारणों से भागकर आना शामिल है (Lesser et al. 2018)। भारत में आंतरिक प्रवासन, उसके वैश्विक प्रवासी और आप्रवासन द्वारा उल्लिखित किया गया है। आंतरिक प्रवासन भारत के शहरी ढांचे का एक मुख्य स्वरूप बनाता है और 'भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी' है (Bhagat 2020; Suresh & James 2020). देश में अवैध प्रवासियों के समूह भी आते हैं, जिनका अधिकांश भाग पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल से आ रहा है (Upadhyay 2008).

दोनों देशों में, महामारी, और विशेष रूप से लॉकडाउन और स्वास्थ्य समस्या के समाधान के लिए लागू किये गए सीमाओं की बंदी ने नई चुनौतियों को पेश कर दिया जो पहले से ही कमज़ोर प्रवासी समूहों के लिए और दुखद थीं। ब्राज़ील में, शारीरिक दूरी के उपायों ने हज़ारों की संख्या में बहुमूल्य प्रवासी मज़दूरों को बेरोज़गार कर दिया। अप्रत्याशित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों ने भी सीमा के करीब के राज्यों जैसे

रोराइमा में फंसे वेनेजुएला के और दो देशों की सीमा को जोड़ने वाले पुल पर घिरे पैराग्वे के लोगों के लिए नए रूप की अनैच्छिक/बलपूर्वक गतिहीनता को जन्म दे दिया है। 2020)। भारत में, 23 मार्च 2020. कोघोषित किए गए लॉकडाउन ने, शहरी इलाकों से छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों के लिए प्रवासी मज़दूरों के विशाल पलायन और, विदेशों से भारतीय कामगारों की सामूहिक वापसी को आरंभ कर दिया, जोबेरोज़गार और संसाधन विहीन थे। उत्तर-पूर्व में, अवैध प्रवासियों ने स्वयं को, बिना किसी कमाई या सहायता के और साथ ही घर वापस ना जा पाने की असमर्थता के चलते अपने आप को फंसा हुआ पाया (Nair & Vera Espinoza 2021). महामारी द्वारा पेश की गई चुनौतियों के अतिरिक्त, दोनों ही देशों में सरकारों ने कमज़ोर प्रवासियों की नाजुक स्थितियों को संभालने के लिए अपने आप को बुरी तरह से बिना किसी तैयारी के पाया (Lotta et al. 2020; Sircar 2020)। दोनों ही मामलों में, मज़बूत नागरिक समाज संगठनों ने कई मौकों पर स्थानीय सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय करते हुए, महामारी के प्रभावों से राहत दिलाने.

2. सन्दर्भ

2.1 ब्राज़ील

लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील वह पहला देश था जिसमें 26 फरवरी 2020 को कोविड-19 का केस दर्ज़ हुआ था। एक साल के भीतर ही, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस देश में करीब 1 करोड़ केस और 290.000 से अधिक मृत्यु हुई हैं (WHO 2021).

दुनिया में ब्राज़ील एक मात्र देश है जिसकी 21.2 करोड़ की आबादी (IBGE 2021) को एक मुफ़्त, सार्वभौमिक और विस्तृत स्वास्थ्य सिस्टम प्राप्त है (PAHO 2017)। इस तथ्य ने, महामारियों से लड़ने वाले ब्राज़ील के इतिहास के साथ, अन्य लैटिन अमेरिकी देशों के मुकाबले में, इस विशेष स्थिति ने वायरस के विरूद्ध लड़ाई का आरंभ करने में ब्राज़ील को एक लाभप्रद की स्थिति में रख दिया था। हालाँकि, ब्राज़ील के राष्ट्रपति, जैर बोल्सोनारो ने, उन बातों को लागू किया जिनको "वायरस के निर्मूलन के लिए संस्थागत रणनीति" कहा गया है (Brum 2021), जिसने देश को संक्रमण और मौत की दरों में वृद्धि के लिए शीर्ष रैंक पर पहुंचाने में अपना योगदान दिया था। इस संदर्भ में, प्रवासी और शरणार्थी आबादी समाज में उनकी अनिश्चित सामाजिक-आर्थिक समावेशन के चलते महामारी द्वारा सबसे अधिक प्रभावित थे (Zapata & Prieto Rosas 2020).

ब्राज़ील में प्रवासन का झुकाव और प्रवृत्तियाँ 2008 वैश्विक आर्थिक मंदी के समय से ही महत्वपूर्ण बदलावों से गुज़र चुकी है। हालांकि देश को आम तौर पर 1980 के दशक से अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के गंतव्य के बजाय एक स्रोत के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन पिछले दशक को अंतरराष्ट्रीय अप्रवासन दरों में बढ़ोतरी के द्वारा चिह्नित किया गया है (Fernandes 2015; de Oliveira 2013). 2010 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि ब्राज़ील में रह रहे विदेश में जन्मे नागरिकों में से 22.14% दूसरे दक्षिण अमेरिकी देशों से थे: अधिकांश बोलीविया और पैराग्वे से थे, इसके बाद अर्जेंटीना और उरूग्वे से थे (Fernandes 2015). वैसे, 2010 की जनगणना ने पिछले कुछ सालों में ब्राज़ील में हो रही कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रवासन प्रवृत्तियों को प्रदर्शित नहीं किया था: 2010 से लगातार हैती के नागरिकों का आना, और खास तौर पर 2016 के अंत से वेनेजुएला के नागरिकों का भी.

एक अनुमान के मुताबिक, 2010 और 2015 के बीच, देश में 85.079 हैती नागरिक प्रवेश किए, जो मुख्यb तौर मानवीय आवासीय वीजा या शरणार्थी के तौर पर आए थे। इस जनसंख्या में पुरूषों और नौजवानों का दबदबा था - 73.9% पुरुष थे और 20-34 आयु वर्ग के समूह से संबंधित थे (Baeninger & Peres 2017)। वेनेजुएला के लोगों की बात करें तो, कम से कम 223.163 लोग औपचारिक रूप से 2019 देश में प्रवेश कर चुके थे और शेष 66.956 ने यह काम 2020 में किया। अगस्त 2020 तक, 46.000 वेनेजुएला के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से ब्राज़ील की प्रशंसा की जा रह थी, जिससे उनका देश लैटिन अमेरिका में सबसे अधिक वेनेजुएला शरणार्थियों को रखने वाला देश बन गया था (ACNUR 2020a)। ब्राज़ील में रहने वाले अधिकांश वेनेजुएला के नागरिक नौजवान व्यस्क हैं, और उनका प्रवाह लैंगिक रूप से निष्पक्षता के साथ संतुलित है (Cavalcanti & de Oliveira 2020)। हैती, वेनेजुएला, और मर्कोसुर प्रवासियों के अलावा, ब्राज़ील ने पिछले दस वर्षों में गैर-क्षेत्रीय प्रवासियों और शरणार्थियों को भी स्वीकार किया है– आंशिक तौर पर एकजुट पुनर्वास प्रयासों एक परिणाम के तौर पर – अन्य देशों से जैसे कि सीरिया, फिलिस्तीन, सेनेगल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (Vera Espinoza 2018).

वर्ष 1997 में, ब्राज़ील ने शरणार्थी अधिनियम (विधि 9.474) को पारित किया था, जिसमें राष्ट्रीय कानून 1951 के शरणार्थी समझौते और कार्टाजेना समझौते के कुछ तत्वों का समावेशन करते हुए, और शरणार्थियों के लिए राष्ट्रीय समिति की स्थापना करना शामिल था (CONARE)। ब्राज़ील के संविधान का अनुच्छेद 196 स्वास्थ्य के लिए सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करता है, इस पर प्रवासी होने की स्थिति कोई प्रभाव नहीं है, और ब्राज़ील का नया प्रवासन कानून, 13.445/2017 प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा पर केंद्रित है। यह "सेवाओं, कार्यक्रमों और सामाजिक लाभों, सार्वजनिक वस्तुओं, शिक्षा, विस्तृत सार्वजनिक कानूनी सहायता, काम, आवास, बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा के लिए शरणार्थियों को समान और मुफ़्त पहुँच" की गारंटी देता है (ब्राज़ील 2017: अनुच्छेद 3 खंड XI)। इसके अतिरिक्त, ब्राज़ील ने हाल ही में प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा और सम्मान के प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धताओं पर हस्ताक्षर किए। उनमेंशरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक करार और 2030 सतत विकास लक्ष्य हैं। ब्राज़ील ने सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक करार (GCM) की समझौता वार्ताओं में सक्रिय भूमिका भी निभाई थी जिस पर देश ने हस्ताक्षर किए थे (Waltrick 2019), लेकिन राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने 2019 में सत्ता में आने के बाद इसे वापस ले लिया था.

वर्ष 2018 में, ब्राज़ील ने वेनेजुएला के प्रवासियों और शरणार्थियों का प्रबंधन करने के लिए एक विशेष प्रतक्रिया को लागू किया था: ऑपरेशन शरण (Operação Acolhida)। इस ऑपरेशन का संचालन सेना द्वारा किया गया था और इसे संयुक्त राष्ट्र और नागरिक समाज संगठनों द्वारा सहायता दी गई थी। यह मानवीय प्रकृति का पहला मिशन था जिसे सैन्य बलों द्वारा ब्राज़ील के क्षेत्र में अंजाम दिया गया था. ऑपरेशन का को तीन मोर्चों पर तैयार किया गया था: 'सीमा की व्यवस्था' – व्यवस्थित रूप से वेनेजुएला के लोगों का प्रवेश और नियमितिकरण; 'स्वागत/शरण' – आवास, भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान; और 'आंतरिकीकरण' – सीमा से ब्राज़ील के दूसरे राज्यों के लिए वेनेजुएला के लोगों को स्वैच्छिक रूप से पुनः बसाने के लिए एक कार्यक्रम (Zapata & Tapia forthcoming)। इस प्रकार से, ऑपरेशन शरण ने देश में एक मुश्किल आदर्शात्मक और वास्तविक मानवीय ढांचे के निर्माण को लागू किया है (Moulin & Magalhaes 2020).

मार्च 2020 में महामारी के प्रसार के साथ ही, सरकार ने देश में विदेशियों के प्रवेश को सीमित करने के लिए अध्यादेशों (portarias) की एक श्रृंखला को लागू कर दिया था। मार्च में, इसने देश की सीमाओं को सील कर, समुद्र, भूमि और हवा के रास्ते देश में गैर-नागरिकों के प्रवेश को निलंबित कर दिया (Governo do Brasil 2020)। हालाँकि, देश की गतिशीलता के प्रबंधन के लिए इन उपचारों द्वारा स्थापित किए गए उदाहरणों और इनके संभावित दीर्घ-कालिक परिणामों के बारे मे चिंताओं को उठाया गया है। एक तरफ, इन portarias (अध्यादेशों) ने प्रवेश को मना करना, अपने देश वापस भेजने और संक्षेप में कहें तो शरण की तलाश कर रहे और/या मानवीय सुरक्षा के ज़रूरतमंदों को वापस भेजना, और उनके लिए नागरिक, प्रशासनिक और आपराधिक आरोपों के साथ 'दोषी' का ठप्पा लगाना आसान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ, इन नए उपचारों की भाषा पुराने कानूनों की सुरक्षा-केंद्रित भावना को फिर से जीवित करती हैं जबकि इनमें ब्राज़ील की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के सम्मान के लिए कोई अपवाद नहीं शामिल हैं।

वायरस को रोकने के लिए तय किए गए अन्य उपायों के साथ, सीमाओं को बंद करने का एक विषम प्रभाव ब्राज़ील में प्रवासी आबादी पर पड़ा था, यहाँ यह बात स्पष्ट है कि उनका एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम करता है (Bengochea et al. 2021; Zapata & Prieto Rosas 2020)। इसके अतिरिक्त, राज्य ने महामारी के प्रभावों से राहत पाने में प्रवासियों और शरणार्थियों की मदद के लिए किसी भी लक्षित उपायों को नहीं अपनाया है और इनमें से कई लोगों को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं तक पहुँच पाने में समस्याओं का अनुभव हुआ है क्योंकि उनके पास आवश्यक दस्तावेज़ नहीं है (Vera Espinoza et al. forthcoming).

इसके बावजूद, महामारी के आरंभ से ही कुछ संस्थाओं ने प्रवासियों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के साथ काम किया है। उदाहरण के लिए, साउ पाउलो की नगर-पालिका सरकार ने भोजन के 200 पार्सलों, स्वच्छता के रसायनों और मास्कों का वितरण किया था (Governo do Estado de São Paulo 2020), और अमेजन क्षेत्र में शरणार्थियों की मदद के लिए नागरिक समाज ने भोजन का दान दिया था (Governo do Estado do Amazonas 2020)। ब्राज़ील द्वारा प्रस्तुत किया

गया एक अन्य सकारात्मक उपाय था प्रवासन के दस्तावेज़ों की समय-सीमा को स्वतः बढ़ाया जाना (ACNUR 2020b), यह मानकर कि संघीय पुलिस द्वारा जारी किए गए समय समाप्ति के दस्तावेज़ों को 16 मार्च, 2021 तक वैध माना जाएगा (BAL Global 2020)। हालाँकि, ब्राज़ील की मुख्य समस्याओं में से एक का संबंध अनियमित प्रवासियों से जुड़ी है, वैसे इनको कानून से सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन इनको अपने अधिकारों का उपयोग करने में प्रशासनिक बाधाओं की एक पूरी श्रृंखला का सामना करना पड़ता है और वे नागरिक समाज संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता पर निर्भर होने के लिए बाध्य हैं (Cornali 2020)। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) ने भी ब्राज़ील की रोराइमा और अन्य मुख्य स्थानों पर शरणार्थी आश्रय-स्थलों को तैयार करने में मदद की है, हाइजीन किट उपलब्ध कराए हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए स्पैनिश और अन्य आदिम भाषाओं में कोविड-19 से बचाव के अभियान चलाए हैं (Hugueney & Godinho 2020)। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संगठन (IOM) ने महामारी के दौरान ब्राज़ील में रह रहे वेनेजुएला के लोगों की सहायता और उनके पुनर्वास को जारी रखा है (OIM 2020), और उसने रोराइमा राज्य में मोबाइल हेल्थ यूनिटों को भी स्थापित किया है (EEAS 2020).

2.2 भारत

जनवरी 2020 में कोविड-19 के पहले केस के रिपोर्ट होने के एक साल बाद (Reid 2020), भारत में160,692 COVID संबंधित मौतें हो चुकी हैं (25 मार्च 2021 के आंकड़ों के अनुसार) (WHO 2021). जैसे बहुत से अध्ययनों का अनुमान था, भारत में कोविड-19 की पुष्टि वाले केसों की संख्या भारत में बहुत अधिक थी (US के ठीक बाद)।

हालाँकि, भारत में कोविड-19 के रिपोर्ट किए गए केसों में मृत्यु की संख्या अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी कम रही है (Chatterjee 2020)।

भारत के सामाजिक इतिहास में प्रवासन का बड़ा स्थान है (Tumbe 2018)। स्पष्ट तौर पर कहें, तो वर्तमान में, भारत के संदर्भ में तीन प्रकार के प्रवासन विशेष हैं: प्रमुख शहरी और निर्माण केंद्रों के लिए आंतरिक प्रवासन, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए; कुशल और अकुशल भारतीयों का दुनिया के विभिन्नों में श्रमिक प्रवासन, खास तौर पर खाड़ी (गल्फ़) देशों में; और पड़ोस के देशों से भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों और शरणार्थियों की उपस्थिति। सभी नागरिक समाज संगठन सामूहिक तौर पर पुष्टि करते हैं कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 23 मार्च, 2020 को लॉकडाउन करने की अचानक हुई घोषणा का तत्काल प्रभाव सभी तीनों समूहों पर पड़ा, जिससे 1947 के बंटवारे के बाद से उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा प्रवासन शुरू हो गया.

लम्बे समय से प्रवासी मज़दूर जो अनौपचारिकता से दूर रहते हैं, भले ही उन्हें कम मान्यता ही प्राप्त हुई है, आधुनिक भारत के पहलु की प्रमुख कुंजी रहे हैं। ILO (2019) की एक रिपोर्ट के अनुसार, "...कुल श्रमिक बल के 90% से अधिक अनौपचारिक (इस व्याख्या में वे लोग हैं जिनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है) हो, और गैर- कृषि श्रमिक बल के 85% अनौपचारिकहोने के साथ, भारत इस विषय में न्यून-मध्य आय के देशों के साथ बिल्कुल अलग है। हालाँकि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन अनौपचारिकता दशकों से इसी स्तर पर बनी हुई हैं (Mehrotra 2019)। यहाँ एक प्रमुख कारण देश में दूसरे राज्यों के श्रमिकों के लिए दस्तावेज़ीकरण की कमी है, जिसके साथ ठेकेदारों द्वारा अनौपचारिक नियुक्ति प्रक्रियाएँ जुड़ी हुई हैं, इसीलिए परिणामस्वरूप डेटा में बड़ा अंतर मौजूद है। इसके बावजूद, 2011की जनगणना के आधार पर, एक मोटा अनुमान दर्शाता है कि भारत की 1.3 अरब आबादी में से 45 करोड़ जनता, आंतरिक प्रवासी है (Statista 2020)। निसंदेह, यह ध्यान देने योग्य है कि देश की अर्थव्यवस्था का कृषि से उद्योगों की ओर रूपांतरण होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने अभी तक श्रमिक का नियामन नहीं किया है, इसीलिए ये प्रवासी अदृश्य और पहुँच से दूर रह जाते हैं (Breman 2008).

असंगठित क्षेत्रों में आंतरिक प्रवासियों का यह श्रमिक बल अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। फैक्ट्री के मज़दूर, घरेलू कर्मचारी, रिक्शा वाले और ठेले वाले देश के अल्प-कुशल श्रमिक बल के बड़े हिस्से के कुछ उदाहरण हैं। देर तक काम करने, कुछ जोखिमपूर्ण काम की स्थितियाँ और कम मज़दूरी मिलने के बावजूद भी, देश के आर्थिक विकास के लिए इस असंगठित क्षेत्र द्वारा किए गए योगदान बहुत ही अहम हैं, लेकिन साथ ही यह बुरी तरह से अ-मान्य हैं। भारत के बड़े शहरों, साथ ही देश का औद्योगिक क्षेत्र, इस श्रमिक बल पर बुरी तरह से निर्भर रहता है जो देश के ग्रामीण इलाकों से और अक्सर उन राज्यों में से निकलता है जो भारत के कम विकसित हिस्सों में हैं। लॉकडाउन ने प्रवासी मज़दूर के बीच संकट की ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर दिया जो लंबे समय से चली आ रही ढांचागत असमानताओं के सामने और जो महामारी से पहले से ही मौजूद थीं.

खाड़ी (गल्फ़) देशों में काम करने वाले भारतीय मज़दूर भारत से प्रवास करने वालों का एक बड़ा हिस्सा हैं। उनमें से ज़्यादातर अर्द्ध-कुशल या अकुशल है और, उनकी संख्या करीब 85 लाख है (Pethiyagoda 2017)। महामारी द्वारा पेश की गई चुनौतियाँ खाड़ी (गल्फ़) के राज्यों के कानूनों के चलते और गंभीर हो गईं जिसमें उनकी वापसी पर प्रतिबंध लग गया, जबकि नियोक्ता ने उनको नौकरी से निकाल दिया। हो सकता है ये मज़दूर पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहे हों, लेकिन उनके द्वारा भेजे गए पैसों ने भारत में उनके घरेलू इलाकों में हो रहे विकास में बड़ा योगदान दिया है (Sahoo 2015). महामारी ने तार्किक रूप से उनके और उनके परिवारों के नज़रिए को बदल दिया है। खाड़ी (गल्फ़) देशों में मौजूद भारतीय प्रवासियों ने अपने देश वापस आने के लिए अतिरिक्त चुनौतियों का सामना किया है.

23 मार्च, 2020 को, भारत देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा करने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया (BBC News 2020)। सरकार के द्वारा अपनाए गए नियंत्रण के उपाय गतिशीलता की मानवीय प्रकृति

 के आधार पर अनापेक्षित थे, घरेलू परिवहन मार्गों को बंद करना (जिसमें लंबी दूरी की ट्रेनें शामिल थे) और राज्य व राष्ट्र की सीमाओं को बंद करना (भारतीय प्रेस सूचना ब्यूरो 2020). इसके अतिरिक्त, जन स्वास्थ्य की आपात स्थितियों से विशिष्ट रूप से निपटने के लिए किसी कानून की अनुपस्थिति में केंद्र की सरकार,और उसके बाद राज्य सरकारों ने औपनिवेशिक काल के महामारी रोग अधिनियम (1897) को लागू कर दिया (Goyal, 2020).

ठप्प पड़ जाने से शहरों, जैसे कि नई दिल्ली, बेंगलुरू और मुंबई में मौजूद हजारों श्रमिकों को रातों-रात बेरोजगार और निराश्रित बना दिया.

उदाहरण के लिए, राज्य की ढांचागत परियोजनाओं पर काम करने के लिए अनुबंधित किए गए मज़दूर, उन निजी ठेकेदार कंपनियों द्वारा, जिन्होंने उनको काम के लिए रखा था, अपना प्रबंध ख़ुद करने के लिए बेसहारा छोड़ दिया गया (Maraa कलेक्टिव 2020)। कई श्रमिकों के पास शहरों में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कोई साधन नहीं थे। चूँकि अंतरराज्यीय बसों और लंबी दूरी की ट्रेनों को अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिससे बहुतों को पैदल चलकर वापस घर जाना पड़ा (Khadria 2020)। हज़ारों किलोमीटर का यह विशाल पलायन गर्मियों की चिलचिलाती धूप के बीच हुआ था (Nair, 2020)। कठोर लॉकडाउन उपायों को कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ और गहन कर दिया गया जो बार-बार उन लोगों को शारीरिक दंड (BBC

News 2020b) देते रहे जिन्होंने क्वारंटाइन के नियमों को तोड़ा, साथ ही घर लौट रहे निचले वर्ग के श्रमिकों को बार-बार लक्षित किया गया (Ganguly 2020)। कानून प्रवर्तनअधिकारियों के पास क्वारंटाइन के उपायों को लेकर स्पष्ट और प्रभावी संवाद नहीं था, जिसके चलते अक्सरवे इस बात का अंतर नहीं कर सके कि किसने गैर-जिम्मेदारी के साथ कानून को तोड़ा और किसके पास इसके अलावा कोई और विकल्प ही नहीं था (Kikon 2020).

।आसाम में, जो देश का एक उत्तर पूर्वी राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, वहाँ लॉकडाउन से कुछ ही सप्ताह पहले उग्र विरोध के बीच, एक विवादास्पद कानून सामने आया, जो शरणार्थियों को धर्म के आधार पर नागरिकता दे रहा हों (Sharma 2020)। जबकि लॉकडाउन ने विरोध प्रदर्शनों को कम किया, आसाम वापस लौट रहे प्रवासी श्रमिकों (Leivon et al. 2020) और पड़ोसी राज्यों में प्रवासन की विपरीत होती प्रवृत्ति ने कोविड-19 के केसों में एक बढ़ोत्तरी दर्ज़ की थी। कुछ राज्यों जैसे नागालैंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य का ढांचा और जाँच की सुविधाएँ बहुत बुरी तरह से अविकसित थी जिसकी वजह से विश्लेषण के लिए नमूनों को पड़ोसी राज्य आसाम की प्रयोगशालाओं में भेजना पड़ता था। अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (PPE) की गंभीर कमी का भी सामना करना पड़ा था। इसी दौरान, बड़े शहरों में काम करने वाले उत्तर-पूर्व भारत के प्रवासी श्रमिकों को नस्लीय धमकियों और उनकी अलग शारीरिक पहचान के चलते शोषण का शिकार बनाया गया था (Haokip 2021)। उत्तर-पूर्व के श्रमिकों के साथ ही साथ बिहार और ओड़िशा जैसे राज्यों को वापस लौट रह श्रमिक (Kikon 2020), जो शहर में अपना गुजारा नहीं कर सकते थे, उन्होंने घर वापसी में कठिन चुनौतियों का सामना किया (Salle 2020)। भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रवासियों की असामान्य रूप से बड़ी संख्या है और यह दुनिया के कई जगहों में फ़ैले हुए हैं. साथ ही बहुत से लोग वर्किंग परमिट पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों में रह रहे हैं, जो लॉकडाउन के चलते फंस गए हैं (Sitlhou 2020).

वंदे भारत मिशन' (भारत सरकार 2020) के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निकालने और घर वापस लाने का पहला चरण मई 2020 में शुरू हुआ था, यानी देश स्तरीय लॉकडाउन के करीब दो महीने के बाद। UAE में रह रहे कई उत्तर-पूर्व के प्रवासी श्रमिकों के लिए, यह विकल्प उपयोगी नहीं था, क्योंकि अधिक फ्लाइटें दक्षिण भारत के राज्यों से जुड़ी थीं। कई प्रवासी श्रमिकों की नौकरियाँ छूट गईं साथ ही उनके वीज़ा निरस्त कर दिए गए, इस प्रकार उन पर भारी जुर्माना देय हो गया और बिना वैध कागज़ातों के वहाँ रूकने के चलते वे संभावित कैद के भी दोषी हो गए (Karasapan 2020).

महामारी के चलते जिन श्रमिकों की मौत हो गई थी या जिन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ा उनका कोई भी आधिकारिक रेकॉर्ड नहीं रखा गया था (The wire, 2020), लेकिन एक अनुमान है कि कुल 1 करोड़ आंतरिक प्रवासी श्रमिक अपने गृह राज्यों को लौटे, जिसमें 32 लाख उत्तर प्रदेश और 15 लाख बिहार वापस पहुँचे (Rao et al. 2020), साथ ही एक अनुमान है अप्रैल 2020 तक 12.2 करोड़ भारतीय बेरोजगार हुए थे (Inamdar, 2020)। नागरिक समाज संगठनों ने शहरों में फंसे प्रवासी श्रमिकों की जीवन यापन और कार्य करने की स्थितियों पर आवश्यक जानकारी को एकत्र और रेकॉर्ड करके डेटा के अंतर को पूरा किया। स्वतंत्र रिपोर्टों ने पुष्टि की कि प्रवासी श्रमिकों की एक बड़ी संख्या अनौपचारिक मज़दूरों की थी और उन्होंने बिना किसी लिखित अनुबंध के काम किया था (Patel 2020).

यह स्पष्ट है कि लॉकडाउन ने प्रवासियों की सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दुर्बलताओं को बढ़ाया और उनमें से कई को निराश्रित छोड़ दिया: बेरोजगार और मज़दूरी तक पहुँच के बिना (Rajan et al. 2020)। संकट के प्रारंभ से ही, नागरिक समाज के कार्य का एक महत्वपूर्ण भाग सहायता का वितरण करना और प्रवासी-प्रमुखता वाले समूहों के साथ ही साथ अन्य मानवीय संगठनों, धार्मिक समूहों, और संबंधित सरकारी विभागों के साथ समन्वय करना था (Youngs 2020)। नागरिक समाज के संगठनों को अनगिनत चुनौतियों को निपटाना पड़ा था, जैसे कि बहुत ही कम समय के भीतर उनकी सहायता कार्यक्रमों के लिए फ़ंड या दान का इंतज़ाम करना और राहत कार्यकर्ताओं की सहायता के वितरण के लिए अनुमति प्राप्त करना। निजी स्रोतों से दान और स्वैच्छिक सहायता जरूरी हो गई थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के डॉक्टरों का एक नया नेटवर्क स्थापित किया गया जिसने फंड और अनाज का दान दिया, इनके साथ ही साथ रिक्शा ड्राइवर भी थे जिन्होंने राहत कार्यकर्ताओं को निशुल्क यात्रा की व्यवस्था दी। ऐसे उत्कृष्ट गठबंधन का इस्तेमाल कभी-कभी बहुउद्देशीय विकास एजेंसियों (Ramachandran 2020) द्वारा पूरे सामाजिक-आर्थिक स्पेक्ट्रम में खाद्य राशनों के वितरण से लेकर बैंकों और डाकखानों के ज़रिए मिलने वाली वित्तीय सहायता पाने में निराश्रितों मदद, घर वापस लौटन वाले श्रमिकों की सरकारी अधिकारियों की सहायता से यात्रा और परिवहन की व्यवस्था करने की व्यापक सहायता में किया गया था।

3. कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट का आधार 52 अर्द्ध-संरचित गुणात्मक साक्षात्कार हैं जिन्हें ब्राज़ील (25 साक्षात्कार) और भारत (27 साक्षात्कार) में प्रवासियों और शरणार्थियों के साथ काम कर रहे नागरिक समाज संगठनों (CSOs) के साथ फरवरी और मार्च 2021 में संचालित किया गया था।.

हमने दोनों देशों में नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के तीन मुख्य समूहों को शामिल किया था, जिसका आधार उद्देश्यगत नमूना प्राप्त करना था: 1) गैर-सरकारी संगठन (NGOs); 2) पंथ-आधारित संगठन और 3) प्रवासी-प्रमुखता वाले संगठन.

नमूना प्राप्त करने के लिए, हमने देशों को उनके क्षेत्रीय भौगोलिक-राजनैतिक खंडों में बांटा और उसके बाद प्रत्येक देश में प्रवासियों और शरणार्थियों के साथ संपूर्ण देश में काम कर रहे सभी नागरिक समाज संगठनों की पहचान की (देखें परिशिष्ट 1)। हमारा लक्ष्य प्रत्येक क्षेत्र में हर समूह का साक्षात्कार करने के लिए संगठनों की संख्या के बीच संतुलन बनाए रखना था, भले ही कुछ विशेष क्षेत्रों में कुछ संगठनों की केंद्रीयता के चलते बाधाएँ लागू थीं। हालाँकि, भारत में नमूने इस तथ्य के कारण सीमित थे कि देश के उत्तर-पूर्व में स्थित संस्थाओं ने इस अध्ययन में भागीदारी ना करने का विकल्प चुना था।

हमने दोनों देशों मे डेटा एकत्र करने के लिए एक समान व्यवस्था अपनाई थी। साक्षात्कार का लक्ष्य समझना

था: i) कोविड-19 महामारी के प्रसार के बाद से ब्राज़ील और भारत में प्रवासियों के सामने आई चुनौतियाँ; ii) नागरिक समाज संगठनों के द्वारा उनको उपलब्ध सहायता; iii) अच्छे कार्य और शेष अंतर; iv) नई साझेदारियाँ जो महामारी के दौरान उभर कर सामने आईं और v) सरकारें कैसे अपने कार्य को सहारा देने के लिए तीसरे सेक्टर के साथ शामिल हो सकती हैं (देखें परिशिष्ट 2).

सभी साक्षात्कार ऑनलाइन या फ़ोन पर किए गए थे। साक्षात्कार के डेटा को एक समान व्यवस्था के जरिए विश्लेषित और सुव्यवस्थित किया गया था। हमारे स्रोतों की गोपनीयता की सुरक्षा करने के लिए, साक्षात्कार की सामग्री को अनाम रखा गया है, हालाँकि हमने संगठनों के प्रकार और भौगोलिक स्थानों को स्पष्ट किया है, क्योंकि यह जानकारी दोनों देशों में कार्यकर्ताओं के अलग-अलग मुद्दों और नज़रियों को समझने से जुड़ी है।

इस शोध को Ethics Committees of Queen Mary University of London (QMERC20.154) और the Federal University of Minas Gerais (CAAE: 44923521.5.0000.5149) से स्वीकृति प्राप्त हुई है।

4. ब्राज़ील और भारत में नागरिक समाज और अप्रवासन

4.1 ब्राज़ील में नागरिक समाज का एक संक्षिप्त इतिहास

हालाँकि विद्वानों और कार्यकर्ताओं ने इसके वास्तविक भागीदारी के चरित्र पर सवाल उठाएँ, ब्राज़ील केराजनैतिक सिद्धांतों का समुच्चय, नागरिक संविधान (Constituição Cidadã), 1988 में लागू हुआ था।

दो दशकों से अधिक समय तक चली सैनिक तानाशाही जिसके चरित्र की पहचान सामाजिक आंदोलनों और राजनैतिक विरोध को बलपूर्व दमन से जुड़ी थी, लोग सक्रिय और औपचारिक रूप से लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण में योगदान दे सकते थे। इसके बाद से हुए दो समानांतर विकास ब्राज़ील के नागरिक समाज की भूमिका को समझने के लिए प्रमुख हैं। सबसे पहले, नए संविधान का निर्माण आंशिक तौर पर प्रसिद्ध संशोधनों के जरिए हुआ था, जिसने समाज के विभिन्न वर्गों को नए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, और नगरपालिका विधायिका के निर्माण में सहारा देने की अनुमति दी थी। दूसरा, संविधान ने एक प्रणाली की श्रृंखला स्थापित की जिसके जरिए नागरिक समाज सार्वजनिक प्रबंधन में सीधे तौर पर भागीदारी कर सकता था (Rocha 2008)। लोकप्रिय परिषदों के गठन के जरिए, आज लोक प्रशासन के अधिकांश क्षेत्रों में सामाजिक भागीदारी के लिए संस्थागत स्थान मौजूद हैं (Avritzer 2007; Rocha 2008)। जैसा हम आगे चर्चा करेंगे, ब्राज़ील में प्रवासियों और शरणार्थियों को स्वीकारना और उनका समावेशन इस पैटर्न के लिए कोई अपवाद नहीं है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ब्राज़ील में लोकप्रिय राजनैतिक भागीदारी केवल 1988 के बाद संभव हो पाई थी, ना ही यह कि पुनः-लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में नागरिक समाज की सक्रिय भूमिका बिना किसी संघर्ष के उभरी। 1960 के दशक के अंत से लेकर 1980 के दशक तक, सैन्य तानाशाही द्वारा किए गए हद से अधिक अत्याचारों के कारण देश में अनगिनत सामाजिक आंदोलन उभरे, जिसे भूमिहीन श्रमिकों का आंदोलन (MST), राष्ट्रीय छात्र संगठन (UNE), नेशनल ट्रेड यूनियन सेंटर (CUT), और बहुत से संगठन कैथोलिक चर्च के प्रगतिशील धड़े के साथ जुड़े थे, जिसे मुक्ति का धर्मशास्त्र कहा गया था (Rocha 2008)। इसी दौरान 1966 में यह भी हुआ था, जब कैथोलिक संगठन Cáritas Arquidiocesana, अपने अंतर्राष्ट्रीय भ्रात संगठन से स्वतंत्र हो गया और इसने ब्राज़ील के विभिन्न शहरों में अपनी मौजूदगी के आधार पर स्वयं को एक स्वायत राष्ट्रीय संस्था के तौर पर स्थापित किया।

1970 के दशक के अंत तक, चिली और उरूग्वे में सैनिक तानाशाही द्वारा नरसंहारों की तीव्रता के मध्य में, राजनैतिक तौर पर निर्वासित लोग ब्राज़ील, खास तौर पर रियो डी जेनेरियो की ओर आने लगे। चाहें स्वायत्त रूप से या लैटिन अमेरिका में कैथोलिक संस्थानों के एक नेटवर्क के जरिए, इन समूहों ने सुरक्षा के लिए रियो डी जेनेरियो में Cáritas के कार्यालय से संपर्क किया। इस प्रकार से, संगठन, धीरे-धीरे उन लोगों के लिए आश्रयस्थल बनता गया जो इस क्षेत्र में राजनैतिक उत्पीड़न से बच गए थे, भले ही इसका मतलब था ब्राज़ील की सैन्य सत्ता से दुश्मनी मोल लेना। इन नई मांगों के दबाव में, ब्राज़ील में बिशपों के राष्ट्रीय संघ (CNBB) के समर्थन के साथ, Cáritas ने देश में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) के एक प्रतिनिधित्व को लाने के लिए एक आंदोलन की शुरूआत कर दी (Campanholo 2019)। जैसा विद्वानों के उचित तर्क दिया हैं, निश्चित तौर पर उस समय राज्य की अनुपस्थिति थी, लैटिन अमेरिकी राजनैतिक निर्वासितों के साथ के अतिरिक्त काम को ब्राज़ील के नागरिक समाज संगठनों द्वारा पहले ही संभाल लिया गया था, जिसने गैर सरकारी संगठनों और रियो डी जेनेरियो में 1977 में नए खुले UNHCR के कार्यालय के बीच मज़बूत रिश्ते बना दिए थे (Fischel & Marcolini 2002; Jatobá & Martuscelli 2018; Moreira 2010)। असल में, यह कहा जा सकता है कि ब्राज़ील में UN एजेंसी की स्थापना बड़े पैमाने पर गैर-सरकारी संगठनों के कार्य के जरिए हुई थी।

इस प्रकार, 1970 के दशक से ही, ब्राज़ील का नागरिक समाज कम से कम तीन मोर्चों पर देश में प्रवासी और शरणार्थी आबादी के अधिकारों की रक्षा में शामिल रहा है: राष्ट्रीय प्रवासन/गतिशीलता की व्यवस्था के आधुनिकीकरण के परामर्श के जरिए; प्रवासियों और शरणार्थियों के स्वागत और पुनर्वास का सीधे समर्थन करके; और स्थानीय समावेशन की प्रक्रिया में सहायता द्वारा, चाहें स्वायत्त रूप से, या सरकार और UNHCR के साथ साझेदारी में।

ब्राज़ील में, वर्तमान नियामक फ्रेमवर्क जो नागरिक समाज संगठनों और राज्य के बीच साझेदारी को निर्देशित कर रहा है उसे 2014 में लागू किया गया था (Law 13.019)। इस कानून ने सार्वजनिक और तीसरे सेक्टर के बीच भागीदारी के नियमों को अधिक स्पष्टता के साथ स्थापित किया - साथ ही इसका मुख्य ध्यान सार्वजनिक खर्चों का पारदर्शिता था, और इसने, दूसरे क्षेत्रों के बीच, विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि सांस्कृतिक और कलात्मक गतिविधियों, खेलों, और बच्चों और किशोरों में काम कर रहे नागरिक समाज संगठनों को फाइनेंस के लिए निजी कंपनियों के लिए कर प्राप्तियों का भी निर्माण किया था (Pannunzio 2013)। भारत के विपरीत, ब्राज़ील के कानून अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग का नियामन नहीं करते हैं (खंड 4.2 देखें)

शरणार्थी अधिकार-आधारित कानून के लिए नागरिक समाज का समर्थन

राज़ील के सबसे नवीनतम ऐतिहासिक काल के दौरान, यानी 1980 से लेकर 2017 तक, वह कानून जिसने देश में गतिशीलता का नियामन किया था वह बड़े पैमाने पर सुरक्षा की प्राथमिकता के पहलू पर डिज़ाइन किया गया था। तानाशाही के दौरान निर्मित हुआ था, इसमें विदेशी नागरिक की स्थिति विदेश से विद्रोह के प्रभाव पर सेना के डर से जुड़ी हुई थी, खास तौर पर उनके लिए जिनकी जड़ें पड़ोस के लैटिन अमेरिकी देशों में थी (Machado 2020; Milesi & de Andrade 2017; Moreira 2010)। 1970 और 1980 के दशक वे दौर थे जिसमें ब्राज़ील में तुलनात्मक रूप से कम प्रवासन हुआ था हालाँकि यह दौर इस दौर को ब्राज़ील से बाहर प्रवास के लिए चिन्हित किया गया था, खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स की ओर (Acosta 2018; Zapata & Fazito 2018; Margolis 2013)। इस सीमित प्रवासन नीति के आगे, देश में किसी भी तरह का कोई राष्ट्रीय शरणार्थी सुरक्षा फ्रेमवर्क नहीं था, और इस दौरान यहाँ आए राजनैतिक निर्वासितों के पास थोड़ी सी ही कानूनी सुरक्षा थी।

जल्दी ही इस नए स्थापित हुए गणतंत्र में, नागरिक समाज संगठनों ने 1951 के शरणार्थी समझौते और इसके नियम को लागू करने और इसमें से भौगोलिक धाराओं के हटाने के लिए गतिशील होना आरंभ कर दिया – हालाँकि ब्राज़ील ने, 1960 और 1967 में, समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, ये समझौते केवल उन लोगों को विशेष सुरक्षा देते थे जो यूरोप से आए थे (Jatobá & Martuscelli 2018; Milesi & de Andrade 2017)। वर्ष 1996 तक, नागरिक समाज ने उस विधेयक की प्रस्तावना के लिए अपनी एक सक्रिय भूमिका मानकर प्रबंध कर लिया था जो आगे चलकर राष्ट्रीय शरणार्थी अधिनियम बना। उस ओर जिन रणनीतियों को अपनाया गया उनमें शामिल था न्याय मंत्रालय को खुली चिट्ठियाँ लिखना; जन सुनवाईयों में तीव्र भागीदारी करना; और राष्ट्रीय संसद में विधायी प्रक्रियाओं की नज़दीक से निगरानी करना (Milesi & de Andrade 2017)। इसे क्षेत्रीय सेमीनारों और बैठकों के जरिए लैटिन अमेरिका में अन्य संगठनों के साथ बातचीत का भी सहारा था, यह खास दौर में हुआ था जिसका मुख्य परिचय पूरे महाद्वीप में कोलंबिया के लोगों का पुनर्वास था।

उस प्रभाव के लक्षण 1997 में स्वीकृत कानून पर अनगिनत रूप से थे और इसने सुरक्षा फ्रेमवर्क की एक विशेषता को समझाने में मदद की, जिसे अक्सर ही क्षेत्र में सबसे प्रगतिशील में से एक माना गया (Jatobá & Martuscelli 2018; Jubilut 2006)। सबसे महत्वपूर्ण रूप से, 1997 के शरणार्थी अधिनियम ने शरणार्थियों के लिए राष्ट्रीय समिति (CONARE) का निर्माण किया था, जो एक त्रिकोणीय संस्था थी जिसकी जिम्मेदारी शरणार्थी-स्थिति को निश्चित करना और शरणार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए काम करना था (Jatobá & Martuscelli 2018; Moreira 2010)। यह संस्थान कई मंत्रालयों, संघीय पुलिस विभाग के प्रतिनिधित्व, और किसी नागरिक समाज संगठन के एक प्रतिनिधि (दो राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन इस पीठ में बारी-बारी से बैठते हैं) को मिलाकर बना था। जैसा Jubilut और Apolinário (2008) ने रेखांकित किया, यह डिज़ाइन, बहुधा किसी और देश में नहीं दिखता है, जो एक मानवाधिकार- आधारित दृष्टिकोण के साथ राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति चिंता को संतुलित करता है.

प्रवासी अधिकारों पर आधारिक कानून और मानवता के आधार पर वीज़ा के लिए नागरिक समाज का समर्थन

समय के साथ ही गतिशीलता के मामलों में नागरिक समाज के कार्य का दायरा बढ़ गया था, इसकी प्रकार इसकी भौगोलिक पहुँच बढ़ी थी। वर्ष 2004 में, Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH) ने प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए एकता नेटवर्क (RedeMir) के निर्माण का प्रस्ताव किया था, जो नागरिक समाज संगठनों के बीच कार्यवाहियों के समर्थन, एक साथ आना, और समन्वय के लिए मुख्य राष्ट्रीय पटलों में से एक बन गया (Milesi et al. 2018)। सदी 2000 की शुरूआत की विशेषता आंतर-क्षेत्रीय प्रवासन की थी, 2010 ने ब्राज़ील की उत्तरी सीमा से हैती के नागरिकों का बड़ी संख्या में तेजी से आगमन देखा, इसका कारण वह भूकंप था जिसने पहले से ही खस्ताहाल देश में बुरी स्थिति पैदा कर दी थी। फिर भी, मर्कोसुर और अन्य दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों के विपरीत, इस समूह का ब्राज़ील में प्रवेश और निवास करने का कोई पसंदीदा मार्ग नहीं था, ना ही वे शरणार्थियों की क्लासिकल परिभाषा के अनुरूप थे। एक तरह से क्योंकि उन्होंने उस देश के उस हिस्से से प्रवेश किया था जहाँ ऐतिहासिक रूप से राज्य की मौजूदगी नहीं थी, इसलिए हैती के लोगों को लोक अधिकारियों की ओर से बहुत ही कम सहायता प्राप्त हुई थी। इसके स्थान पर, एकर और अमेजन के राज्यों में कैथोलिक संगठन वह पहली संस्थाएँ थीं जिन्होंने स्वागत के ढांचे का निर्माण किया था (Mamed 2016; da Silva 2013).

मुख्य तौर पर RedeMir के जरिए, इन गैर सरकारी संगठनों को दूसरे संगठनों का समर्थन हासिल हुआ और राज्य की गैर मौजूदगी के विरूद्ध बोल पाए। एक साथ आने के साथ ही, CONARE में, बतौर वोटिंग सदस्य, और इसी प्रकार राष्ट्रीय प्रवासन परिषद (Conselho Nacional de Imigração - CNIg) 1 , में बतौर पर्यवेक्षक सदस्य नागरिक समाज की उपस्थिति 2012 में हैती के नागरिकों के लिए मानवता के आधार पर वीज़ा की स्वीकृति दिलाने के लिए बहुत मत्वपूर्ण थी, जिससे उनको पांच वर्षों तक ब्राज़ील में रहने और काम करने की अनुमति मिल रही थी (de Oliveira & Sampaio 2020; Fernandes & de Faria 2017).

ये उन्नत व्यवस्थाएँ, जिन्होंने क्रूर विदेशी स्थिति के लागू रहने के बावजूद अपना काम किया था, उन्होंने,दशकों के राजनैतिक संघर्ष के बाद, 2017 के प्रवासन कानून के डिज़ाइन और स्वीकृति को स्पष्ट कर दियाथा। नए कानून के ठोस आधारों में विभिन्न विमर्श फोरम शामिल थे, जो पिछले दस वर्षों में आयोजित किए गए थे, जो स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर सामाजिक आंदोलनों और नागरिक समाजसंगठनों को एक साथ लेकर आए। इस बात को ध्यान में रखते हुए, प्रवासन और शरण पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन (Comigrar) विशेष ध्यान का अधिकार रखता है। बतौर राष्ट्रीय गतिशीलता योजना पर सामूहिक भावना के प्रदर्शन के लिए बनाई गई इस व्यवस्था ने 2014 में चली बैठकों की श्रृंखला के जरिए सामाजिक आंदोलनों और गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे 800 से अधिक लोगों को जुटाया, जिसमें प्रवासी-प्रमुख संगठन शामिल थे। Comigrar द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों को प्रभावी रूप से 2017 के प्रवासन कानून के प्रारूप में शामिल किया गया था। जैसा de Oliveira और Sampaio (2020)

गया था। जैसा de Oliveira और Sampaio (2020) ने हाल ही में महसूस किया था, यह जन सुनवाईयों और अनौपचारिक रूप से नागरिक समाज में और कांग्रेस में बिल की डिज़ाइन के लिए ज़िम्मेदार विशेषज्ञों के आयोग में सक्रिय कार्यकर्ताओं के जरिए हुआ था। ब्राज़ील की संसद में प्रस्तावित विधेयक की चर्चा के दौरान, इस स्वीकृत कराए जाने के लिए जोर देते हुए, कई गैर सरकारी संगठनों ने प्रवासियों के अधिकारों के बारे में, और मानवीय गतिशीलता के आम भ्रांतियों को दूर करने के बारे में जन जागरूकता अभियानों की व्यवस्था की थी (de Oliveira & Sampaio 2020).

शरणार्थी अधिनियम के समान ही, 2017 के प्रवासन कानून ने भी बहुत सारी उन्नतियाँ उत्पन्न की थीं। सबसे महत्वपूर्ण, इसने प्रवासी (विदेशी नहीं) को एक मानवाधिकार का विषय माना था, इस प्रकार से इसने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विधायिका के पुराने विशेष ध्यान को हटा दिया था (de Oliveira & Sampaio 2020; Jarochinski et al. 2020; Zapata & Fazito 2018)। इसके बावजूद, नए कानून की स्वीकृति ब्राज़ील में एक नए राजनैतिक परिदृश्य का परिणाम था, जिसमें रूढिवादी पक्षधरिता वाले सत्ता

[1]CNIg को 1980 में संघीय कानून 6.815 के जरिए बनाया गया था। यह चार मुख्य क्षेत्रों के लिए ज़िम्मेदार था: प्रवासन नीतियों के लिए सूत्र बनाना; मज़दूर के प्रवास की गतिविधियों के समन्वयन के लिए; कुशल मज़दूर के लिए राष्ट्रीय मांग का मूल्यांकन; और मज़दूर के प्रवासन के लिए संबंधित अध्ययनों का बढ़ावा देने के लिए। यह सरकार, उद्योग संगठनों, ट्रेड यूनियनों, और नागरिक समाज के विभिन्न स्वरूपों के प्रतिनिधित्व से मिल कर बना था। और स्वीकार्यता में बढ़त पाते जा रहे थे (Acosta et al. 2018)। इस बदल रहे हालात न केवल विधायिका को स्वीकार करने के लिए प्रेसिडेंशियल वीटो की संख्या में दिख रहा था, बल्कि उस जीत में भी था जिसने विधेयक को नियमित किया था। इसने महत्वपूर्ण रूप से राज्य के सुरक्षा बलों को अधिक शक्तियाँ दीं - जैसे कि संघीय पुलिस - जैसा मूल रूप से कल्पना की गई थी। इसीलिए तर्क दिए गए थे कि यह परिणाम स्वयं कानून की भावना का सम्मान नहीं करता है और देश के संविधान का उल्लंघन करता है (de Oliveira & Sampaio 2020; Machado 2020).

इन विमर्शों के दौरान पूरे लैटिन अमेरिकी से वेनेज़ुएला के लोगों का विशाल आरंभ हो गया था, जो उस देश में 2016 के अंत में मानवीय संकट की स्थिति के गंभीर होते जाने का परिणाम था। ब्राज़ील के भीतर बढ़ रही सुरक्षा के संदर्भ में, 2016 में वेनेज़ुएला के नागरिकों को उनके देश वापस भेजे जाने के विरूद्ध आवाज़ उठाने में, और 2018 में उत्तरी सीमावर्ती राज्य रोराइमा की सीमा बंद करने के विरोध में गैर सरकारी संगठन सबसे प्रमुख थे (Alvim 2018; Milesi et al. 2018)। इसके अतिरिक्त, इन संगठनों ने नए कानून, और ब्राज़ील के संविधान की सही व्याख्या बताते हुए सक्रिय रूप से प्रशासनिक संस्थाओं पर दबाव बनाया, जो देश में रहने वाले नागरिकों और अप्रवासियों के बीच समानता की गारंटी देता है। इसे सार्वजनिक नागरिक कार्यवाहियों के दावों के जरिए, लोक रक्षा के कार्यालय (DPU) के साथ नज़दीकी गठबंधन में किया गया है। इन अनगिनत कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप, प्रवासी और शरणार्थी आबादियों को कई सामाजिक सुरक्षा के लाभ तक पहुँच प्राप्त हुई है जैसे कि वेनेज़ुएला के लोगों के लिए मर्कोसुर निवासी शुल्क छूट; सतत नकद लाभ कार्यक्रम (BPC), जो दुर्बल-आय वर्ग के परिवारों के लिए न्यूनतम मज़दूरी की गारंटी देता है; और, अभी हाल ही में, कोविड-19 आपातकालीन वित्तीय भत्ता (Milesi & Coury 2018; Zortea 2017; Bengochea et al. 2020).

[1]CNIg को 1980 में संघीय कानून 6.815 के जरिए बनाया गया था। यह चार मुख्य क्षेत्रों के लिए ज़िम्मेदार था: प्रवासन नीतियों के लिए सूत्र बनाना; मज़दूर के प्रवास की गतिविधियों के समन्वयन के लिए; कुशल मज़दूर के लिए राष्ट्रीय मांग का मूल्यांकन; और मज़दूर के प्रवासन के लिए संबंधित अध्ययनों का बढ़ावा देने के लिए। यह सरकार, उद्योग संगठनों, ट्रेड यूनियनों,और नागरिक समाज के विभिन्न स्वरूपों के प्रतिनिधित्व से मिल कर बना था।

प्रवासियों और शरणार्थियों का स्वागत, अनुकूलन और समावेशन

तिशीलता और शरण पर इसके उन्नत कानून के बावजूद, यह आम धारणा है कि ब्राज़ील राज्य के पास प्रवासन और शरणार्थियों के प्रति अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के सम्मान के लिए सीमित क्षमता और राजनैतिक इच्छाशक्ति है (Zapata & Tapia forthcoming; Jatobá & Martuscelli 2018)। परिणाम के तौर पर, जब इस आबादी के स्वागत, पुनर्वास, और समावेशन की बात आती है, तो उसके लिए देश ने ऐतिहासिक रूप से राज्य, UNHCR, गैर सरकारी संगठन, और अभी हाल ही में, IOM के बीच ज़िम्मेदारियों के साझा करने का मॉडल स्वीकार किया था। हालाँकि इस पैटर्न का मूल 1970 के दशक से जुड़ा है, जो निश्चित तौर पर पिछले दशक में उन्नत हुआ है।

जब हैती के लोग 2010 में एकर और अमेजन में आना शुरू किए थे, तो उनको आश्रय और भोजन उपलब्ध कराने में नागरिक समाज संगठन सबसे प्रथम थे। हालाँकि बाद में एकर राज्य ने सहायता के लिए ज़िम्मेदारी ली थी, आने वाले सालों में (Mamed 2016) प्रवासियों को आवास और मूलभूत ज़रूरतों को मुहैया कराने के लिए अमेजन में गैर सरकारी संगठनों ने बतौर प्राथमिक कर्ता अपना काम जारी रखा था। ब्राज़ील की उत्तरी सीमा से वेनेजुएला के लोगों के लगातार आवागमन के बाद कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति रोराइमा राज्य में दिखी थी। हालाँकि 2018 में बोआ विस्ता और पैकाराइमा शहरों में ऑपरेशन शरण ने कई आश्रय स्थापित किए, जिसमें से कई का प्रबंध अभी गैर सरकारी संगठन कर रहे हैं (Jarochinski et al. 2020)। इसी तरह से, अनुकूलन कार्यक्रम, जो एक आंतरिक पुनर्वास या पुनर्स्थापना के कार्यक्रमों को प्रदर्शित करता है, वह मुख्यः तौर पर गैर सरकारी संगठनों के जरिए संचालित किया जाता है, जो आम तौर पर पुनर्स्थापित हुए परिवारों को आरंभिक आश्रय, भोजन, और यहाँ तक कि सीधे नकद स्थानांतरण देने के लिए ज़िम्मेदार है (Baeninger 2018; Rosita Milesi & Coury 2018).

यह साझी-ज़िम्मेदारी वाला मॉडल प्रवासी और शरणार्थी समावेशन की दुनिया में भी प्रदर्शित किया जाताहै। या तो स्वायत्त तौर पर या UNHCR के रूप में क्रियान्वयन साझीदारों के रूप में, गैर-सरकारी संगठनों ने प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेश की है (Jatobá & Martuscelli 2018; Jubilut 2006)। इसमें शामिल है, लेकिन सीमित नहीं, पुर्तगाल का उदाहरण; रोजगार प्राप्त करने में मार्गदर्शन; दस्तावेज़ीकरण और कानूनी सहायता; और यहाँ तक कि चिकित्सा परामर्शों में भाषा संबंधी सहायता सेवाओं के प्रावधान (Milesi & Coury 2018; Zortea 2017). हालाँकि ऐसी गतिविधियों के महत्व को अनदेखा नहीं किया जाता है, यह भी याद रखना चाहिए कि नागरिक समाज संगठनों के लिए पारंपरिक राज्य व्यवस्थाओं के प्रतिनिधिमंडल, चाहें वह स्वागत के लिए हों या समावेशन के लिए, समस्या वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, इससे सेवाओं को उपलब्ध कराने में मुख्य असमानताएँ आती हैं, ऐसा मुख्यतः इसलिए है क्योंकि विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के पास पुनर्वास कर रही आबादी को आवश्यक सहारा देने के लिए अलग-अलग क्षमताएँ होती हैं। Moulin (2012) और Vera Espinoza (2018) ने यह भी नोट किया था कि ब्राज़ील में समावेशन – और लैटिन अमेरिकी के अन्य देशों में – अक्सर "पात्रता" के एक घातक तर्क के जरिए अपना स्वरूप लेता है, जिसके द्वारा जिन्होंने अतिरिक्त सहायता की मांग की, या असंतुष्टि दिखाई, उनको अधिकारी के तौर पर नहीं, बल्कि मुख्य तौर कृतघ्न माना जाता है.

फिर भी, ऐतिहासिक रूप से प्रवासी और शरणार्थी अपने अधिकारों की मांग करने में मुखर रहे हैं। हालाँकि विदेशी की स्थिति इन लोगों को विरोध प्रदर्शनों और औपचारिक भीड़ जुटाने से प्रतिबंधित करता है, उनके प्रभाव बदनामी से भरे थे; उदाहरण के लिए, Comigrar श्रृंखला के सम्मेलनों के दौरान, साथ ही साथ प्रवासियों का मार्च (Marcha dos Migrantes) - एक विरोध जो 2007 से हर वर्ष साओ पाउलो में होता है। इन कार्यक्रमों में प्रवासियों द्वारा बताई गई मांगों में से कई, जिसे गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भी सहारा दिया गया था, उनको सफलतापूर्वक 2017 के ब्राज़ीली प्रवासी कानून में शामिल किया गया था। एक अन्य ऐतिहासिक प्रदर्शन जो 2009 में हुआ था जिसमें फ़ीलीस्ती के पुनर्वासित शरणार्थियों ने ब्रासीलिया में UNHCR के कार्यालय के बाहर एक हड़ताल की `घोषणा थी, जहाँ परिवारों ने एजेंसी से अतिरिक्त सहायता की या उनको जार्डन के शरणार्थी कैंप में सहायता के साथ वापस पहुँचाने की मांग की (Vera Espinoza 2018; Moulin 2012)। अभी हाल ही में, Martuscelli (2020) बताया कैसे कांगों के शरणार्थियों ने सीधे विदेश मंत्रालय को एक औपचारिक शिकायत आयोजित की थी, जिसमें उनके परिवार के एकीकरण के अनुरोधों की प्रक्रिया समय पर करने की मांग थी। राजनैतिक एकजुटता के इन विभिन्न

जैसा ऊपर विमर्श किया गया था, राष्ट्रीय शरणार्थी सुरक्षा फ्रेमवर्क, और नए प्रवासी कानून दोनों की रूपों में नागरिक समाज संगठनों के समर्थन की भूमिका अविस्मरणीय रही है। ये उपचार, हालाँकि इनके बीच में बीस वर्षों की अवधि रही है, अपने साथ अनगिनत नवाचार विशेषताएँ धारण करते हैं, जिसमें राज्य, संयुक्त राष्ट्र, और नागरिक समाज संगठनों के बीच साझी ज़िम्मेदारी के मॉडल का स्वरूपण करना शामिल है। हालाँकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि इन कर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच का संबंध तनाव से मुक्त है। बहुत ही स्थितियों में, गैर सरकारी संगठन उन भूमिकाओं को निभाते हैं जो मुख्यतः राज्य से जुड़ी होती है, और कई बार सरकारें मानवीय संकट की स्थिति के प्रबंधन के मोर्चे पर नहीं होती हैं। कोविड-19, पिछली सदी की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति, को सुव्यवस्थित रूप से ब्राज़ील की संघीय सरकार द्वारा कम करके आंका गया है। उसी समय, गतिशीलता को सीमित करने और सीमा पर सेना को बढ़ाने के लिए इसे एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। यह स्थायी अपवाद की इस पृष्ठभूमिक के विरूद्ध है (देखें Vera Espinoza et al. forthcoming) जिसे हम इस बात से जाँचते हैं कि कैसे नागरिक समाज संगठनों ने देश में प्रवासियों और शरणार्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया और महामारी के दौरान इन लोगों को सहारा दिया है।

4.2 भारत में नागरिक समाज का एक संक्षिप्त इतिहास

भारत में नागरिक समाज संगठनों का उदय 19वीं शताब्दी के अंत में, उपनिवेशवाद के प्रतिरोध और सुधारवादी कार्यों की युगल प्रक्रियाओं से हुआ था जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा थे। सार्वभौमिकता का दावा करने की प्रक्रिया में, लोकतंत्र, नागरिकता, और नागरिक समाज के विचारों का सह-विकास का हुआ । भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के विचार का विकास हुआ, इसी प्रकार, साथ ही साथ सामंतवाद के विरूद्ध नागरिक आंदोलन और प्रतिरोध विकसित हुए (Chandhoke 2011)[2].

इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ आंदोलनों जिन्होंने भारत में नागरिक समाज की दिशा तय कि थी उनका आरंभ स्वतंत्रता के पहले से है। उन्नीसवीं शताब्दी में, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों जैसे कि ब्रह्म समाज 3 और आर्य समाज 4 ने महिलाओं की शिक्षा और विधवा विवाह के लिए काम किया था। इन समूहों ने हिंदु रूढिवादिता का विरोध किया था, जैसे कि जाति-आधारित ऊँच नीच, प्रथाएँ, और मूर्ति पूजा। ब्रिटिश राज के दौरान मिशनरियों का काम इसी के समानांतर था। वर्ष 1813 में पारित हुए चार्टर अधिनियम के परिणाम में भारत में मिशनरी की गतिविध शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और पुनरूद्धार पर विशेष ध्यान देते हुए बढ़ गई थीं (Sahoo 2013).

वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और वर्ष 1886 में राष्ट्रीय सामाजिक सुधार सम्मेलन की स्थापना के साथ ही, राष्ट्रीयता और सामाजिक सुधार एक दूसरे से जुड़ गए, क्योंकि उपनिवेशवाद का अंत सामने था और यह स्वयं में ही एक नए राष्ट्र के गठन का आव्हान था। इसका ठोस आधार महात्मा गाँधी के सामाजिक और राजनैतिक विषयों को अलग ना करने का दर्शन था। इसी प्रकार उन्होंने कांग्रेस के सदस्यों के लिए गरीब और कमज़ोरों के उत्थान की ओर 'सकारात्मक कार्य' करने पर जोर दिया था (Shah 2019; Sahoo 2013) । इसके एक हिस्से में लंबे समय से चली आ रही जमींदारी प्रथा, बंधुआ मज़दूरी और इसी प्रकार की अन्य असमानताओं से आगे आना शामिल था.

वर्ष 1890 का दशक जाति-आधारित संगठनों के निर्माण का साक्षी था जिसने भी सामंतवाद के विरूद्ध खेतिहर मज़दूरों की एकजुटता के लिए संस्थाओं के रूप में काम किया। इसी प्रकार से, देश के विभिन्न हिस्सों में मज़दूर आंदोलन भी जन्म लेने लगे थे, जैसे कि बॉम्बे के कॉटन मिल्स और कलकत्ता के जूट मिल्स। श्रमिकों का संगठन बनाना आरंभ कर दिया था (Sahoo, 2013)। वर्ष 1910 का दशक सामाजिक नायकों के रूप में महात्मा गाँधी और डॉक्टर बी. आर. आंबेडकर के उत्थान का साक्षी बना।

सभी प्रकार की दासताओं, विशेष तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य, के विरूद्ध विद्रोह में 1857 की बगावत क्रांतिकारी मोड़ था। वर्ष 1885 से लगातार, अनगिनत स्वायत्त कार्यवाहियों और आंदोलनों का जन्म औद्योगिक श्रमिकों, खेतिहर मज़दूरों, निचली जातियों, धार्मिक समूहों, नस्लीय और भाषाई स्वरूपों, और महिलाओं के समूहों के बीच हुआ। ब्रिटिश सत्ता और भूमि के निजी स्वामित्व की उसकी नीतियों का टकराव आदिवासी समाज के भीतर सामूहिक स्वामित्व की परंपरा से हुआ जिसके चलते आगे चलकर किसान आंदोलनों भूमिका रची। देश के विभिन्न हिस्सों में मज़दूर आंदोलन भी आरंभ हो गए थे। वर्ष 1890 के दशक तक, बॉम्बे कॉटन और कलकत्ता जूट मिल्स के श्रमिक काम करने और जीवन यापन की बहुत ही खराब स्थितियों को लेकर विरोध कर रहे थे (Sahoo 2013)। यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी के आते ही, नए-नए स्थापित हुए औद्योगिक श्रमिकों के बीच फ़ैला असंतोष बढ़ रहा था, जिसका परिणाम तत्काल हड़तालों और काम रोकने के रूप में सामने आ रहा था।

इस लंबी पृष्ठभूमि के सापेक्ष, आदिवासी, खेतिहर किसान और मज़दूर वर्ग एक सामूहिक अभिव्यक्ति में आ गए और उन्होंने नारे दिए, जैसे कि "क्रांति जिंदाबाद", और सार्वजनिक मंचों पर विरोध आम हो गए (Shah 2019: 46).[5]

जवाहरलाल नेहरू (1947-1964) के नेतृत्व में, राष्ट्र-निर्माण के एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी मॉडल के आधार पर, कांग्रेस पार्टी ने भारत में राज्य और समाज के मध्य बतौर एकीकरण के एक विशेष संस्थागत लिंक के रूप में काम किया। 'सकारात्मक कार्य' का सिद्धांत 1950 में भारतीय योजना आयोग के निर्माण और ग्रामीण विकास के प्रति एक केंद्रीय व्यवहार नींव रखने की प्रेरणा बना, जिससे पंच-वर्षीय योजनाएँ बनीं (Shah 2019; Sahoo 2013), इसके विपरीत यह इंदिरा गांधी (1967-1977) की सत्ता थी जिसने राज्य और राजनैतिक संस्थाओं के बीच संबंधों में कमी और वर्ष 1975-1977 के बीच के आपातकाल के अन्यायों के विरूद्ध नागरिक समाज के खड़े होने को देखा (Shah 2019; Chandhoke 2003; Dhanagare 2001)। इस सरकार ने स्वयं -सेवी संगठनों की राजनैतिक भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया था। राजनैतिक गठबंधनों और उन स्वयं-सेवी संगठनों जिनको विदेश से फंड की प्राप्ति होती थी उनके ऊपर निगरानी बनाए रखने के लिए संसद में 1976 का विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम (FCRA) लागू किया गया (Sahoo 2013)। Chandhoke पूरा जोर देकर तर्क देते हैं, "नागरिक समाज ने अपनी सबसे असादार जीत तब दर्ज की है जब उन्होंने तानाशाही का सामना किया है, नागरिक और राजनैतिक अधिकारों की अस्वीकृति से अधिक कुछ और असहयोग और राजनैतिक प्रतिरोध की चिंगारी को हवा नहीं दे सकता है।" (2003: 4)। सामाजिक उथल-पुथल के कारण आपातकाल-विरोधी आंदोलनों ने पूरे भारत में जनता को एकजुट और उनका राजनीतिकरण किया। अतः विशेष तौर पर नगरपालिका और औद्योगिक श्रमिकों, इनके साथ ही साथ गरीब और भूमिहीन मज़दूरों को शामिल करने के लिए नागरिक समाज का दायरा बढ़ गया।.

आपातकाल के चलते मार्च 1977 में इंदिरा गांधी की हार हुई और मोरारजी देसाई (1977-79) के नेतृत्व जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। अपने ग्रामीण सुधार कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर, जनता पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं-सेवी संगठनों की स्थापना के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहन दिया। नागरिक प्रशिक्षण में स्वयं-सेवी एजेंसियों की भूमिका पर सरकार ने बल दिया और गैर सरकारी संगठनों के लिए फ़ंडिंग और सरकारी सहयोग बढ़ाया। उदाहरण के लिए, सरकार ने कॉर्पोरेशनों को उनकी कर योग्य आय में से गैर सरकारी संगठनों के लिए अनुदान देने के लिए कटौती करने की छूट दी। जनता सरकार की इन गैर सरकारी संगठन हितैषी नीतियों ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS, जो राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टी की मूल वैचारिक पार्टी भी है) और हिंदु राष्ट्रवादी संगठनों को भी बहुत भारी मात्रा में लाभ दिया, जो आपातकाल के दौरान इनके साथी थे।

जनवरी 1980 (1984 तक) कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आई और एक बार फिर से उसने स्वयं-सेवी क्षेत्र में कार्य को सीमित कर दिया। उन्होंने विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम (FCRA) को 1984 में संशोधित कर दिया, जिसमें उन्होंने भारी संख्या में आर्थिक और कानूनी बाधाएँ लगाईं (Sahoo 2013)। इसने नागरिक समाज के कार्य पर राज्य को असाधारण नियंत्रण दिया, जो आज भी जारी है। जनता पार्टी के पतन के साथ ही, इसके कुछ सदस्यों ने 5 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी (BJP) की स्थापना की और स्वयं को सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी का एकमात्र भरोसमंद विकल्प के रूप में पेश किया। BJP 1998 में सत्ता में आई और 2004 में अपनी हार होने तक, इसने सक्रिय रूप से विकास के नवउदारवादी मॉडलों को स्वीकार किया।

नागरिक समाज पर 1990 के दशक के उदारीकरण के पश्चात की महत्वपूर्ण अवधि का गहरा प्रभाव पड़ा। भारत ने 1990 के बाद के काल में उदारीकरण को गले लगाया। 6 अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता का गैर सरकारी संगठनों ने स्वागत किया था, लेकिन वामपंथ और दक्षिपंथ दोनों ओर के संगठनों जैसे कि RSS ने इसका प्रतिरोध किया (Biswas 2006)। उसी समय, 1990 का दशक वह भी समय था जब सामाजिक आंदोलनों और मूलभूत आंदोलनों ने अधिकारों के फ्रेमवर्क में विकास के आधारभूत मुद्दों को लेकर मुखर होना शुरू किया था। ऐसे कई नागरिक आंदोलन 1990 के दशक के बाद से ही सामाजिक और पर्यावरण के मुद्दों पर भारत में निरंतर फैलते चले गए: ओड़िशा में आदिवासी समाज का पुनर्वास, आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट की खनन, और राजस्थान में जल संरक्षण के आंदोलन, आदि।

[2] संक्षिप्त इतिहास प्रवासन ने स्वयं ही नागरिक समाज संगठनों को अधिक वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय बनने में मदद की थी। हमें देश से बाहर प्रवास और प्रवासन की प्रमुखता वाले नागरिक समाज संगठन संपूर्ण क्षेत्र और देशों में फ़ैले मिलते हैं। इसने ना केवल उनकी वित्तीय संसाधनों को जुटाने में मदद की थी बल्कि विचारों, तकनीकों आदि को भी जुटाने में उनकी मदद की थी। भारत में राजनैतिक भागीदारी को लेकर नागरिक समाज संगठनों (अपने प्रसार के अनुसार) का एक लंबा इतिहास रहा है, उदाहरण के लिए 'गदर आंदोलन' (जो 20वीं शताब्दी के आरंभ का एक अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक आंदोलन था, जो ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए वेस्ट कोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में प्रवासी जीवन जी रहे भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया था)। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गाँधी ने भी उपनिवेशवाद के विरोध के आंदोलन को अपने नेटवर्कों जैसे आज़ाद हिंद फ़ौज (INA) के जरिए भारत के बाहर के देशों, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, मॉरीशस में, और यूके और यूएसए में भारतीय छात्र संगठनों के मध्य एकजुट किया था,। इन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समाज संगठनों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विशेष रूप में, और सामान्य तौर पर कहें तो उपनिवेशवाद के विरोधी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

[3] इसकी स्थापना राम मोहन राय द्वारा 1828 में की गई थी, जो एक धार्मिक सुधारवादी संगठन था जो जाति या धर्म में विश्वास नहीं रखता था।

[4] इसकी स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, जो आधुनिक हिंदु धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य, आरंभिक हिंदु धर्म ग्रंथ, वेदों की पुनर्स्थापना करना था।

[5] यहाँ 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार का ज़िक्र करना अनिवार्य है। यह एक शांतिपूर्ण नागरिक विरोध प्रदर्शन का उदाहरण है जिसे ब्रिटिश द्वारा क्रूरतासे कुचला गया जिसमें पंजाब के शहर में हजारों शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मार डाला गया। ब्रिटिश सेना को मिली दोष मुक्ति से ही यह संभव हो सका कि जो व्यक्ति इस नरसंहार के लिए निजी तौर पर दोषी था, जनरल डायर, उसे अपने इस कार्य के लिए कोई दंड नहीं मिला। तथ्य यह है कि ब्रिटिश ने उस दिन इतने अधिक लोगों की हत्या की इसने संपूर्ण सामाजिक और राजनैतिक परिदृश्य में मौजूदा सामाजिक अन्याय की राष्ट्रीय चेतना को झकझोर दिया।

[6] शीत युद्ध के काल में इंदिरा की सत्ता के अंतर्गत भारत सोवियत ब्लॉक में था। वर्ष 1990 के दशक की पहचान एक ऐसे दौर की जहाँ मौजूदा ढांचे जो आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय रूप से भारत की यथास्थिति को प्रभावित करते थे उनमें मुख्य वैचारिक, राजनैतिक और आर्थिक बदलाव आए।

भारत में नागरिक समाज की स्थापना की ऐतिहासिक राह से, यह स्पष्ट है यह राज्य के साथ कितने गहराई से आपस में गुथा हुआ है - कभी-कभी यह उसके ऐजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए राज्य की मशनीरी के तौर पर काम करता है और कभी-कभी उसकी राजनीति पर सवाल उठाकर राज्य की स्थापना का विरोधी होता है। नागरिक समाज का उत्थान एक ऐसे स्थान के रूप में हुआ था जहाँ सामाजिक सुधार उन संगठनों द्वारा आगे ले जाए गए थे अपने परिदृश्य और व्यवहार में अलग थे। काम का ध्यान विभिन्न विषयों पर था जिसका विस्तार लिंग, धर्म, जाति और श्रम में था। इन संरचनाओं और मुख्यधारा से बाहर के विभिन्न स्वरूपों के सामंजस्य पर राज्य, नागरिक समाज और विभिन्न स्तरों पर लोग काम कर रहे हैं। नागरिक समाज राज्य के संवाद और इससे अलग भी रहता है।

भारत का वर्तमान तीसरा सेक्टर विविध और अनगिनत है। Srivastava और Tandon (2005) के अनुसार, भारत में 12 लाख से अधिक संगठन हैं जो स्वयं को गैर-लाभ के क्षेत्र में रखते हैं। इस विशाल मंच के भीतर, और देश के असंगठित मज़दूर क्षेत्र के दिए गए विशाल आकार के चलते यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, कि अनगिनत नागरिक समाज संगठन उन विषयों पर काम करते हैं जो भारत के प्रवासियों और शरणार्थियों की आवश्यकताओं के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। तीसरे सेक्टर के इन संगठनों की सीमा स्थानीय, से लेकर राष्ट्रीय, से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तक है; वे अनगिनत सामाजिक-राजनैतिक पदों पर हैं, साथ हीं कई ट्रेड यूनियनों और श्रमिकों के संगठनो के साथ नज़दीक से जुड़े हैं, जबकि अन्य पंथ-आधारित या किसी और प्रमुखता वाले हैं और इनकी व्यवस्था श्रमिकों द्वारा स्वयं की जाती है; कुछ के काम लघु-स्तर पर हैं, जबकि अन्य परिचालन के अनुसार कठिन ऑपरेशन करते हैं; कई स्थानीय सरकारों और निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी में काम करते हैं और जिनके पास दस्तावेज़ नहीं है उनके लिए जिला मैजिस्ट्रेटों और स्थानीय कचहरियों कानूनी प्रतिनिधित्व भी उपलब्ध कराते हैं। उनकी कानूनी स्थितियाँ भी काफी अलग-अलग हैं। भारतीय कानून के अनुसार, स्वयं-सेवी संगठनों का उनकी कानूनी स्थितियों के अनुसार, बतौर सोसाइटी, या बतौर चैरिटेबल ट्रस्ट (सार्वजनिक/निजी), या एक गैर-लाभ की कंपनी के रूप में केंद्र या राज्य के कानून के तहत पंजीकृण कराना अनिवार्य है। उनके ऑपरेशन के तरीके भी अलग-अलग हैं, जैसे हो सकता है वे बतौर कोआपरेटिव, ट्रेड यूनियन या धार्मिक संस्थाओं के रूप में काम करते हों (Chandreashekhar 2018)

महामारी के प्रति नागरिक समाज की प्रतिक्रिया

महामारी के दौरान नागरिक समाज की भूमिका को समझने के लिए, सत्ताधारी पार्टी, BJP (2014- वर्तमान) का नागरिक समाज क्या प्रभाव है इसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। यह भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में नागरिक समाज संगठनों के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों जैसे महिलावादी आंदोलनों, पर्यावरण संबंधी आंदोलनों और अन्य नागरिक अधिकार आंदोलनों का प्रभाव है। नागरिक समाज संगठनों के प्रति सरकार की कार्यवाही का एक हिस्सा इन अंतर्राष्ट्रीय लिंक्स से संबंधित रहता है, क्योंकि भारत में संगठनों को लिंग और यौन जैसे विषयों पर काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से फंडिंग प्राप्त होती है।

सरकार ने नागरिक समाज के कर्ताओं पर कठोर कार्यवाहियाँ की है, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया, नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया (Kode & Jacob 2017)। इन्होंने विदेशी अनुदान (नियामक) संशोधन (FCRA) अधिनियम को भी पारित किया था, जिसका संभावित रूप से गैर सरकारी संगठनों और चैरिटेबल संस्थाओं पर विपरीत असर पड़ा है। इसने गैर सरकारी संगठनों के कार्य को अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है क्योंकि अधिनियम एक संगठन के फंड को दूसरे संगठन को देने की अनुमति नहीं देता है, भले ही पहला प्राप्तकर्ता FCRA के योग्य हो, जिसके चलते फंड की कमी होने से बहुत से ऑपरेशनों को मज़बूरन बंद करना पड़ा। वे संगठन जो कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (CSR) फंड्रिंग पर निर्भर हैं वे अधिक कठिनाइयों को सामना कर रहे हैं क्योंकि कॉर्पोरेट फंड्रिंग को तत्काल राहत कार्य और प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत निधि(PM CARES) फंड की ओर रिडायरेक्ट किया जा रहा है (Rustagi & Wu 2020)। BJP ने 2014-2020 के मध्य FCRA के अंतर्गत विदेशी फंडों को प्राप्त करने वाले 20,000 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के लाइसेंसों को रद्द किया था। इसके बावजूद, चूँकि कोविड-19 से निपटने के लिए राज्य जुटा हुआ था,सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने महामारी से लड़ने में सरकार की मदद के लिए 92,000 से अधिक गैर सरकारी संगठनों से अनुरोध किया था (Ramachandran 2020)। नागरिक समाज के घट रहे दायरे के बावजूद, यह व्यक्तिगत तौर पर लोग और गैर सरकारी संगठन थे जो लॉकडाउन की अवधि में एक साथ आगे आए, जिसे बहुत थोड़ी सी तैयारी के साथ BJP द्वारा 24 मार्च 2019 को लगा दिया गया था।

5. प्राप्त परिणामों पर चर्चा

5.1 ब्राज़ील से प्राप्त परिणाम

5.1.1 महामारी के दौरान प्रवासियों के सामने आई चुनौतियाँ

i. दस्तावेज़ीकरण तक पहुँच, अनियमितता और सीमा की बंदी

राज़ील में, महामारी के दौरान प्रवासियों और शरणार्थियों नें जिस पहली विशेष बाधा का सामना किया वह अनियमितता से संबंधित है। वे जो पहले से ही देश में रह रहे थे उन्होंने अपने दस्तावेज़ों के नवीनीकरण में कई तरह की समस्याओं का सामना किया, जिसका मुख्य कारण संघीय पुलिस थी – वह ससंस्थान जो प्रवासन नीति के क्रियान्वयन के लिए ज़िम्मेदार है, जिसमें प्रवासन और शरणार्थी दस्तावेज़ों को जारी करना शामिल है – उसने भारी संख्या में अपॉइंटमेंट के स्लॉटों को घटाया, इसका कारण प्रसार के फैलने की शुरूआत में उनके कार्यालयों के बंद से उत्पन्न कर्मचारियों की कमी थी। हमारे उत्तरदाताओं के अनुसार, दस्तावेज़ीकरण और नियमितिकरण की प्रक्रियाएँ जिनमें तीन महीनों का समय लगता था, अब उसमें छह से नौ महीनों का समय लगता है, और कुछ मामलों में, तो एक साल से अधिक हो गया है। मामलों को और अधिक उलझाने के लिए, सभी प्रक्रियाओं को एक ऑनलाइन फॉर्मेट पर ले जाया गया, जो उन लोगों पर एक अतिरिक्त भार डालता है जिनके पास तकनीकी टूल्स और/या इन सेवाओं तक पहुँचे के लिए जानकारी नहीं है। हालाँकि सरकार ने समाप्त हो चुके दस्तावेज़ों की अपने आप समय-सीमा बढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए एक अध्यादेश (Portaria Nº 18-DIREX/PF) पारित किया था, हमारे उत्तरदाताओं से रिपोर्ट किया था कि सार्वजनिक संस्थाओं को अभी नवीनीकृत किए दस्तावेज़ों की मांग है, साफ़ है कि उनको संशोधित नियम का पता नहीं है।

महामारी की शुरूआत से ही, गणराज्य के राष्ट्रपति के सिविल हाउस द्वारा, न्याय और जन सुरक्षा मंत्रालय द्वारा, और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सीमा की बंदी करने से संबंधित 20 से अधिक अध्यादेशों जारी किया गया था। ये वैधानिक उपचार विशिष्ट रूप से शरण की तलाश कर रहे लोगों की सुरक्षा और/या मानवीय सुरक्षा के ज़रूरतमंद लोगों के लिए ब्राज़ील की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं करते है (ब्राज़ील की प्रवासन नीति के आधार स्तंभों में से एक)। उदाहरण के लिए, 22/05/20 के अध्यादेश 255, ने शरणार्थी सुरक्षा के अनुरोध की संभावना को नकारने के लिए एक कानूनी छिद्र बना दिया था (देखें खंड 5.1.3) देश में पहले से ही रह रहे प्रवासियों के सामने आ रही बाधाओं के बावजूद भी, साक्षात्कार देने वालों ने जोर देकर कहा था कि प्रवासन के प्रबंधन में बदलावों के कारण नए-नए आए लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है।

इस प्रकार, सीमा बंद करने के दो प्रमुख परिणाम रहे हैं: i. अवैध चैनलों (trochas) के जरिए देश में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोत्तरी, जिसके चलते अवैध स्थिति वाले प्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है; ii. मध्यम और लंबी अवधि में गतिशीलता के प्रशासन में संभावित परिवर्तन (देखें खंड 5.1.3).

अनियमितता अन्य समस्या की एक श्रृंखला बना देती है। जैसा लगातार हमारे उत्तरदाताओं के विमर्श में शामिल रहा, सबसे प्रमुखता से दिखाई पड़ने वाले प्रभावों में से एक रहा औपचारिक रोजगार, क्योंकिव्यापार में बिना दस्तावेज़ों के काम नहीं मिलता या, कई मामलों में, जिनकी वैधानिक स्थिति समाप्त हो जाए या अस्थायी हो उनका शोषण होता है। इसका तार्किक परिणाम बेरोजगारी को बढ़ाता है, खास तौरपर सेवा उद्योग में, जहाँ बहुत से प्रवासी और शरणार्थी काम कर रहे थे। परिणामस्वरूप, बहुत से लोग जिनके पास पहले औपचारिक नौकरियाँ थीं, वे मज़बूरन असंगठित क्षेत्र में आ गए। लगातार अपनाए गए लॉकडाउन के उपायों के चलते, भोजन बेचने जैसी गतिविधियाँ लगातार बाधित होती रही हैं और जो परिवार जीवन यापन के लिए ऐसे व्यवसायों पर निर्भर थे उन्हें बहुत अधिक घाटा उठाना पड़ा है। हमारे साक्षात्कार दाताओं के अनुसार, इन समस्याओं का एक परिणाम जो समझ में आता है वह है उन प्रवासियों की संख्याओं का बढ़ना है जो बंधुआ मज़दूरी जैसे स्थितियों की[7]

[7] https://reporterbrasil.org.br/2019/12/pacto-pelo-trabalho-decente-nas-confeccoes-de-sao-paulo-completa-10-anos/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-01/brasil-teve-mais-de-mil-pessoas-resgatadas-do-trabalho-escravo-em

ii. सामाजिक-आर्थिक दुर्बलताओं का बढ़ना

वित्तीय कठिनाईयों ने भी लोगों को करीब पूरी तरह के राज्य से मिलने वाले लाभों पर निर्भर रहने परमज़बूर कर दिया है। लैटिन अमेरिका के अन्य देशों के विपरीत, ब्राज़ील का कानून सभी प्रवासियों को, भले ही उनकी वैधानिक स्थिति कुछ भी हो, सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच की गारंटी देता है (Vera Espinoza et al. forthcoming) – हालाँकि, जैसा खंड 4.1 में कहा गया था, नागरिक समाज संगठनों और जन सुरक्षा कार्यालय को अक्सर इन अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता था। साक्षात्कार देने वालों ने राज्य के राहत कार्यक्रमों, विशेष तौर पर आपातकाली वित्तीय भत्ते तक पहुँच के लिए प्रवासियों और शरणार्थियों के सामने आए कई व्यवहारिक अवरोधों का नाम लिया था।[8] उसमें सबसे आम अनियमितता है, क्योंकि बहुत सेलोग, खास तौर पर वे जो अभी हाल ही में देश में आए हैं, उनके पास आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ नहीं हैं, जैसे CPF और राष्ट्रीय राहत पंजीकरण। ग़लत जानकारी, भाषा संबंधी बाधाएँ और सरकार के ऑनलाइन आवेदन प्रणाली तक पहुँच में आ रही दिक्कतें अन्य दिख रही चुनौतियों के अतिरिक्त थीं। एक साक्षात्कारदाता के अनुसार, इसी तरह के समान प्रक्रिया कुछ प्रकार की मानवीय सहायता के साथ हुई थी।

आर्थिक दुर्बलताओं ने भी प्रवासियों को अपने मूल देश में अपने परिवारों के लिए पैसे और सामान भेजने की क्षमता को प्रभावित किया है, हमारे 25 साक्षात्कार देने वालों में से 19 का यह कहना था। पैसे भेजने में आई गिरावट तीन मुख्य कारकों से आरंभ होती है: बेरोजगारी, महंगाई, और व्यापक अनिश्चितता में तेज उछाल। कुछ साक्षात्कारदाताओं ने स्वीकार किया है कि प्रवासी अक्सर अपने परिवारों की मदद अपने खर्चे से करना चाहते हैं, इसीलिए वे अक्सर पैसे भेजने को प्राथमिकता देते हैं, बनिस्पत ब्राज़ील में अपनी देख- भाल को निश्चित करने के। इसके अतिरिक्त, प्रवासियों की पैसे भेजने में आई कमी परिवार के उन सदस्यों की देश में अवैध प्रवेश को बढ़ावा देता जो वहीं अपने गृह देश में रह गए थे।

हमारे साक्षात्कारदाताओं के अनुसार, ऐसा विशेषकर वेनेजुएला के लोगों के मामलों में है, जो सीमा-पार की गतिविधियों पर हद सेज्यादा निर्भर हैं।

हमारे साक्षात्कारदाताओं द्वारा उठाई गई एक अन्य मुख्य चुनौती है प्रवासियों और शरणार्थियों के बीच बढ़ रही भोजन की कमी और आवास की असुरक्षा। चूँकि बहुत से लोगों के पास किराएदारी के औपचारिक अनुबंध नहीं थे, इसीलिए मकान-मालिक आसानी से लीज को समाप्त करने में सक्षम थे।

> **“कई चुनौतियों में से एक वित्तीय सहायता को पाना है, फिर चाहें वह आपातकालीन वित्तीय सहायता हो या मानवीय सहायता [...] कई अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए लाभार्थियों के आवास की, और प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई उसकी रिपोर्ट करना आवश्यक है; और इस तरह से लोगों का पंजीकरण करना संभव नहीं है [बिना दस्तावेज़ के]।”**
>
> (पंथ-आधारित संगठन के प्रतिनिधित्व, Brasília)

[8] आपातकालीन वित्तीय भत्ता (Auxilio Emergencial) एक सहायता योजना है जो 18 वर्ष या अधिक के व्यस्कों के लिए, जो कम-भुगतान वाले असंगठित काम में हैं। कम-भुगतान वाले काम की परिभाषा इस प्रकार है जिसमें राष्ट्रीय न्यूनतम मज़दूरी का आधा भुगतान मिलता है। लाभ की भुगतान राशि को आरंभिक तौर पर तीन महीनों के लिए R$600/pcm (USD$116/pcm) तय किया गया था, अप्रैल 2020 से आरंभ है। उसके बाद भत्ते को दो अतिरिक्त महीनों के लिए बढ़ाया गया - जुलाई और अगस्त (आदेश 10.412/30 जून)। सितंबर 2020 में सरकार ने चार और महीनों के लिए सहायता की समय-सीमा आगे बढ़ा दी, अब भुगतान राशि कम कर दी गई थी - 53 USD$/pcm (प्रबंधन अधिनियम 1000/2 सितंबर)।

किराए देने में आई समस्याओं के चलते प्रवासी मज़बूरी में बेघर हो चुके हैं, घर का साझा कर रहे हैं या सरकारी आश्रय स्थलों की ओर जा या वापस लौट रहे हैं। बोआ विस्ता में, कई अवैध बस्तियों से प्रवासियों को हटाए जाने के कारण हालात बहुत अधिक ख़राब हो गए थे, यह कार्यवाही नगर-पालिका और सुरक्षा बलों द्वारा महामारी

के दौरान की गई थी। हालाँकि कुछ प्रवासियों को सरकारी प्रबंधन वाले आश्रय-स्थलों में पुनर्वासित करने की पेशकश की गई थी, लेकिन शेष लोगों को सड़कों पर जाना पड़ा था। जैसा उत्तरी ब्राज़ील में नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों ने लगातार चिन्हित किया है लोग ऐसे स्थानों पर जाने के बजाए सड़कों पर जीना पसंद करते हैं, जहाँ उनकी स्वायत्ता और निजती बुरी तरह दबाई जाए। जैसा बोआ विस्ता में एक पंथ-आधारित संगठन के प्रतिनिधि द्वारा संक्षेप में कहा गया, "प्रवासियों ने बार-बार मुझे बोला है कि आश्रय-स्थलों [ऑपरेशन शरण द्वारा संचालित] में वापस जाना ऐसा लगता है जैसे हम एक नहीं कई कदम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं। जैसा वेनेजुएला छोड़ते समय, हम पिछड़ रहे हैं, हम सब कुछ खो चुके हैं।" परिणामस्वरूप, असंख्य परिवारों द्वारा छोटे फ्लैटों का साझा करना कोई अनोखी बात नहीं है, जहाँ की स्थितियाँ सामाजिक दूरी का पालन करने की इजाज़त नहीं देती हैं।

एक अन्य मुख्य अवरोध स्वास्थ्य सेवाओं के लिए असमान पहुँच है, हो सकता है इसका संबंध प्रवासियों के अपने देश वापस भेजे जाने, भाषा के अवरोधों, ग़लत व्यवहार, और प्रवासियों के अधिकारों के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों में प्रशिक्षण के अभाव के भय से हो। प्रवासियों में कोरोना वाइरस की मौजूदगी को निश्चित करना मुश्किल है, क्योंकि राष्ट्रीय व्यवस्था द्वारा मामलों और मृत्यु के आधिकारिक डेटा अलग नहीं है। शोध में भागीदारों के अनुसार, सूचना में यह संपूर्ण कमी प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए विशेष तौर पर

लक्षित जन स्वास्थ्य नीतियों के लिए दबाव बनाने की नागरिक समाज संगठनों की क्षमता को प्रभावित कर रहा है। अधिकांश संगठनों के प्रतिनिधियों यह भी जोर देकर कहा था कि प्रवासियों के स्वास्थ्य पर महामारी के कई प्रभाव हो सकता है इस आबादी पर एक विशाल मनोवैज्ञानिक भार डाल रहे हों।

हालाँकि महामारी ने ब्राज़ील में सबसे अधिक प्रवासियों और शरणार्तियों को प्रभावित किया है, अन्य कारणों के साथ, इसके प्रभावों को सामाजिक-भौगोलिक विशेषताओं और ब्राज़ील में आने के समय के अनुसार अलग-अलग किया जा रहा है। कम से कम 25 साक्षात्कारदाताओं में से 10 का कहना था कि महामारी का बच्चों वाली महिलाओं पर कहीं बड़ा असर पड़ा ता, क्योंकि डेकेयर सेंटरों और नौकरी के अवसरों की अनुपस्थिति थी। कई साक्षात्कारदाताओं ने रिपोर्ट किया था कि प्रवासी महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा के मामले बढ़े। बच्चों की पहचान एक ऐसे समूह के तौर पर की गई थी जो महामारी के दौरान दस्तावेज़ों और शिक्षा दोनों तक पहुँच में समस्याओं के कारण सबसे अधिक प्रभावित समूह थे।

कई साक्षात्कारदाताओं ने रिपोर्ट किया था कि विभिन्न आदिवासी समूहों, विशेष तौर पर वेनेजुएला से विस्थापित वराओ समुदायों को, उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण महामारी से विशेष तौर पर प्रभावित पाया गया है, और यह भी तथ्य है कि वे अन्य प्रवासियों की तुलना में वित्तीय और मनवीय संसाधनों के प्रति कम रूझान रखते हैं। ना केवल इन लोगों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए लक्षित कदम अपर्याप्त है, बल्कि उनके लिए टिकाऊ समाधानों के बारे में कोई समझ ही नहीं है। इसके अतिरिक्त, कई वराओ शहरी जीवन के आदि नहीं है और स्पैनिश या पुर्तगाली भाषा नहीं बोलते हैं, इसीलिए कई का जीवन सड़कों पर काम करते और जीते हुए बीत
रहा है।

iii. प्रवासियों की प्राथमिक रणनीतियाँ

प्रवासियों ने ऊपर बताई गईं चुनौतियों से निपटने के लिए दो मुख्य रणनीतियों को स्वीकार किया है: सबसे पहली का संबंध आय के वैकल्पिक स्रोतों को खोजना है, जबकि दूसरे का संबंध प्रवासियों बीच एकता के नेटवर्कों के गठबंधन से है (कभी-कभी नागरिक समाज संगठनों के सहयोग के साथ)। हमारे साक्षात्कारदाताओं के अनुसार, उन प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है जिनकी नौकरियाँ छूट गई हैं वे घरों से व्यवसाय कर रहे हैं, खास तौर पर भोजन के क्षेत्र में, वह भी तमाम बाधाओं के बावजूद।

"साओ पाउलो में एक गैर सरकारी संगठनों के साक्षात्कारदाता द्वारा जोर देकर कही गई एक बात: "बहुतों के पास घर में अपने उत्पादों को विकसित करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, या उनके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जिससे ग्राहकों के साथ संपर्क करना मुश्किल हो जाता है। यही समस्या भाषा के साथ भी है, हो सकता है वे आमने-सामने के संवाद को करने में सक्षम हों, लेकिन फ़ोन या ऑनलाइन पर यह अधिक मुश्किल है। कुछ लोग भोजन तैयार कर रहे हैं और ऐप्स के जरिए बेच रहे हैं। यह उनके पहुँचाने के समय और उनकी पुर्तगाली भाषा कितनी अच्छी है उस पर निर्भर करता है।"

(साओ पाउलो में गैर सरकारी संगठन कर्मचारी)

दूसरी रणनीति का संबंध प्रवासियों बीच एकता के नेटवर्कों के गठबंधन से है। कई साक्षात्कारदाताओं के अनुसार, कई प्रवासी परिवार दूसरे प्रवासियों को शरण देते हैं जिनको महामारी के दौरान उजाड़ दिया गया था। दूसरे मामलों में, प्रवासियों ने सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक कैसे पहुँच बनाए इसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया था। रियो डी जेनेरियो के एक नागरिक समाज संगठनों के एक साक्षात्कारदाता ने हमें बताया था, वेनेजुएला के लोगों के एक समूह ने आपातकालीन वित्तीय भत्ते तक पहुँच कैसे पाएँ इसके दूसरे प्रवासियों को स्पैनिश भाषा सिखाने के वीडियो बनाए थे। एक और उदाहरण तथाकथित 'बोलीविया-एकता' का निर्माण था, भोजन के पार्सलों के वितरण के लिए बोलिविया के लोगों के बीच एक विशाल गठबंधन है, जिसे ना केवल नागरिक समाज संगठनों से सहायता मिलती है बल्कि अन्य

प्रवासी समुदायों से भी, मुख्य तौर पर कोरियाई और पेरू के लोगों से।

स्वास्थ्य संकट के दौरान प्रवासियों द्वारा लागू की गई दूसरी महत्वपूर्ण रणनीति, आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में अतिरिक्त एकजुटता रही है। कुछ साक्षात्कारदाताओं के अनुसार, कोविड-19 संकट ने महामारी के पूर्व की प्रवृत्ति यानी यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की ओर पुनः प्रवासन को फिर से बल दे दिया। दूसरों ने अपने मूल देश की ओर वापस जाने का, या बेहतर आर्थिक अवसरों को ब्राज़ील में ही घूमकर तलाशने, या दूसरे राज्यों में जहाँ उनको रिश्तेदारों की सहायता मिले वहाँ जाने का निर्णय कर लिया।

5.1.2 नागरिक समाज संगठनों की भूमिका: उदाहरण और अच्छे कार्

योंकि महामारी ने ब्राज़ील में प्रवासियों और शरणार्थियों की दुर्बलताओं को और गहरा कर दिया था, इसलिए नागरिक समाज संगठनों की मांग बढ़ गई थीं। इस खंड में, हम चर्चा करते हैं कि कैसे गैर सरकारी संगठनों, पंथ-आधारित संगठनों और प्रवासी-प्रमुख समूहों ने इन बढ़ रही मांगों को अनुकूलित किया और उन पर प्रतिक्रिया दी। जबकि साक्षात्कार में संगठनों और समूहों की भूमिका, प्रशासन और लक्ष्य अलग-अलग निकलकर सामने आए, ऐसा ब्राज़ील में जिस क्षेत्र में वे स्थित हैं उसके चलते है, यहाँ चर्चा किए गए अधिकांश परिणाम सारे समूहों में एक समान हैं।

i. नागरिक समाज संगठन: फ़ासलों को भरना

ब्राज़ील में नागरिक समाज संगठनों के काम की सीमा उतनी ही विशाल है जितना उसकी भौगोलिक सीमा। वैसे विशेषज्ञता, संस्थागत व्यवस्थाओं, और फंडिंग के आधार पर पूरे संगठनों में गतिविधियाँ और कार्यक्रम अलग-अलग होते हैं, इन संगठनों द्वारा विकसित किए गए अधिकांश कार्यक्रमों का प्रसार तीन क्षेत्रों में होता है: आगमन और समावेशन की प्रक्रिया के दौरान प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए सहायता; समर्थन; और आपातकालीन मदद। महामारी के दौरान, अधिकांश संगठनों ने भाषा उपलब्धता, कानूनी सहायता, रोजगार की योग्यता की कुशलताओं और नौकरी खोजने की गतिविधियाँ, आवास और आश्रय के बारे में सूचना, साथ ही साथ सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच और दस्तावेज़ीकरण में सहायता जैसे कार्यक्रममों के साथ प्रवासियों और शरणार्थियों के आगमन को समर्थन देने की अपनी गतिविधियों को जारी रखने की व्यवस्था कर ली है।

कोविड-19 संकट के दौरान जिस प्रकार का समर्थन सबसे अधिक बढ़ा है वह है मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लक्ष्य से आपातकाली सहायता। इस आपातकालीन सहायता में शामिल होते हैं भोजन के पार्सलों और फूड वाउचरों को प्रदान और/या वितरित करना, हाइजीन किटों, अल्प-कालिक किराया भुगतान और निजी सुरक्षा उपकरण (PPE) का वितरण, अन्य कामों के साथ। इसी दौरान, कोविड-19 से बचाव के बारे में जानकारी प्रदान करके, दस्तावेज़ीकरण तक पहुँच, और सरकार की आपातकालीन वित्तीय

भत्ते के लिए आवेदन और अन्य सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को देकर अग्रणी भूमिकाओं में थे। कुछ मामलों में, उन्होंने आश्रय-स्थलों में सुरक्षा प्रोटोकॉलों का क्रियान्वयन करने में भी योगदान दिया था। विभिन्न प्रकार के नागरिक समाज संगठनों के बीच स्वास्थ्य संकट को लेकर प्रतिक्रियाओं को देने में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था।

ध्यान देने योग्य है, यहाँ तक कि प्रवासी-प्रमुख वाले संगठन जिनकी सामान्य गतिविधियों में आवश्यक रूप से मूलभूत आवश्यकताएँ नहीं थी, उन्होंने महामारी में ऐसा करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए, साओ पाउलो में हमारे द्वारा साक्षात्कार किए गए प्रवासी-प्रमुख संगठनों में से एक ने ब्राज़ील के रेड क्रास और साओ पाउलो नगर-पालिका के साथ नई साझीदारी स्थापित की थी ताकि प्रवासियों के बीच हाइजीन किटों का वितरण हो, साथ ही साथ भोजन के पार्सलों को वितरित करने के लिए निजी कंपनियों और IOM के साथ साझीदारियाँ की। हालाँकि इस परिवर्तनों का स्वागत है, लेकिन बहुत से लोग सहमत हैं कि वे लंबे समय तक इनको जारी रखने के इच्छुक नहीं हैं। साओ पाउलो में जैसे एक प्रवासी प्रतिनिधि ने कहा, "हम भोजन के पार्सलों को बांटना जारी नहीं रखना चाहते हैं; हम लोगों को नौकरी देना चाहते हैं।"

अधिकांश संगठनों ने समान फंडिंग स्रोतों को बनाए रखने की रिपोर्ट दी, हालाँकि कुछ फंडिंग को आपातकालीन सहायता कार्यक्रमों के लिए रिडायरेक्ट करना पड़ा था। हालाँकि, 25 साक्षात्कारदाताओं में से कम से कम 10 महामारी के दौरान नए प्रोजेक्टों या नई साझीदारियों के जरिए अपनी फंडिंग के बढ़ने के बारे में कहा है, जबकि कुछ संगठनों ने इस फंडिंग में कमी की रिपोर्ट दी थी। साझीदारियों में बढ़त कोई आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि नागरिक समाज संगठनों और प्रवासी-प्रमुख संगठनों जमीन पर बेहतर संपर्क बनाने की ओर प्रवृत्त रहे हैं और वे सीधे प्रवासी समुदायों तक पहुँच सकते हैं। हालाँकि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि हमारे साक्षात्कारों में कई संगठनों ने जोर देकर कहा था कि कुछ मामलों में वे महामारी के दौरान भोजन की आपूर्ति या अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की बढ़ती मांग को संभाल नहीं सके थे। उदाहरण के लिए, मनाउस के एक संगठन ने, कहा था कि जबकि उनके पास भोजन था, लेकिन उनके पास वितरण की पर्याप्त क्षमता नहीं थी, इसीलिए दानकर्ता संस्थान को मांग को संभालने के लिए परिचालन के एक विशेषज्ञ को नियुक्त करना पड़ा। साओ पाउलो में एक दूसरे संगठन, ने कहा था कि कुछ प्रवासियों के पास तो भोजन के पार्सलों को प्राप्त करने के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए भुगतान के भी संसाधन नहीं थे।

भोजन के पार्सलों के वितरण के संबंध में एक और समस्या उभर कर आई जिसका संबंध वराओ समुदाय के सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताओं से है। बाहिया राज्य के एक संगठन द्वारा जैसा कहा गया, वे इस आदिवासी समूह को भोजन के पार्सलों को उपलब्ध नहीं करा सके क्योंकि "वराहे विशेष भोजन करते हैं, इसीलिए जो कुछ भोजन के पार्सल में था वे नही खा पाए।" यह विषय कुछ आपातकाली सहायता कार्यक्रमों की एकरूपता को प्रदर्शित करता है, जिसने हो सकता है विभिन्न प्रवासी समुदायों की विशेषताओं पर ध्यान ना दिया हो।

कई नागरिक समाज संगठनों ने यह भी रिपोर्ट किया था कि वे बढ़ रही मांग को संभालने में समर्थ नहीं थे, क्योंकि उनके पास इसके लिए पर्याप्त वित्तीय और मानवीय संसाधन नहीं थे। जैसा साओ पाउलो के एक संगठन द्वारा जोर देकर बताया गया, "हम सभी प्रवासियों जो किराए, बिजली, पानी आदि के लिए मदद की तलाश में थे उनके लिए हमारे पास आर्थिक संसाधनों की कमी थी। हम प्राप्त होने वाले दान तक सीमित थे"। ब्रासीलिया में, एक पंथ-आधारित संगठन ने कहा कि वे आपातकाली सहायता के आगे भी सेवाएँ देना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ थे: "हम सुव्यवस्थित रूप से वायरस से संक्रमित प्रवासी आबादी पर नज़र रखना चाहते थे, ताकि उनके लिए आवश्यक पूरा ध्यान उनको मिले लेकिन हम अन्य मूलभूत सेवाओं के लिए बढ़ी मांगों को लेकर पस्त पड़ गए थे।"

हमारे साक्षात्कारदाताओं के अनुसार, महामारी के दौरान आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराने में, नागरिक समाज की महती भूमिका, जिसमें प्रवासी-प्रमुख संगठन शामिल हैं, दो विषयों को सामने रखते हैं। एक तरफ, कई को संसाधनों को समर्थन और सामाजिक-आर्थिक समावेशन की गतिविधियों से हटाकर आपातकाली सहायता के लिए बढ़ी मांग को पूरा करने में लगाना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ, कोविड़-19 के संकट ने प्रवासियों और शरणार्थियों के संबंध में साथ ही संपूर्ण सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी समुदायों के बारे में ज्ञान की कमी की ब्राज़ील राज्य की निष्क्रियता पर अतिरिक्त दबाव दिया था। मनाउस के एक गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि ने कहा था कि महामारी नागरिक समाज और UN संगठनों पर निर्भरता को प्रमाणित कर रही है। इसके परिणामस्वरूप, "जो नागरिक समाज संगठन सरकार द्वारा छोड़े गए अंतर को भर रहे हैं उन पर एक अतिरिक्त भार है" (साओ पाउलो में गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधि)

ii. हाइब्रिड काम और तकनीक का उपयोग

स्थानीय लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के उपायों का अर्थ है कि अधिकांश संगठनों को काम करने के नए स्वरूप को तेजी से स्वीकार करना था। अधिकांश संगठन निजी सेवाओं और सहायता को प्रदान करने के अभ्यस्त थे। नागरिक समाज संगठनों ने या तो सभी सेवा प्रावधान ऑनलाइन कर दिए या एक हाइब्रिड काम करने का स्वरूप अपना लिया, जिसमें निजी अपॉइंटमेंटों में कमी और अन्य सेवाएँ ऑनलाइन या फ़ोन पर थीं। इस रूपांतरण के लिए डिजिटल तकनीक और कनेक्टिविटी में निवेश, साथ ही कर्मचारी और यूज़रों को इन नए प्लेटफार्मों और सार्वजनिक क्षेत्र स्थापित व्यवस्था को कैसे इस्तेमाल करना इस विषय प्रशिक्षण आवश्यक था। इस नई सच्चाई को स्वीकारना हमारे साक्षात्कारों की एक नई वास्तविकता बात थी, जैसे साओ पाउलो और पोर्टो एलीग्रे में संगठनों के दो सदस्यों द्वारा जोर देकर कहा गया था।

> **"जब महामारी आई तो हमें अनुकूल करना पड़ा। पिछले साल हम सबकुछ ऑनलाइन करना शुरू कर दिया था, उदाहरण के लिए हमारी कानूनी प्रावधान सेवा। हमनें ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रवासियों को एक गूगल फॉर्म भेजा, जहाँ हम साक्षात्कारों का एक रेकॉर्ड रखते हैं"**
>
> (साओ पाउलो में गैर सरकारी संगठन कर्मचारी)

“हमें हमारे काम में अनुकूलन करना पड़ा और कर्मचारी व्यवस्था को जितना हो सका घटाया। उदाहरण के लिए, हमने Teams का इस्तेमाल शुरू कर दिया, लेकिन जिन लोगों को हम सेवा देते हैं उनके लिए यह एक मुश्किल प्लेटफार्म था। (...) इसीलिए, हमने टीम के लिए मोबाइल फोन को खरीदने का निर्णय लिया, जिससे वे सीधे फ़ोन या WhatsApp द्वार सीधे संवाद कर सकते हैं।और अगर उनके पास फोन ना हो, तो हमारे पास अभी भी कुछ निजी तौर की सेवा है”

(पोर्टो एलीग्रे में पंथ-आधारित संगठन का कर्मचारी)

ऑनलाइन काम करने का अर्थ है कि कुछ संगठनों को उनके सोशल मीडिया अकाउंटों को बनाना, फिर से एक्टिवेट, या उपयोग को बढ़ाना पड़ा था, साथ ही कार्यक्रमों और सेवाओं जैसे कि रिमोट प्रशिक्षण, जिसमें पुर्तगाली भाषा के पाठ और सीवी-लिखने की सेवाएँ - कई मामलों में सामग्री के निर्माण या डिलीवरी में स्थानीय विश्वविद्यालयों साथ करके सेवाओं को देने के लिए अन्य प्लेटफार्मों जैसे कि WhatsApp, Zoom, Facebook, Google Meets, और Youtube को स्वीकार कर रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के उपायों, प्रवासियों और शरणार्थियों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया उपयोगी भी थी।

साक्षात्कार किए गए अधिकांश संगठनों के द्वारा काम के हाइब्रिड मॉडल को और डिजिटलाइजेशन और निश्चित सेवाओं (जैसे कि भाषा प्रबंधन) के लिए तनीकीकरण को अपनाया गया था, जिस्से उनकी सामान्य भौगोलिक पहुँच के परे एक विशाल जनसंख्या तक पहुँचने का अवसर मिला। जैसा साओ पाउलो में एक गैर सरकारी संगठन के व्यक्ति द्वारा कहा गया था:

“पिछले साल हमने 415 प्रवासियों को पुर्तगाली की कक्षाएँ दी थीं। उनमें से 30% साओ पाउलो में नहीं रहते थे। हम अब 22 शहरों में लोगों की सहायता कर रहे हैं और यहाँ तक अन्य देशों में भी। हमने वेनेजुएला और सीरिया में मौजूद लोगों को जोड़ा जो ब्राज़ील आएँगे, क्योंकि वे भाषा के कुछ ज्ञान के साथ आना चाहते थे।

साओ पाउलो में एक गैर सरकारी संगठन

डिजिटल हो गई सेवाओं ने दूसरे शहरों में रहने वाले संगठनों के साथ साझीदारियों में भी योगदान दिया था, या तो अपने अनुभव बांटने के लिए या समर्थन के कार्य में परस्पर सहयोग के लिए। हालाँकि, काम के इन नए स्वरूपों की अपनी सीमाएँ हैं, यह स्पष्ट है कि बहुत से मामलों में प्रवासियों और स्वयं-सेवकों के पास तकनीकी संसाधनों या नई तकनीक का कैसे इस्तेमाल करना है की कमी थी। कुछ मामलों में, जैसा कि साओ पाउलो के एक गैर सरकारी संगठन में, इसके चलते स्वयं-सेवकों की संख्या में तकरीबन 50% तक की कमी आ गई, इसका प्रभाव संगठन द्वारा सहायता किए लोगों की संख्या पर भी पड़ा: “आखिरकार, 2020 के अंत में हमने पिछले साल के मुकाबले 50% कम शरणार्थियों को सहायता दी, अलग-अलग इलाकों के लगभग 1000 लोग। वर्ष 2019 में, हमने 2300 से अधिक लोगों को सहायता प्रदान की।” ऐसे संगठनों के मामलों में जो बेघर प्रवासियों या वराओ समुदायों के साथ काम कर रहे हैं जिनके पास किसी तकनीक या कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ रिमोट तरीके से काम करने का कोई विकल्प नहीं था। प्रवासी-प्रमुखता वाले संगठनों के बीच मुख्य चुनौती एकीकरण का बढ़ावा देने या नए आने वालों के लिए निजी तौर पर व्यवस्थित करने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को जारी रखना था।

इन चुनौतियों का सामना करने में, ब्राज़ील के विभिन्न शहरों में कई नागरिक समाज संगठनों ने प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए सहायता केंद्र बनने के लिए सक्रिय रूप से काम किया है।

“हम ‘आश्रयस्थलों’ के तौर पर काम करते हैं, खास तौर पर उन समयों में जब बहुत सी फेक न्यूज़ फैल रही हो, और जब कुछ इस ग़लत जानकारी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हों”

(ब्रासीलिया में पंथ-आधारित संगठन का कर्मचारी)

iii. साझीदारियाँ

नागरिक समाज संगठनों द्वारा अपनाए गए गठबंधन का महामारी के दौरान प्रसार हुआ था, जैसे 22साक्षात्कारदाताओं द्वारा जोर देकर कहा गया था। इन साझीदारियों को बनाए रखना, महामारी के पहले और बाद में, चुनौतियों से मुक्त नहीं है। जैसा साओ पाउलो में गैर सरकारी संगठन के कर्मचारी में से एक ने कहा, सहायता प्रदान करने के सबसे अच्छे तरीके के बारे में असहमतियाँ होती हैं (जैसे चैरिटी बनाम विकासात्मक नीतियाँ; निजी तौर पर या रिमोट रूप से) इसके अतिरिक्त, पूर्व में, फंडिंग की कमी ने भी नागरिक समाज संगठनों और UN एजेंसियों के बीच विवाद को बढ़ाया था, साथ ही साथ इन संगठनो और प्रवासियों और शरणार्थियों के बीच असहमतियाँ भी बढ़ी थीं (देखें Vera Espinoza 2018; Moulin 2012)। महामारी के परिणाम के तौर पर प्रवासियों की बढ़ी हुई दुर्बलताओं ने इन कुछ अंतरों को किनारे रखने का मौका दिया है। इस अवधि के दौरान, नागरिक समाज संगठनों ने गठबंधन के पारंपरिक पैटर्नों (CSOs, Ios और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच) के परे जाकर औपचारिक और अनौपचारिक साझीदारियों को बढ़ाया था, जिसमें पूरे ब्राज़ील में अन्य नागरिक समाज संगठनों के साथ स्थानीय दूरी से पार जाकर रिश्ते बनाना, निजी क्षेत्र के साथ साझीदारियाँ करना, और पूरे क्षेत्र में कुछ और शरणार्थी-प्रमुखता वाले समूहों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उपायों को अपनाना शामिल है।

देश में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (IOs) की अधिक मौजूदगी के साथ, अधिकांश नागरिक समाज संगठनों और शरणार्थी-प्रमुख संगठनों ने इन संगठनों के साथ मौजूदा साझीदारियों को जारी रखने या बढ़ोत्तरी करने की रिपोर्ट दी थी। इसमें UNHCR (जैसा बहुत से संगंठन क्रियान्वयन साझीदारों के तौर पर विशिष्ट कार्यक्रमों काम के लिए धन प्राप्त करते हैं) जैसे पारंपरिक साझीदार और अभी हाल ही में IOM के साथ शामिल है। उत्तरी शहरों जैसे कि मनाउस और बोआ विस्ता, में मौजूद संगठनों ने भी अन्य UN एजेंसियों

जैसे कि UNICEF, UNFPA और UN महिला के साथ, मुख्य तौर पर संघीय सरकार के ऑपरेशन शरण द्वारा समन्वय किए गए मानवीय टास्क फोर्स के हिस्से के तौर पर सहयोग स्थापित किया था। ये IOs भोजन के पार्सलों और वाउचरों, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं, हाइजीन किटों, और आश्रय आदि को उपलब्ध करवाने में मुख्य धुरी रहे हैं। साक्षात्कारदाताओं ने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि Pan-American Foundation for Development, MSF, USAID, World Vision, Caritas International, और Spanish Jesuit Services के साथ नए या विस्तृत साझीदारियों की रिपोर्ट दी थी।

नागरिक समाज संगठनों ने नागरिक समाज संगठनों के बीच बढ़े हुए सहयोग की भी रिपोर्ट दी थी।उदाहरण के लिए बाहिया में एक गैर सरकारी संगठन अधिकारी, ने बताया कैसे उन्होंने नागरिक समाज संगठनों का एक ‘वैकल्पिक नेटवर्क’ बनाया जिससे विशेषज्ञता को जोड़ और रेफरलों का उपयोग कर सकें, जबकि उसी समय “अपना काम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र पर दबाव के लिए सामूहिक रूप से काम किया.” कुछ संगठनों ने यह भी रिपोर्ट किया था कि कुछ बड़े गैर सरकारी संगठन दान के साथ छोटे संगठनों को सहारा दे रहे हैं।.

अन्य प्रमुख साझीदारियों जो महामारी के दौरान जोर पर रही हैं वह जन सुरक्षा कार्यालय (DPU) और निजी क्षेत्रों के बीच का सहयोग है। नागरिक समाज संगठनों ने स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए प्रवासियों और शरणार्थियों की पहुँच के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए DPU के साथ नज़दीकी सहयोग में काम किया था। वहीं दूसरी तरफ, निजी कर्ताओं के साथ सहयोग दान (कंपनियों और निजी व्यक्तियों दोनों से), भोजन वितरण (स्थानीय सुपरमार्केट के साझीदारियों से लेकर Sodexo और JBS जैसे स्थापित भोजन सेवा कंपनियों के साथ गठबंधन तक) और नौकरी तक पहुँच (प्रशिक्षण और नौकरी ढूँढने दोनों की ही रूपों में) के जरिए साकार हुआ है।

भोजन और अन्य दानों के वितरण को व्यवस्थित करने, स्वास्थ्य शिक्षा और अन्य जागरूकता अभियानों को प्रदान करने के लिए कई संगठनों ने नगर-पालिकाओं के साथ विशिष्ट साझीदारियों को विकसित किया है। पोर्टो एलीग्रे में एक गैर सरकारी संगठन के साक्षात्कारदाता ने कानूनी फॉर्मों को भरने के क्रम में संघीय पुलिस के साथ एक अनौपचारिक साझीदारी की भी रिपोर्ट की है। रोराइमा में, एक संगठन ने आपातकालीन भत्ते तक पहुँचे के लिए 1000 से अधिक वेनेजुएला के परिवारों का पंजीकरण कराने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ साझीदारी की थी।

अंत में, साक्षात्कार किए गए कुछ ही संगठनों ने ही क्षेत्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के स्थापित होने के बारे में बताया था। उदाहरण के लिए, साओ पाउलों में एक गैर सरकारी संगठन ने नागरिक समाज के एक क्षेत्रीय प्रयास पर प्रकाश डाला था जिसने मार्च में मानवाधिकारों पर अंतर-अमेरिकी आयोग एक सुनवाई को पक्का किया था। अन्य प्रवासी-प्रमुख संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय अभियान #RegularisationNow, जो प्रवासियों के नेतृत्व में पूरे क्षेत्र में चल रहा था, उसमें अपनी भागीदारी को दर्ज़ किया था।

iv. चुनौतियां

जबकि साक्षात्कार किए गए संगठनों ने अपने काम को तेजी से संभालने और महामारी द्वारा पेश किए गए मांग के परिदृश्य के प्रबंधन के लिए क्षमता दिखाई है, लेकिन यह प्रक्रिया चुनौतियों से इंकार नहीं है। निजी तौर पर सहायता प्रदान करने के लिए अक्षमता के बावजूद, कुछ संगठनों ने, डेटा की निजता संबंधी चिंताओं पर ध्यान देते हुए, स्वयं-सेवकों पर भरोसा करना छोड़ दिया है, क्योंकि वे प्रवासियों और शरणार्थियों के डेटा तक रिमोट पहुंच नहीं प्रदान कर सकते हैं। कुछ मामलों में, निजी तौर पर सहायता की कमी ने भरोसे का माहौल बनने में कठिनाई पेश कर दी थी, जो मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं और पेशेवरों के काम में मुख्य है।

सेवा प्रबंधन में विभिन्न चुनौतियां नागरिक समाज संगठनों के कर्मचारी और स्वयं-सेवकों के मानसिक स्वास्थ्य और आरोग्यता को भी प्रभावित करती हैं। काम के स्थायी घंटों की कमी और बढ़ती हुई मांग ने पारिवारिक जीवन पर असर डाला और 'कभी ना समाप्त होने वाले काम' के एक नज़रिए का निर्माण किया। जैसे ब्रासीलिया में एक पंथ-आधारित संगठन द्वारा चर्चा की गई थी, "मानवता वाले कार्य इसमें शामिल कर्मचारी से बहुत कुछ मांग करते हैं। अक्सर इसमें पूर्ण-कालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है"। इसी प्रतिक्रिया में, संगठन "देख-भाल करने वालों की देख-भाल" गतिविधियों को लागू करने और कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाने की राह देख रहे हैं। साक्षात्कार किए गए संगठनों में से कम से कम सात ने टीम में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और मनोवैज्ञानिक दबाव के बढ़ने की रिपोर्ट की थी। जैसे साओ पाउलो में एक साक्षात्कारदाता द्वारा बताया गया था, प्रवासी कर्मचारी को अपने खाली फ्रिज की फोटो भेजते हैं, जिससे टीम में असहाय होने की अहसास देता था।

साक्षात्कारदाताओं द्वारा रिपोर्ट की गई दूसरी चुनौती है आपातकालीन सहायता से दीर्घकालिक समावेशन और टिकाऊ समाधानों की आगे बढ़ने की आवश्यकता है (देखें खंड 5.1.3)। बोआ विस्ता में एक पंथ-आधारित संगठन के एक कर्मचारी के शब्द हैं,

"हमें हमारे काम को टिकाऊ समाधनानों के प्रति संरचित करने के बारे में सोचने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, परिवारों के साथ लंबे समय तक रहना, अपनी आत्म-सम्मान को वापस पाने और आत्म-निर्भर बनने में उनकी मदद कर रहा है। आम तौर पर सहायता की समय-सीमा होती है और कोई भी अपनी पूरी ज़िंदगी इस पर निर्भर नहीं होना चाहता है।"

बोआ विस्ता में एक पंथ- आधारित संगठन के एक कर्मचारी के शब्

अंत में, विभिन्न संगठनों, खास तौर वे जो उत्तरी सीमा पर स्थित थे, उन्होंने सीमा के दोबारा खुलने पर सीमा पार करने की अनुमानित विशाल बढ़ोत्तरी से निपटने के लिए नागरिक समाज संगठनों की क्षमता के बारे में चिंताओं को व्यक्त किया था। पहले से कहीं अधिक, मानवीय सहायता के लिए एक सशक्त, व्यवस्थित और सामंजस्य प्रतिक्रिया उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो शरण या मानवीय सुरक्षा की तलाश में हैं।

5.1.3 नीतिगत सुझाव

जैसे पूर्व में दस्तावेज़ों में शामिल किया गया था (Vera Espinoza et al, forthcoming), इस शोध द्वारा पुष्टि की गई थी, नागरिक समाज संगठनों - और अन्य गैर-सरकारी कर्ता जैसे कि अंतराष्ट्रीय संगठनों (IOs) - प्रवासियों और अन्य दुर्बल आबादी की मूलभूत आवश्यकताओं और सामाजि-आर्थिक समावेशन की सुलझाने के क्रम में ब्राज़ील राज्य के समान ही पूरक भूमिका निभाते हैं। यह खंड मुख्य नीतिगत सुझावों का संक्षेपण करता है, खास तौर पर नीति के क्रियान्वय के अंतरों के संबंध में और कैसे सरकारें ब्राज़ील के समाज में प्रवासियों और शरणार्थियों के समावेशन के प्रति अपने समर्थन और अपने काम को विस्तार देने के लिए तीसरे सेक्टर को शामिल कर सकती हैं।

i. नीतियों और कार्यों के बीच सामंजस्य को मज़बूत करने की आवश्यकता

राज़ील अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दक्षिण अमेरिका में शरणार्थी सुरक्षा के लिए एक नायक और आदर्श की भूमिका में सराहा गया है (देखें खंड 4.1) और नया प्रवासन कानून 2017, जैसे पहले ही बताया गया था, मानवाधिकारों की सुरक्षा और गैर-विभेदीकरण के सिद्धांतों पर केंद्रित है। हालाँकि, हमारे साक्षात्कारदाताओं ने एक स्र में नीतियों और कार्यों के बीच सामंजस्य की कमी के बारे में इंगित किया था, यह स्पष्ट है कि इन कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति और वित्ती संसाधन नहीं हैं। नीति क्रियान्वयन के ये अंतर नां केवल सामाजि-आर्थिक समावेशन और सामाजिक बंधुत्व की प्रवासियों की संभावना को कम करते हैं, बल्कि राज्य की ओर से संस्थागत जड़ता की चिंतित करने वाली स्थिति की ओर ले गए हैं, जिसके चलते नागरिक समाज संगठनों पर भारी बोझ पड़ रहा है। इसका अर्थ पुनर्वासित आबादी के प्रवेश और बसावट के लिए निर्मित किए गए अस्थायी कानूनी प्रणाली को स्वीकार करने में है, अन्य अंतर-क्षेत्रीय सामाजि-आर्थिक नीतियों के साथ थोड़े से गठजोड़ के साथ है। जैसा हमारे एक साक्षात्कारदाता का कहना है:

"सरकार में सकारात्मकता की कमी नई नहीं है (...) वे लोगों को ब्राज़ील में आने और शरण लेने की अनुमति देते हैं। सरकार की शाब्दिक चतुराई यह है कि 'हमने सीमाओं को खोल दिया है, उनको यहाँ आने देते हैं, हम दस्तावेज़ीकरण प्रदान करते हैं।' और संविधान के अनुसार, शरणार्थियों को ब्राज़ील के किसी अन्य नागरिक के समान ही स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक पहुँच पाने का अधिकार है (...) सरकार ने इसका उपयोग यह कहने के लिए किया है कि वे अच्छा काम कर रहे हैं, आवासों, काम तक पहुँच, भाषा का प्रशिक्षण आदि की बात करने पर, सभी कुछ नागरिक समाज संगठनों द्वारा किया जाता है"

(साओ पाउलो में एक गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि)

जैर बोल्सोनारो (2019 -) की सरकार के दौरान, इन नीतियों की प्रगतिशील भावनाओं पर, प्रसिद्धि पाने वाली, राष्ट्रीयता से भरी नीतियों की पृष्ठभूमि से लगातार सवाल उठते रहे हैं। बोल्सोनारो ने ना केवल देश को सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक करार से बाहर निकाला, बल्कि उनकी सरकार की शाब्दिक चतुराई वाली, नीतियाँ और कार्य तानाशाही दौर के विदेशी स्थिति के अनुसार रहीं, जिसने प्रवासियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरे तौर पर प्रस्तुत किया (Zapata & Tapia forthcoming)।

इस संदर्भ में, महामारी के साथ संबंधित जोखिमों का आरोप लगाकर, सरकार ने अध्यादेशों की एक श्रृंखला के जरिए देश की सीमाओं को सील कर दिया था जो विशिष्ट रूप से वेनेजुएला के लोगों के विरोध भेदभाव करना है। हालाँकि हवाई मार्ग से देश में प्रवेश कर रहे लोगों प्रतिबंधों को जुलाई 2020 से ही हटा लिया गया है, लेकिन किसी साधन से वेनेजुएला से आ रहे लोगों के लिए, प्रतिबंध अपने स्थान पर हैं, एक अनियत समय तक के लिए। विशेष तौर पर इन कार्यवाहियों और इसके लिए और अन्य 'अवांछित' प्रवासी आगमन के लिए देश के प्रबंधन पर इनके दीर्घ-कालिक परिणामों द्वारा उत्पन्न चिंताएँ अपने स्थान पर हैं।

ii. प्रवासन के स्थानीय प्रशासन में उन अंतरों को सुलझाना जो समावेशन के अवसरों को सीमित करते हैं।

नागरिक समाज संगठनों द्वारा पूरे देश में सुझाया दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव उन मुद्दों को सुलझाने से जुड़ा था जिनका सामना उनके रोजमर्रा के जीवन में सामने आते हैं, साथ ही साथ संरचनाओं से जुड़े कारकों की राजनीति और नीतियों के साथ ताकि उनका मध्य- और दीर्घ-कालिक समावेशन हो। दूसरी तरफ, विदेशी लोगों से नफ़रत करने के स्तरों के बढ़ने के बारे में उठाई गई चिंताएँ और भेद-भाव के विरूद्ध एक राष्ट्रीय जन जागरूकता अभियान की तत्काल आवश्यकता थी, ताकि प्रवासी उद्देश्य को दिखाया जाए और प्रवासन के लाभों के बारे में समाज को शिक्षित किया जाए, वे विषय जो देश के नए प्रवासन कानून के लिए मुख्य हैं। दूसरी तरफ, साक्षात्कारदाताओं ने प्रवासियों की योग्यताओं (विदेशी विश्वविद्याल की डिग्रीयों को पुनः वैधता देना) की पहचान के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए, प्रवासियों की आवश्यकताओं और अनुभवों के जानने के लिए, और अप्रवासियों को नौकरियाँ देने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत को चिन्हित किया था। संक्षेप में कहें, तो साक्षात्कारदाताओं ने जातिय और नस्लीय विविधता के बढ़ रहे स्तरों के संभावित लाभों के बारे में स्थानीय समुदायों के ज्ञान के स्तरों को बढ़ाने ज़रूरत को सुझाया था:

> **“ब्राज़ील के समाज को यह समझना ज़रूरी है कि प्रवासी यहाँ मदद के लिए हैं (...) प्रवासियों का समावेशन संघीय पुलिस, या शरणार्थियों की राष्ट्रीय समिति (CONARE) द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि ब्राज़ील के लोगों के व्यवहार से होगा”**
>
> (साओ पाउलो में एक प्रवासी-प्रमुख संगठन के प्रतिनिधि)।

इस सुझाव का एक मुख्य तत्व प्रवासियों और शरणार्थियों की आबादी की विशेषताओं और अधिकारों पर लोकतंत्र में पूरी तरह से व्याप्त जानकारी की कमी को सुलझाना है। इसे लोक सेवकों, विशेष तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और अन्य सामाजिक सेवाओं से संबंधित को प्रशिक्षण देकर नागरिक समाज संगठनों के ज्ञान का[9] लाभ उठाकर किया जा सकता है।

साक्षात्कारदाताओं ने सरकार के विभिन्न स्तरों (स्थानीय, राज्य और संघीय) और अन्य भागीदारों के मध्य बेहतर समन्वयन की ज़रूरत पर भी बल दिया था, ताकि संभवतः एक बहु-स्तरीय टास्क फोर्स का गठन करके जैसा नए प्रवासन कानून 9 में स्थापित, चुनौतियों से निपटने के लिए प्रयाप्त प्रतिक्रिया देने में सक्षम रहा जाए। एक साक्षात्कारदाता के शब्दों में:

> **“शहर और राज्य स्तर के पास व्यवस्थित प्रतिक्रिया नहीं है, जो राष्ट्रीय स्तर से अलग भी है। लेकिन सामान्य तौर पर, मुझे लगता है कि मुख्य चुनौतियों में से एक है प्रवासियों को अधिकारों का एक विषय के तौर मानना जिस पर उनकी नागरिकता का कोई प्रभाव नहीं है। मुझे लगता है अभी सार्वजनिक क्षेत्र में इस बात को पहचाने जाने की कमी है कि प्रवासी और शरणार्थी भी सामाजिक सुरक्षा के तंत्रों तक पहुँच सकते हैं। इसलिए, कुछ शहरों में, प्रवासियों को उन अधिकारों और सेवाओं तक पहुँच पाने में समस्याओं आती हैं जो केवल ब्राज़ील के लोगों के लिए नहीं हैं।”**
>
> (पोर्टोएलीग्रे में एक पंथ-आधारित संगठन के प्रतिनिधि)।

हालाँकि, इस अंतरों को भरने में पूरे देश में क्षेत्रीय और स्थानीय भिन्नताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें प्रवासियों का स्वागत करने वाली अलग-अलग प्रणाली, सार्वजनि ढांचा और सामाजि-आर्थिक गतिविधियाँ शामिल हैं।

[9] कानून 13.445/2017, अनुच्छेद 120: "प्रवास, शरण और राजयविहीनता पर राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य नागरिक समाज संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी संस्थाओं की भागीदारी के साथ राज्यों, संघीय जिला और नगर पालिकाओं के सहयोग से संघीय कार्यकारी शाखा द्वारा कार्यान्वित क्षेत्रीय कार्यों को समन्वित और व्यक्त करना होगा"।

iii. राज्य और नागरिक समाज संगठनों के मध्य संवाद के लिए आगे आना

एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव का संबंध नागरिक समाज संगठनों और सहायता के लिए उनकी तत्काल आवश्यकता के प्रति वर्तमान सरकार के रवैये को बेहतर बनाने से जुड़ा है। नागरिक समाज के प्रति ‘सामान्य तौर पर शत्रुतापूर्ण माहौल’ को कम करने और यह पहचान करने की मांग सरकार से की गई थी कि धरातल पर नीतियों के क्रियान्वयन के लिए उनको बहुत अधिक भार उठाना पड़ रहा है, अक्सर वे उन कामों की ज़िम्मेदारियों को उठा रहे हैं जो राज्य से संबंधित हैं। दो साक्षात्कारदाताओं के शब्दों में:

> **“हम अक्सर कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि राज्य अपने कर्तव्यों से अलग ना हो। उनके लिए यह आसान है कि नागरिक समाज को ही सारा काम करने दें। इसीलिए हमें और अधिक समर्थन के काम करने की ज़रूरत है – हम आपात स्थितियों को नहीं संभाल सकते हैं; हमें प्रशासनिक अधिकारियों से दीर्घ-कालिक उपायों की मांग की ज़रूरत है [...] हमारे पास एक राष्ट्रीय कानून है, लेकिन राज्यों और नगर-पालिकाओं के पास वहाँ क्रियान्वयन की कोई क्षमता नहीं है, जहाँ ज़िंदगी जारी है”**
>
> (ब्रासीलयिा में एक पंथ-आधारति संगठन के प्रतनिधि)।

> **“मुझे महसूस हुआ है कि बतौर नागरकि समाज हमारे प्रयास बस एक आग बुझाने की कार्यवाही के जैसे हैं, और हम असली समस्याओं को सुलझाते ही नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई सार्वजनकि नीति है ही नहीं: हम केवल लोगों के अस्तत्वि को बचाए रखने की गारंटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं**
>
> (रोराइमा में स्थति एक पंथ-आधारति संगठन के प्रतनिधि)।

नागरिक समाज संगठनों के काम को सहायता देने के लिए सामने आए कुछ विचारों में शामिल थे स्थायी वित्तीय सहायता के लिए फंड का निर्माण और कार्यालय के लिए जगह की पेशकश - क्योंकि इन स्थानों व्यवस्था, खास तौर बड़े शहरों में, बहुत महंगी पड़ती है। उन्होंने गैर सरकारी संगठनों और अन्य भागीदारों के साथ सरकार के जरिए साझीदारियों को विस्तार देने या प्रवासियों और शरणार्थियों को पर्याप्त रूप से सेवा देने के लिए प्रस्तावों के पेश करके पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप करना है। इसमें बातचीत के लिए स्थान को खोलना या बनाए रखना, साक्ष्य-आधारित सार्वजनिक नीतियाँ जो प्रवासियों के अधिकारों का सम्मान करती है उनके विकास में नागरिक समाज संगठनों के लिए अपनी बात कहने का अधिकार सुनिश्चित करना है।

अच्छे कार्य जिनको दोहराया जा सकता है उसमें वह स्थान शामिल है जैसा नागरिक समाज का त्री-स्तरीय CONARE में और साथ ही राज्यों की समितियों में है जो विभिन्न नागरिक समाज संगठनों और राज्य के कर्ताओं जैसे प्रवासियों, शरणार्थियों, राज्यविहीन लोगों और मानव-तस्करी के पीड़ित COMITRATE) जो पूरे देश में हैं उन पर ध्यान के लिए समितियों को एक साथ लाता है (ACNUR 2021; Ministério da Justiça 2021)।

iv. निर्णय लेने में प्रवासी प्रतिनिधित्व और भागीदारी को बढ़त।

नागरिक समाज संगठनों द्वारा दिया गए अंतिम नीतिगत सुझाव का संबंध सार्वजनिक जीवन में प्रवासियों की भागीदारी के संबंध में नए प्रवासन कानून के प्रावधानों को अमल में लाने से संबंधित है। हालाँकि कानून अप्रवासियों को मताधिकार नहीं देता है, लेकिन उनके अधिकारों की गारंटी देता है और “प्रवासी नीतियों के स्वरूपण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के लिए सामाजिक बातचीत” में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देता है (खंड II, XIII)। इस दिशा में, साक्षात्कारदाताओं ने मुख्य कार्यों जैसे कि शरणार्थियों और प्रवासियों से स्वयं उनकी बात सुनना, खास तौर पर प्रवासी-प्रमुख संगठनों का, इससे अधिक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ती है, और समाज में फैली उनकी सकारात्मक भूमिका को रेखांकित किया। निर्णय क्षमता में उनकी भागीदारी औपचारिक रूप से बढ़ाने के लिए भी मांग उठाई गई थी, उदाहरण के लिए, स्थानीय तौर पर विभिन्न समुदायों (हैती, वेनेजुएला, क्यूबा, सेनेगल के लोग आदि) के सामुदायिक नायकों को शामिल या नियुक्त करके, ताकि प्रत्येक समुदाय का प्रतिनिधित्व हो और सार्वजनिक नीतियों के प्रभाव की संभावना जानी जाए। इस इलाके में एक अच्छा कार्य साओ पाउलो की अप्रवासियों की नगर-पालिका परिषद है, जो सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज संगठनों के बीच समान प्रतिनिधित्व से युक्त एक सलाहकार परिषद है, जिसमें प्रवासी आबादी के लिए 2016 नगर-पालिका नीति के स्वरूपण, क्रियान्वयन और निगरानी में प्रवासियों और उनके संगठनों को शामिल करता है (Prefeitura de São Paulo 2021)।

5.2 भारत से प्राप्त परिणाम

5.2.1 महामारी के दौरान प्रवासियों के सामने आई चुनौतियाँ

i. आजीविका पर गंभीर प्रभाव

रोजगार की स्थिति और किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने की अवधि भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासियों द्वारा सामना की गई चुनौतियों के स्तर को निश्चित किया था, क्योंकि पहले से मौजूद दुर्बलताएँ और विषण हो गईं थीं। अचानक नौकरियों का छूट उन प्रमुख चुनौतियों में से एक था जिसका सामना प्रवासियों ने किया था जिसका सीधा असर उनकी आजीविका पर पड़ा था। ना केवल नौकरियाँ गईं, बल्कि वेतनों को ना देना और देर से भुगतान का अर्थ था कि प्रवासी किराया नहीं दे सकते थे, इसके चलते वे बेघर हो गए। बहुत से नियोक्ताओं ने कोई जानकारी या सहायता नहीं दी। एक गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि के शब्दों में "सोचिए आपने एक ही समय पर अपनी नौकरी और अपना आवास दोनों गंवा दिया।" जानकारी की कमी ने लोगों के बीच भय और डर फैला दिया।

शुरूआत में, लॉकडाउन के दौरान, वे अपनी सीमित बचत के साथ अपनी व्यवस्था करने में सक्षम थे। जैसे- जैसे अवधि बढ़ती गई, कई घर लौटने की तलाश में थे, लेकिन उनके पास ना तो संसाधन थे और ना ही परिवहन के तरीके। यहाँ तक कि जो किसी तरह से अपने मूल स्थान पर पहुँच गए उन्होंने क्वारंटाइन संबंधी समस्याओं का सामना किया। इस दौरान कुछ प्रवासियों को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम सुविधाओं के साथ 14– 20 दिनों के लिए क्वारंटाइन केंद्रों में रखा गया था, जबकि कुछ तो अपने परिवार के सदस्यों की मदद से गायब हो गए और छिपे रहे, क्योंकि क्वारंटाइन होना अच्छा नहीं माना जा रहा था। इसके अलावा, जो अपने मूल स्थान की ओर वापस लौट रहे थे उन्होंने खेती या सब्जी बेचने का काम किया। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में बहुत अवसर नहीं थे। भूख और खाद्यान्न की अनुपलब्धता एक दूसरी चुनौती थी, साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या उभर रही थीं। एक लगातार जारी महामारी और अपने बचाव, परिवार के लिए चिंता, रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा, घर वापस जाने के लिए परिवहन और पैसे की तलाश के बीच वापस जा रहे प्रवासियों ने चुनौतियों का सामना किया। स्थानीय पुलिस की क्रूरता महमारी की कष्टकारी यादों में से एक छाप छोड़ जाती है। कुछ मामलों, प्रवासियों का मानसिक संतुलन भी खो गया। भविष्य की अनिश्चितता उनके दिमाग़ों में कहीं घर कर चुकी थी।

वापस लौट रहे प्रवासियों के लिए सहारे की कोई प्रणाली नहीं थी। खाड़ी देशों से तेलंगाना वापस लौटने वाले प्रवासियों ने चार्टर फ्लाइटों और वापस आने पर क्वारंटाइन केंद्रों में भारी मात्रा में धन खर्च किया। महामारी ने भारत में विशेष तौर पर शरणार्थी आबादी को सबसे अधिक प्रभावित किया। आम आबादी की तुलना में, बहुत अधिक संख्या में शरणार्थियों ने डिप्रेशन, पोस्ट ट्रामैटिक स्ट्रेस डिआर्डर (PTSD), या स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित थे, इसका कारण युद्ध के भयावह अनुभव और सुव्यवस्थित शोषण था। कई के लिए, महामारी का अर्थ मानसिक-सामाजिक सहायता, मनोवैज्ञानिक देखभाल और दवाओं के लिए पहुँच में कमी से है। आजीविका, आवास और स्वास्थ्य देखभाल के अतिरिक्त, लॉकडाउन के दौरान UNHCR शरणार्थी स्थिति निर्धारण (RSD) गतिविधियों के अस्थायी तौर पर निलंबन का गंभीर प्रभाव शरण की तलाश कर रहे उन मामलों पर जो अभी भी लंबित हैं, साथ ही उन पर भी हुआ जो अभी तक UNHCR के साथ पंजीकृत नहीं हैं। शरणार्थी समुदाय ने इन चुनौतियों का सामना विभिन्न तरीकों के साथ किया है: जबकि कई ने भारत में एक सम्मानित जीवन सुरक्षित करने में बढ़ रही मुश्किलों के चलते अपने मूल देश वापस जाने का फैसला कर लिया था, कई ने UNHCR द्वारा प्रक्रिया किए गए उनके मामलों के लिए रूकने और प्रतीक्षा करने का फैसला किया। एक उत्तरदाता ने कहा कि "दिसंबर 2018 में शरणार्थियों के लिए वैश्विक करार की स्वीकृति के लिए भारत का वोट एक आशा देने वाला बदलाव है।"

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों/ वापस आने वाले प्रवासियों के मामले में, नौकरी के छूट जाने का सीधा प्रभाव विदेशी मुद्रा भेजने पर पड़ा, जिसने व्यक्ति आय के साथ ही साथ राष्ट्रीय आय को भी प्रभावित किया। चूँकि परिवहन के साधन बंद थे, प्रवासी घर पर अपने परिवारों को पैसे भेजने में अक्षम थे। इस प्रवासियों के साथ ही उनके परिवारों जो उन पर आश्रित थे उनके लिए आर्थिक और आजीविका की परेशानी को बढ़ा दिया।

ii. सामाजिक-आर्थिक दुर्बलताएं

हमारे साक्षात्कारदाताओं द्वारा पहचाने गए सबसे दुर्बल समूहों में थे बुजुर्ग, महिलाएँ, बच्चे, और उभयलिंगी समुदाय। महिलाएं घरेलू हिंसा के चलते मानसिक और शारीरिक तौर पीड़ित हुईं हैं। बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ा क्योंकि स्कूल बंद थे और ऑनलाइन पढ़ाई तक हर बच्चे के लिए पहुँचना संभव नहीं था। जैसा दो संगठनों के प्रतिनिधियों से साझा किया, "अगर आप भारत में प्रवासी श्रमिकों का पैटर्न देखते हैं, तो आपको उनका दलित, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य पिछड़ी जातियों से मिलता है। यह सामाजिक समूह भारत की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। यही वे लोग हैं जिनको घर वापस लौटने और नौकरियाँ पाने में कठिनाई हुई थी।" प्रवासी श्रमिकों के मध्य, महिलाएँ उद्योगों में काम करने के प्रवृत्त हैं जिसमें कपड़ा उद्योग, सेवा, सौंदर्य, वृक्षारोपण, निर्माण शामिल है – इन सभी पर महामारी के गंभीर प्रभाव पड़े हैं। उन्होंने अतिरिक्त जोखिमों का सामना किया था, जिसमें यौन और शारीरिक उत्पीड़न और क्वारंटाइन केंद्रों में सुरक्षा के विषय शामिल हैं। टीकारण और पोषणयुक्त भोजन की कमी की चुनौती के चलते बच्चे अधिक दुर्बल थे क्योंकि आंगनबाड़ी 10 लॉकडाउन के दौरान बंद थे। एक प्रमुख चिंता सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाएँ तक पहुँच में कमी के चलते थी, खास तौर पर गर्भवती महिलाओं और बुज़ुर्गों के लिए। बहुत से वरिष्ठ नागरिक भी मज़दूरों के रूप में काम करते हैं और दैनिक मज़दूरी पर जीते और निर्भर रहते हैं। अचानक लगाए गए लॉकडाउन के साथ, वरिष्ठ नागरिकों के पास कोई मज़दूरी या बचत नहीं थी। साथ ही, इन वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोविड-19 का जोखिम बहुत अधिक था।

उभयलिंगी समुदाय के लिए, उनकी आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वह है जो उनको शादी के समारोहों, बच्चे के जन्म और अन्य कार्यक्रमों में मिलता है। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के चलते, उनकी आय के स्रोत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। इसके अलावा, वे भी भूख से पीड़ित हुए थे। चूँकि इनमें से अधिकांश के पास कोई वैध दस्तावेज़ नहीं थे, किन्नरों को सरकार द्वारा प्रदत्त सहायताएँ नहीं मिल सकती थीं। भारत में कई आदिम समूह संस्कृति और संगीत के क्षेत्र में काम करते हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान के मांगणियारों ने शताब्दियों से अपने संगीत प्रदर्शन से जीवन बिताया है और अब वे स्वयं को आगे बढ़ने और प्रदर्शन करने के लिए असमर्थ पाते हैं, जिसने उनकी आजीविका को प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त, चिन निराश्रितों और शरणार्थियों ने स्थानीय समुदाय द्वारा विदेशी लोगों से नफ़रत के व्यवहार में बढ़ोत्तरी की रिपोर्ट दर्ज़ की थी।

iii. महामारी के लिए प्रवासी की प्रतिक्रिया

प्रवासी इस संकट की स्थिति से निपटने के लिए स्वयं ही उपायों की तलाश कर रहे हैं। प्रवासियों ने घर वापस लौटकर स्वयं को बचाने के प्रयास किए हैं। उनमें से कुछ जो सब्जियाँ बेच रहे थे या रिक्शा चला रहे थे उन्होंने यह काम करना शुरू कर दिया है। विशेष तौर पर, महिलाएँ, स्वयं-सहायता समूहों और अन्य समुदाय-आधारित प्रयासों के निर्माण में सक्रिय हैं। सामूहिक प्रयास जैसे स्वयं-सहायता समूह, महिला समूह, युवा समूह, धार्मिक समूह ने एक जगह जमा होने, संक्रमण, वित्तीय दबाव आदि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद दुर्बल प्रवासियों की मदद में प्रमुखता ले ली थी। कई प्रवासियों ने कृषि और मछली पालन को भी अपनाया है। स्थिति संभालने के उपायों में स्थानीय महाजनों से बहुत ही भारी ब्याज पर पैसे लेना शामिल है। एक साक्षात्कारदाता ने कहा कि

"प्रवासी कामगार लोग है जो किसी की दया पर निर्भर नहीं रहे हैं, वे दया पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा करने के लिए मज़बूर हैं"।

(एक उत्तरदाता)

हालाँकि, कुछ मामलों में, प्रवासी पूरी तरह से सरकारों की सहायता पर निर्भर हैं, जैसे कि राशन, स्वास्थ्य सुविधाएँ, और अन्य मुफ़्त या भारी मात्रा में सब्सिडी वाली वस्तुएँ। सभी उत्तरदाताओं ने एक स्वर में कहा कि एक भावना – उम्मीद का टूटना और अपने अपने नियोक्ताओं और विशेष महत्वपूर्ण रूप से सरकार से सहारा ना मिलने का अहसास – उन्हें बड़े शहरों में वापस लौटने से रोक रहा है। जबकि महामारी का प्रभाव शहरी के साथ- ग्रामीण भारत पर भी पड़ा है, गांवों में, प्रवासियों के पास एक प्रकार की सहायता प्रणाली, या रिश्तेदारों का एक नेटवर्क है जो किसी गंभीर आवश्यकता के मामले में उनकी मदद करेगा।

[10]आंगनबाड़ी एक हिंदी शब्द है जिसका सामान्य अनुवाद "चाइल्ड केयर सेंटर" के रूप में किया जा सकता है।

5.2.2 तीसरे सेक्टर के संगठनों की भूमिका: उदाहरण और अच्छे कार्

सामाजिक संकट की गंभीर स्थितियाँ उस नींव के पत्थर को आकार देती है जो कोविड-19 के संदर्भ उभरकर सामने आए भारत के तीसरे सेक्टर के अविस्मरणीय प्रयासों के साक्षी हैं। महामारी और भारत में इसके परिणामी लॉकडाउन महामारी के प्रयास को रोकने के लिए सरकारों द्वारा तिक्रियागत उपाय थे जिन्होंने प्रवासियों और उनके परिवारों के लिए बडे पैमाने पर संकट को उत्पन्न कर दिया था, जैसे ऊपर स्पष्ट किया गया था। कोविड-19 से उत्पन्न अप्रत्याशित स्वास्थ्य संकटों को सुलझाने के प्रयास लाखों लोगों के पलायन का कारण बने, जिनमें से अधिकांश पहले से ही हाशिए पर पड़े समाज और प्रवासी थे। जैसे-जैसे इन प्रवासियों ने स्वयं को तत्काल और अल्प अवधियों में कैसे अपने बचाएं इसकी प्रमुख चुनौती में फंसा हुआ पाया, तीसरा सेक्टर विशाल सामाजिक और संचालनात्मक चुनौतियों के लिए उठ खड़ा हुआ, क्योंकि इसने तेजी के साथ भोजन, आवास, स्वच्छता किट और कोलाहल के बीच परेशानी में फंसे लाखों प्रवासियों को धीरज देने के लिए धरातल पर ऑपरेशनों को विस्तृत और प्रसारित किया (ET Government 2020)।

i. प्रवासियों की चुनौतियों में से कुछ दूर करने में नागरिक समाज संगठनों का योगदान

प्रवासियों की मदद के लिए, बहुत से संगठन, कोविड-19 के जोखिम के बावजूद, अपनी क्षमता के पार चले गए। सीमित गतिविधि की इजाज़त ने इन संगठनों को अपना काम करने से नहीं रोका। उत्तरदाताओं के अनुसार, उनके संगठन ने प्रवासियों के लिए रोजमर्रा की आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने की कोशिश की थी। संगठनों ने प्रवासियों को पकाए हुए भोजन और खाद्यान्न के किट दोनों वितरित किए थे। भोजन के पार्सल, सामान्य तौर पर, उसमें चावल, गेहूँ, दालें, मंजन, प्याज और आलू संगठन के अनुसार अलग-अलग मात्रा में होते थे। उत्तरदाता खुलासा करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान सरकार के मुफ़्त भोजन वितरण के कार्यक्रम लाभप्रद थे। भोजन का वितरण करने में सरकारी एजेंसियों की मदद करने के लिए संगठनों के लिए

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को खोल देना भी एक प्रशंसनीय कदम था, इससे वितरण के लिए न्यूनतम कीमत पर भोजन तक पहुँच मिली। एक उत्तरदाता ने कहा था कि संगठन ने प्रवासियों और उनके परिवारों के लिए 21 दिनों तक भोजन और पानी की व्यवस्था की थी। बच्चों के लिए, संगठनों ने पेंसिल, रबर और ड्राइंग की किताबों को बांटा था।कुछ संगठनों ने प्रवासियों और कारंटाइन केंद्रों के लिए मास्कों और सैनिटाइजरों के वितरण पर ध्यान दिया था। उन्होंने सैनिटाइजरों का कैसे उपयोग करें और महमारी से संबंधित अन्य निर्देशों के पालन के लिए सोशल मीडिया पर छोटे वीडियो प्रसारित किए थे। जानकारी और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने के लिए नागरिक समाज संगठनों ने कैंप भी आयोजित किए थे। कई उत्तरदाताओं ने इस बात की पुष्टि की थी कि संगठन ने कोविड-19 की जाँच के संचालन के साथ ही साथ प्रवासियों के आवागमन के लिए पासों को प्राप्त करने में मदद की। एक संगठन ने लोगों को 'कर्मवीर योद्धा पुरस्कार' देकर उन लोगों कोप्रेरित किया था जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में महामारी के दौरान किसी भी तरह से योगदान दिया था। कुछ

संगठनों ने विशेष तौर पर बिना कागज़ातों वाले प्रवासियों की मदद की जो सरकारी सेवाओं तक पहुँच से छूट गए थे। उन प्रवासियों को तत्काल चिकित्सा सेवाएँ भी प्रदान की गई थीं जिनको इसकी आवश्यकता थी , जिसमें कुछ नागरिक समाज संगठनों की मदद ली गई थी। एक संगठन ने वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को गांवों की नदियों और कुओं की सफाई में शामिल किया था और उन्हें भोजन के पैकेट और हफ़्तों के लिए राशन दिया। एक अन्य संगठन ने 'पवित्र बुद्ध' योजना आरंभ की, जहाँ लोग अपने बची वस्तुओं और वे चीजें जिनका इस्तेमाल नहीं करते (भोजन, कपड़े या कोई भी अन्य सामान) दे जाते, जिसे प्रवासियों और अन्य ज़रूरतमंद श्रमिकों के मध्य वितरित किया जाता था।खाड़ी (गल्फ़) से पुनः प्रवासन करने के विषय में, एक नागरिक समाज संगठन ने श्रमिकों के बीच खाड़ी में ही रहने और ना घबराने के लिए भरोसा जगाया, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉलों का पालन करने के लिए कहा। एक दूसरे नागरिक समाज संगठन ने बाहरी देशो में मौजूद अवैध श्रमिकों की जाँच करवाने और स्वदेश वापस लौटने के लिए सहायता उपलब्ध कराने में भी मदद की थी। जब स्वदेश वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन की घोषणा की गई थी, तब नागरिक समाज संगठनों ने हवाई यात्रा के टिकटों की व्यवस्था करके, और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए प्रवासी श्रमिकों की स्वदेश वापसी के लिए सहायता उपलब्ध कराई थी। जिस समय प्रवासी पैदल चलकर अपने मूल इलाकों की ओर वापस जा रहे थे, गैर सरकारी संगठनों ने उनको पानी, मल्टी-विटामिन की गोलियाँ, प्रोटीन के टैबलेट, महिलाओं के लिए सैनेट्री नैपकिन, मास्क, दस्ताने आदि उपलब्ध कराए थे। मूलभूत राशन के पैकेट- चावल, अनाज, ब्रेड को भी बांटा गया था। संगठनों ने कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए आश्रय तलाशने वालों और शरणार्थियों के लिए एक हेल्पलाइन आरंभ किया था। उन्होंने कोविड-19 के बचाव पर संचारक सामग्री तैयार की थी, जिसमें सरकारी हेल्पलाइनों के बारे जानकारियों को, विभिन्न शरणार्थी भाषाओं में दिया गया था और उन्होंने सरकारी आदेशों आदि के बारे में महत्वपूर्ण संदेश का प्रसार करने के लिए समुदाय के प्रमुखों से संपर्क बनाए रखा था। संगठनों ने शरणार्थियों और शरण चाहने वालों का संपर्क विभिन्न स्थानीय गैर सरकारी संगठनों से कराया था - उनकी स्थिति के आधार पर - आवश्यक सेवाओं और आवश्यकताओं तक पहुँच के लिए था। संबंधित संगठनों ने घरेलू हिंसा की पीड़ितों को राहत प्रदान करने वाले संगठनों से महिलाओं का संपर्क कराया। सबसे महत्वपूर्ण रूप से, संगठनों ने UNHCR और इसकी साझीदार संगठनों के लिए दुर्बल मामलों की पहचान भी थी ताकि लोग सुरक्षा घेरे से बाहर ना जा पाएँ। UNHCR और इसके साझीदार संगठनों के रिमोट कार्य जिसका अर्थ है कि दुर्बल लोग तत्परता के साथ सेवाओं तक पहुँचने में असमर्थ हैं। भारत में शरणार्थियों के लिए समावेशन और एकीकरण की बहुत संभावना नहीं है और महामारी ने इसे केवल और दुरूह बना दिया क्योंकि शरणार्थी असंगठित क्षेत्र में कम नौकरियों के संघर्षरत थे।

एक उत्तरदाता ने जोर देकर कहा था कि "दक्षिण एशिया एक बड़ी ताकत होने के कारण, भारत को शरणार्थी सुरक्षा और टिकाऊ समाधानों के लिए क्षेत्रीय प्रणाली के निर्माण और विकास में सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए, जैसे शरणार्थियों के लिए वैश्विक करार में उम्मीद की गई थी।"

एक उत्तरदाता

ii. नागरिक समाज संगठनों के सामने आई चुनौतियाँ

अंतरों की बात करें तो, बड़े अधिकारियों के साथ संवाद की कमी, फंड और संसाधनों की कमी प्रमुख मुद्दे थे। संगठनों ने कुछ स्थानीय राजनेताओं, कॉर्पोरेटरों आदि के द्वारा वोट बैंक की राजनीति करने के बारे में बताया गया था। स्वास्थ्य सेवा के लिए पहुँच कमज़ोर थी। पिछड़े इलाकों तक यात्रा करने में अक्षमता भी एक चुनौती थी। हालाँकि, कुछ संगठनों का मानना था कि, उचित योजना और प्रबंधन के साथ, संसाधनों और फंडिंग की कमी की चुनौतियों में से कुछ को संभाला जा सकता है।

खाड़ी देशों में सरकार द्वारा संगठनों की पहचान एक बड़ी चुनौती थी। बिना सरकारी मंजूरी, समर्थन और सहायता के, प्रवासी श्रमिकों की मदद करना मुश्किल है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं उपलब्ध कराई गई थी। भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया। स्वदेश वापसी का मिशन एक भुगतान आधारित मिशन था। फंसे हुए श्रमिकों से यात्रा को खर्चे का वहन करने के साथ 14 दिन क्वारंटाइन केंद्र में रहने की उम्मीद की गई थी। हालाँकि, उन प्रवासियों को पहले से ही बुरी तरीके से सरकारी मदद की दरकार थी। वे अपने हवाई टिकटों और आइसोलेशन केंद्रों के खर्च को उठाने में समर्थ नहीं थे। केवल कुछ ही वापस लौटने का खर्च वहन सकते थे।

iii. अच्छे कार्य

अच्छे कार्यों के संबंध में, कुछ उत्तरदाताओं ने रेखांकित किया था कि केरल की सरकार ने उन लोगों के लिए 5000 रूपए की धनराशि घोषित की थी जो महामारी के दौरान काम नहीं कर पाए। उन्होंने उन लोगों के परिवार के सदस्यों के लिए 10,000 रूपए की घोषणा की थी जिनकी कोविड-19 से मौत हो गई थी। इसके अतिरिक्त, वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के सहायता पुनः समावेशन ऋणों के जरिए करने की घोषणा की गई थी। हमारे साक्षात्कारदाताओं द्वारा बताए गए अच्छे कार्यों में से एक केरल सरकार के अंतर्गत श्रम और कौशल विभाग से संबंधित था, जिसने अतिथि श्रमिकों के लिए आवाज़ (AAWAZ) बीमा कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त, एक गैर सरकारी संगठन सभी श्रमिकों के लिए 'मज़दूर आईडी कार्ड' बनाने के लिए सरकार पर दबाव डालने की योजना बना रहा है ताकि उनको समाज में पहचान मिले। इसके अलावा, वे निर्माण स्थलों पर बच्चों के लिए मनोरंजन के स्थान के निर्माण पर विचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उनको मूलभूत स्वच्छता, बचत की अहमियत आदि बातें सिखाई जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार ने एक बार में 3000-5000 प्रवासियों को व्यवस्थित करने के लिए विशाल आश्रय स्थलों का निर्माण किया है।

भोजन, चिकित्सा सहायता और पानी मौजूद था। मोबाइल के लिए चार्जिंग के पॉइंट बिस्तर के बगल में थे। इसके अलावा, आश्रय स्थलों में अच्छा समय व्यतीत करने के लिए खेल संबंधी वस्तुएं भी दी गईं थीं।

अच्छे कार्यों के द्वारा, एक संगठन ने 'आपातकालीन सहायता सेवा' की एक नीति को स्थापित किया था जिसमें बिहार में स्थानीय जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा लोगों के लिए एक ग्राहक सेवा नंबर प्रदान किया गया था। महामारी के दौरान परेशानी में फंसे लोगों के लिए यह नंबर था ताकि वे स्थानीय सरकार द्वारा उपलब्ध सहायता जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, भोजन आदि को प्राप्त करें। यह नीति बहुत प्रभावी थी और इससे उन 25,00,000 प्रवासियों को बहुत मदद मिली जिन्होंने बिहार में 'कर्मनासा की सीमा' पार की थी।

एक अन्य नागरिक समाज संगठन ने कहा था कि सरकार द्वारा किए गए कई प्रबंध केवल कागज़ों पर थे, लेकिन वास्तविकता, वाकई कुछ नहीं हुआ था। एक उत्तरदाता ने बताया था कि "अगर गैर सरकारी

संगठनों और उनके काम मौजूद ना होते, तो प्रवासियों के हालात कहीं बदतर हो जाते।" एक संगठन का कहना था कि स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देश अच्छे थे। स्थानीय पुलिस द्वारा की गई निगरानी बहुत मददगार साबित हुई क्योंकि उन्होंने उन पर दंड लगाया जिन्होंने मास्क नहीं पहना था और सरकारी निर्देशों की अनदेखी की थी। उन्होंने लोगों को नियमों का पालन करने के लिए बाध्य किया। हॉस्पिटलों से प्राप्त उपयोगी सलाह ध्यान देने योग्य थी।

iv. गठबंधन, साझीदारियाँ और फंडिंग

साझीदारियों और सहयोगों के संबंध में, एक संगठन का कहना था कि उसने International Parliament of Kerala के साथ गठबंधन किया था। प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए एक 'विशेष हॉटलाइन' 'सामुदायिक समूहों' का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त संगठन ने सरकार के स्थापित संगठन, 'Norka Roots', International Parliament of Kerala और उनके सामुदायिक समूहों के साथ काम करके चिकित्सा सहायता और भोजन के साथ लोगों तक पहुँच प्राप्त की। इसके अलावा, यह 'Migrant Forum in Asia' का सहयोगी था। बहुत अधिक संख्या में विशाल संगठन इस फोरम के साथ जुड़े हुए थे जिनका प्रसार जीवन के विविध क्षेत्रों तक में था (वकील, मीडिया, उद्यमीस, नियोक्ता)।

कुछ संगठनों ने कहा कि विभिन्न शहरों में कई स्थानीय/जमीनी गैर सरकारी संगठनों के साथ गठबंधन किया गया था। कुछ संगठनों ने स्थानीय प्रशासन के साथ गठबंधन किया था ताकि सहायता उपलब्ध कराई जाए और इसके अपने कार्यवाहियों को करने के लिए आवागमन के अनुमतियों प्राप्त किया जाए। एक संगठन ने एक विशाल देश-स्तरीय गैर सरकारी संगठन के साथ गठबंधन किया और संसाधनों के तौर पर मदद प्राप्त भी की।

आगे कहें तो, Whatsapp जैसे ऐप्स ने गठबंधनों को करने में मदद की और एक ही क्षेत्र में एक साथ काम करने की मुश्किल से बचने में मदद की। सामूहिक प्रयास जैसे स्वयं-सहायता समूह, महिला समूह, युवा समूह, धार्मिक समूह ने एक जगह जमा होने, संक्रमण, वित्तीय दबाव आदि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद दुर्बल प्रवासियों की मदद में प्रमुखता ले ली थी।

फंडिंग के संदर्भ में, उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाएँ मिली-जुली थीं। कुछ ने बताया कि उनके संगठनों को फंडिंग में भारी कमी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी फंडिंग के स्रोत भी महामारी द्वारा प्रभावित थे। वहीं दूसरी तरफ, कुछ संगठनों ने अपनी फंडिंग में बढ़त देखी थी, क्योंकि उन्होंने महामारी के दौरान नए नेटवर्कों और फंडिंग के स्रोतों का निर्माण किया था। दूसरे संगठनों को आय के स्रोतों में कोई महत्वपूरण बदलाव नहीं नज़र आए क्योंकि उन्होंने ज़िम्मेदारियों का वितरण कर दिया था। एक मामले में, एक सत्यापित Twitter (ब्लू टिक) अकाउंट ने संगठन को वैधता देने के लिए मदद की और इसके चलते भरोसा बढ़ा, जिससे फंडिंग में बढ़त हुई।

5.2.3 नीतिगत सुझाव

यह स्पष्ट है कि महामारी ने भारत के सामाजिक ढांचे में लंबे समय से चले आ रहे अंतरों और दरारों को खोलकर रख दिया है, जो महामारी के दौरान बहुत अधिक गहरा हो गया है, जिसने प्रवासियों और अल्प- कुशल, असंगठित क्षेत्रों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। इस आबादी की सहायता करने के लिए तीसरे सेक्टर के प्रयासों ने मौजूदा राष्ट्रीय और राज्य की नीतियों में विशेष अंतरों को प्रकट किया है जिनको तत्काल सुलझाना आवश्यक है यदि ऐसा संकट की स्थिति दोबारा कभी भविष्य में आती है तो उसके लिए।

i. मज़दूर का नियमितिकरण और दस्तावेज़ीकरण

प्राथमिकता के तौर पर, महामारी ने इस तथ्य के लिए अचूक साक्ष्य दिए हैं कि मज़दूर की अनौपचारिकता को नियमित करना आवश्यक है। बहुत से श्रमिक देश के दूसरे हिस्सों से आते हैं, जहाँ वे बड़े शहरों और उद्योगों में बिना निर्धारित दस्तावेज़ीकरण की सुरक्षा के काम करते हैं। गैर-पंजीकृत और पहचाने जाने में अयोग्य, वे अपने ही देश में प्रभावी तौर पर अवैध नागरिकों के रूप में रहते और काम करते हैं, अक्सर वे स्थानीय भाषाओं को बोलने या पढ़ने या लिखने में असमर्थ रहते हैं। इससे वे सामाजि सुरक्षाओं के संसाधनों से अछूते रह जाते हैं और जीवन के मूलभूत साधनों के लिए अपने नियोक्ता के आसरे रहते हैं। आंशिक तौर पर, ऐसा ठेकेदारों की नियुक्ति प्रक्रियाओं के चलते होता है, जो असंगठित, बिना किसी अनुबंध के भर्तीकरते हैं, जिससे कि कोई प्रवासी मज़दूर बल के कोई वित्तीय या अन्य पहचान या उनकी सुरक्षा ना हो। नीति-निर्माण द्वारा किया गया, प्रवासी मज़दूर का पंजीकरण जो निजी क्षेत्र और इसके एजेंटों को सरकार के प्रति उत्तरदायी ठहराता है, वह सभी प्रवासियों के लिए आधिकारिक पहचान स्थापित करेगा।.

निर्धारित दस्तावेज़ीकरण को उपलब्ध कराने के लिए नीतियाँ विधायी प्रक्रियाओं और मज़दूर नीतियों को भी जोड़ सकती हैं जिससे प्रवासियों के लिए स्थितयाँ बेहतर होती हैं। एक तथ्य जो बार-बार साबित होता है वह यह है कि असंगठित प्रवासी मज़दूर बिना अनुबंधों या स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्थाओं के काम करने को मज़बूर होता है। ये श्रमिक गंदी बस्तियों में रहने को मज़बूर होते हैं, जहाँ स्वच्छ, साफ पानी, और अन्य मूलभूत सुविधाओं की पहुँच नहीं होती है। तीसरे सेक्टर के संगठन लगातार प्रवासियों और उनके परिवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता के आवास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुँच की आवश्यकता पर बल देते हैं। वे उन तरीकों को भी रेखांकि करते हैं जिनके जरिए श्रमिकों का निर्धारित पंजीकरण नियोक्ता के अच्छे कार्यों से सरकार श्रमिकों की ज़िंदगियों को बेहतर सम्मान देने के लिए जोड़ सकती है। एक संगठन ने बताया कि, प्रवासियों के लिए यात्रा, भोजन और सैनिटाइजर दान करने के बजाए, संबंधित राज्यों की सरकारों को उनके काम करने वाले शहर में ही भोजन और अन्य मूलभूत सेवाओं को उपलब्ध कराना चाहिए था। इससे बहुत बड़ी सीमा तक रोग के प्रसार से बचा जा सकता था और अचानक मचे कोलाहल से भी मुक्ति मिल सकती थी।

ii. सरकार और नागरिक समाज संगठनों के संवाद का बढ़ना

समर्थन के साथ जमीन पर किए गए नागरिक समाज संगठनों के कार्य के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने संकट का सामना करने में अकेले काम नहीं किया, बल्कि प्रवासियों द्वारा अनुभव की गई आवश्यकताओं, दुर्बलताओं और जोखिमों के बारे में ठोस जानकारी भी प्राप्त की है, जो इस देश के श्रमिक बल का सबसे बड़ा हिस्सा हैं और विदेश में काम करते हुए देश में पैसा भेजकर विदेशी मुद्रा का प्रवाह करते हैं। संकट से निपटने के लिए तीसरे सेक्टर द्वारा किए गए प्रयास जो महामारी के दौरान खुलकर सामने आएवे उनकी उस भूमिका का साक्ष्य हैं जो वे स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर निभाते हैं। नागरिक समाज संगठनों का, अपनी संपूर्ण विविधता में, भारत के सभी नागरिकों, चाहें वह किसी भी सामाजिक वर्ग, जाति या धर्म के हों, उन के समावेशन और एकीकरण में मुख्य भूमिका के लिए पहचाना जाना आवश्यक है। सरकार के साथ नागरिक समाज संगठनों के गठबंधन के संबंध में, यह सुझाव दिया गया था कि सरकार को स्थानीय और जमीनी-स्तर के गैर सरकारी संगठनों के साथ अधिक सहयोग करना चाहिए। स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के काम को पहचाने जाने और एक पोर्टल बनाने की आवश्यकता है जहाँ स्थानीय गैर सरकारी संगठन अपने कार्य को दिखा सकें। कुछ संगठन सुझाव देते हैं कि सरकार कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े सुरक्षा उपायों भ्रमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नागरिक समाज को शामिल कर सकती है।

प्रवासियों के प्रशिक्षण देने वालों को नियुक्त करने के सुझाव दिए गए थे, और प्रवासियों द्वारा किए गए लोन के आवेदन को तेजी से निपटाने के लिए बैंकों के साथ गठबंधन के लिए गैर सरकारी संगठनों को नियुक्त करने के सुझाव दिए गए थे। नागरिक समाज संगठनों को यौन कर्मियों, किन्नरों, तलाकशुदा महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य दुर्बल समूहों के सर्वे में शामिल किया जा सकता है ताकि यह आकलन किया जाए कि उनको भोजन और आवश्यक सेवाएँ मिल रही हैं या नहीं। तीसरे सेक्टर को लोगों को सशक्त करना और अधिक प्रभावी काम करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। एक उत्तरदाता का तर्क था:

> **"हमें (नागरिक समाज संगठनों को) एक उत्प्रेरक के समान काम करना चाहिए और हमें सरकार के काम को कराना चाहिए। हमारा काम सरकार की जगह लेना नहीं, ना ही वह काम करना है जिसे सरकार को करना चाहिए। अस्थायी तौर पर सरकार को यह दिखाने के लिए कैसे चीजों को बेहतर करना है हम कुछ काम कर सकते हैं। बड़े स्तर पर बदलाव लाना सरकार का काम है, इसके बजाए हमें लोगों की मदद के लिए सरकार और उनकी एजेंसियों के साथ काम करना चाहिए।**
>
> एक गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि, नई दिल्ली

आवासीय किराया परिषदों का गठन करना चाहिए ताकि बलपूर्वक मकान खाली कराने से बचा जाए और झुग्गी बस्तियों नोटिफिकेशनों को देना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ (SSS) मज़दूरों के लिए आवश्यक हों। प्रवासियों के 'डेटा' पर भागीदारों के साथ विमर्श होना चाहिए। आंतरिक रूप से, श्रेणियाँ जैसे कि एक महिलाएँ, किन्नर, या सड़कों पर रहने वाले अधिक दुर्बल थे और इसीलिए विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा प्रणाली इनके लिए आवश्यक थी। इस संबंध में, नागरिक समाज संगठनों की मदद को लोगों की आवाज़ के तौर पर लिया जाना चाहिए। सरकार को दुर्बलता की पहचान करने के लिए एजेंसियों और नागरिक समाज संगठनों के साथ नेटवर्क बनाना चाहिए। कुछ उत्तरदाताओं ने ध्यान देने पर पाया था कि वे शोध पर ध्यान देते हैं और आजीविका, परिवहन,

> आवासीय लागतों के काम को प्राथमिकता देते हैं, और सरकार को सलाह देते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया करें। वे घर से काम के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी पाया कि वे लड़कियाँ की शिक्षा और जागरूकता के कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

iii. अप्रवासी समावेशन को सुलझाना

तीसरे सेक्टर की मदद के साथ, सरकार को अंतर्राष्ट्रीय/वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए नीतियों में सुझार करना चाहिए। नागरिक समाज संगठन उन नौकरियों और क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जिनकी भविष्य में अधिक मांग रहेगी। सरकार को उन प्रवासी श्रमिकों के लिए जो महामारी के दौरान वापस आए थे, एक डेटा एकत्रीकरण कार्यक्रम आरंभ करना चाहिए। उनकी कुशलताएँ, अनुभव और ज्ञान, उनकी भविष्य की योजनाएँ इन सभी को इस डेटा में रेकॉर्ड किया जाना चाहिए। सरकार को उन प्रवासी श्रमिकों

के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए जिनकी नौकरियाँ छूट गईं थीं और उनको मुआवजा देना चाहिए। परिवार के लिए भी एक सहायता प्रणाली उपलब्ध कराना चाहिए। सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक करार (2018) में शामिल 23 उद्देश्यों के आधार पर इन क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों के लिए नीति का विकास करने की एक आवश्यकता है। एक अधिक मानवीय तरीके से प्रवासियों को उनकी आजीविका के स्रोतों में वापस समावेशित करने की आवश्यकता है। महामारी ने प्रवासियों की भारी भीड़ को सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस प्रकार, विडंबनापूर्ण रूप में, महामारी के दौरान प्रवासियों के सम्मान बढ़ गया है। लोग अब उनके काम को मान देते हैं और उनको बराबर का नागरिक मानते हैं। परेशान प्रवासियों की यह पहचान कहीं छिप सी गई है और उनको वापस प्रेरित करने की आवश्यकता है। एक उत्तरदाता ने सुझाव दिया कि प्रवासियों को भी प्रयास करने होंगे। उदाहरण के लिए, वे गांवों में व्यापार शुरू करके अपना समावेश कर सकते हैं। गांवों में, लोगों के पास अपनी जमीन है, अगर वे उस पर काम करें और अपने समय और संसाधनों का प्रयोग करें, तो वे कमाई भी करेंगे। यहाँ तक कि अगर किसी के पास खेत नहीं है, तो वह सब्जियाँ उगाकर पैसे कमा सकता है। नागरिक समाज संगठन यह भी सुझाव देते हैं कि समावेशिक महसूस करने के लिए प्रवासी श्रमिकों कोरोजगार योजनाओं तक पहुँच बनाना चाहिए था। संगठनों में से एक ने विभिन्न विषयों के संबंध में प्रवासियों के लिए जागरूकता अभियानों की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था ताकि उनको अधिक जागरूत और समाज में समावेशित किया जाए।

iv. नई भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ

नए कार्यक्रमों के संबंध में, कई संगठन लगातार भोजन के पार्सलों, कपड़ों, दवाओं, पानी और प्रवासी महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिनों का वितरण करना जारी रखेंगे। एक गैर सरकारी संगठन की योजना गांवों मे सामुदायिक कल्याण केंद्रों को आरंभ करने की है, जहाँ महिला मुफ़्त में सिलाई जैसी कुशलताओं को सीखेंगी, और बच्चों का ध्यान रखा जाएगा। एक अन्य नागरिक समाज संगठन ने कहा कि वे महामारी के बाद भी 'फूड बैंक' कार्यक्रम को जारी रखेंगे। यह संगठन स्वास्थ्य में सुधार के लिए आयुर्वेदिक और अन्य दवाइयों का वितरण भी जारी रखेगा। नागरिक समाज संगठनों ने कहा कि यह महिलाओं से संबंधित विषयों पर कार्य करना जारी रखेगा और उनके अधिकारों पर जागरूकता फैलाएगा, जबकि एक दूसरे संगठन का कहना ता कि यह प्रवासी श्रमिकों को आजीविका के अवस उपलब्ध कराना जारी रखेगा, - जैसे कि पर्यावरण को स्वच्छ रखकर या सब्जियाँ बेचकर -, जिससे किए कई स्वयं को नियमित बनाए रख सकते हैं।

6. निष्कर्ष

इस अध्ययन का ध्यान कोविड-19 की महामारी के दौरान दो प्रमुख विकासशील देशों, ब्राज़ील और भारत में, प्रवासियों की सहायता में नागरिक समाज की भूमिका पर था। दोनों देशों में कुछ निश्चित समानताएँ हैं, जैसे कि विशाल भौगोलिक क्षेत्र, क्षेत्रीय रूप से औद्योगिक और आर्थिक शक्ति और सहभागी लोकतंत्र; पर इसके साथ ही साथ यहाँ दीर्घ-कालिक ढांचागत असमानताएँ हैं। इसके बावजूद, ब्राज़ील और भारत एक साथ अपने डायनामिक्स और प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए अपनी बाध्यताओं के मामले में अलग हैं। इस क्रॉस-क्षेत्रीय विश्लेषण में संपूर्ण रूप से जो बात सामने आती है उनमें वे अंतर हैं जो नीतियों और कार्यों के मध्य में मौजूद हैं, जो लंबे समय से मौजूद हैं लेकिन महामारी के प्रसार और निरंतर कडाउनों के बाद महत्वपूर्ण रूप से दिखने लगी।

यह भी स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि प्रवासी नेतृत्व वाले संगठनों सहित विभिन्न प्रकारों और आकारों के नागरिक समाज संगठनों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका बिल्कुल महत्वपूर्ण है। यदि, महामारी के पहले, नागरिक समाज संगठन आम तौर पर अल्पसंख्यक या सीमांत समूहों की सहायता और पैरवी से जुड़े थे, तो महामारी ने संकट की स्थिति में उनके लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता को भी उजागर किया है।

बहुत से नागरिक समाज संगठनों नें जो समर्थन में शामिल थे उन्होंने अपने काम को रूपांतरित किया, कुछ मामलों में तो रातो रात बदलाव करके आपातकाली सहायता मुहैया कराई है। भोजन, स्वास्थ्य देखरेख, कानूनी सहायता का प्रबंधन और बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे वापस लौट रहे लोगों की निजी आवश्यकताओं, जैसे कि मास्क, सैनिटाइजरों और अन्य वस्तुओं को प्रदान करना, प्राथमिकताएँ रही हैं। इसलिए, महामारी में फंसे लोगों को लिए जागरूकता, सूचना, शिक्षा और सहायता की तत्काल आवश्यकता भी है। नागरिक समाज संगठनों का धरातल पर होने का अर्थ है कि उन्होंने आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए स्वयं को तैयार किया और उस पर प्रतिक्रिया दी जबकि उनके लक्ष्य, वास्तव में, समाज में ढांचागत सुधार करने से संबंधित है। इसी प्रकार से, उन्होंने सरकारों से बहुत पहले अपना काम आरंभ कर दिया था, राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तर पर, वे ऐसा कर सके।

यह आश्चर्य की बात नहीं है, इसके द्वारा नागरिक समाज संगठनों ने अपने क्षेत्र को विस्तार और वृद्धि दोनों ही रूपों में सभी संभावनाओं से भरपूर पाया। ये भागीदारियाँ उनकी स्थितियों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच एक उपयोगी पुल के रूप में सुदृढ़ करती हैं।

इसके आगे, यह रिपोर्ट सरकारों के लिए इस आवश्यकता की मांग करती है कि वे विस्थापन के संदर्भ में नागरिक समाज संगठनों के काम को पहचान और समर्थन दोनों दे। उन्होंने संकट की स्थिति में सामाजिक बंधुत्व के लिए प्रमुख के रूप में काम किया था, लेकिन भविष्य ऐसे संकटों से बचने के लिए उनके समर्थन के प्रयास को समझना आवश्यक है। महामारी ने इन संगठनों की तीव्र क्षमता और बहु-पक्षीय ताकत को निखारा है, जहाँ वे एक ही समय में, सहायता, समन्वय, गठबंधन और प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रवासियों और शरणार्थियों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति-निर्माताओं को सामाजिक बंधुत्व और एकीकरण के प्रयासों में नागरिक समाज को बतौर एक प्रमुख भागीदार शामिल करना और समर्थन देना आवश्यक है।

प्रवासियों और उनकी स्थितियों के संबंध में ब्राज़ील और भारत में महामारी के बाद भविष्य कैसा दिख सकता है इसे समझना वर्तमान में असंभव लगता है, लेकिन दिमाग़ में यह रखना ज़रूरी है कि सरकारों, अन्य गैर-सरकारी कर्ताओं, और निजी क्षेत्रों के साथ, राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर, साझीदारों के रूप में नागरिक समाज संगठनों की व्यापक पहुँच, दक्षता और महत्वपूर्ण है। भविष्य की योजना को आकार देने में नागरिक समाज संगठन प्रमुख कर्ता हैं। महामारी में उनके व्यापक अनुभवों से सीखने और उनकी क्षमताओं अपनाने दोनों ही कामों के लिए नागरिक समाज संगठनों को शामिल करना प्रवासियों, अतिथि समुदायों और सभी के लिए समाज में समावेश करने के लिए प्रयासों के लिए मुख्य कुंजी होगी।

अनुलग्नक

उपभवन 1. साक्षात्कार की जगह और संगठन के प्रकार

सूची 1: ब्राज़ील में लिए गए इंटरव्यू

क्षेत्र	शहर	संगठन का प्रकार
मध्य-पश्चमि	ब्रासीलिया (संघीय जिला)	2 पंथ /आस्था पर-आधारित 1 प्रवासी-नेतृत्व
	कैंपो ग्रांडे (मातो ग्रोसो दो सुल)	
उत्तरी-पूर्व	फेरा डे सैन्टाना (बहिआ)	1 नागरिक समाज संगठन 2 पंथ /आस्था पर -आधारित
	जोसाओ पेसोआ (पराइबा)	
उत्तर	बोआ विस्टास (रोराइमा)	1 नागरिक समाज संगठन 3 पंथ /आस्था पर -आधारित
	मनाउस (अमज़ोनास)	
दक्षणि-पूर्व	बेलो होरिजोंटे (मिनासगेराइस)	3 नागरिक समाज संगठन 4 पंथ /आस्था पर -आधारित 3 प्रवासी- नेतृत्व
	रिओ डी जेनेरिओ (रिओ डी जेनेरिओ)	
	साओ पाउलो (साओ पाउलो)	
दक्षणि	पोर्टो एलेग्रे (रिओ ग्रांडे दो सुल)	2 नागरिक समाज संगठन 1 पंथ /आस्था पर आधारित 2 प्रवासी-नेतृत्व

सूची 2: भारत में लिए गए इंटरव्यू

प्रवास के प्रकार	क्षेत्र	शहर	संगठन का प्रकार
आंतर प्रवास	उत्तर	दिल्ली, उत्तर-प्रदेश , बिहार	11 नागरिक समाज संगठन 02 प्रवासी-नेतृत्व 03 पंथ /आस्था पर आधारित
	दक्षिण-पश्चिम	मुंबई	2 नागरिक समाज संगठन
आप्रवासन	उत्तर भारत	दिल्ली	1 नागरिक समाज संगठन 2 प्रवासी-नेतृत्व
	पार देशी	पार देशी	
पुन: प्रवासन	दक्षिण-पूर्व	हैदराबाद	1 प्रवासी नेतृत्व
	दक्षिण	केरल	3 नागरिक समाज संगठन 2 पंथ /आस्था पर आधारित

उपभवन 2: साक्षात्कार प्रश्नावली

प्रतिभागी सूचना

- नाम
- संगठन
- स्थान
- संगठन में भूमिका कार्यकाल के वर्ष

अनुभाग 1: स्वास्थ रक्षा संबंधी संकट में प्रवासियों की चुनौतियाँ

- कॉविड 19 के समय में प्रवासियों और शरणार्थियों द्वारा किन मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा है या पड़ रहा है?
- किस प्रकार से स्वास्थ रक्षा संबंधी संकट और आर्थिक संकट ने प्रवासियों और शरणार्थियों के समग्र जीवन स्तर / कल्याण और उनके सामाजिक आर्थिक एकीकरण (रोजगार, आवास, स्वास्थ्य और / या अन्य सामाजिक आर्थिक अधिकारों के संबंध में) को प्रभावित किया है?
- किस प्रकार से स्वास्थ रक्षा संबंधी संकट और आर्थिक संकट ने प्रवासियों और शरणार्थियों के अंतरराष्ट्रीय रिमिटेन्स (प्रेषन) प्रथा को प्रभावित किया है?
- किस प्रकार से इन चुनौतियों नें विभिन्न समूहों को उनकी अन्य भेदयताओं (जैसे - उम्र, यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान, प्रवासन की स्थिति, विकलांगता और जाति) के संबंध में प्रभावित किया है?
- प्रवासी ख़ुद स्वास्थ रक्षा संबंधी संकट से उभरने वाली चुनौतियों का सामना कैसे कर रहें हैं?

अनुभाग 2: सिविल सोसाइटी संगठन: मानकों द्वारा स्थापित अच्छे आचरण की सीख

- आपके संगठन ने किस हद तक और किन तरीकों से, अनुभाग 1 में उल्लिखित कुछ चुनौतियों से उभरने में योगदान दिया है?
- आपके संगठन ने प्रवासियों और शरणार्थियों को क्या सहयोग और सहायता उपलब्ध कराई है? (उदाहरण स्वरूप - कुछ नये कार्यक्रम की शुरुआत, पुराने कार्यक्रमों का विस्तार या सुलभ उपलब्धता के लिए नियमों में लचीलापन इत्यादि)
- आपके कार्यक्रमों द्वारा सहयोग या सहायता में क्या कमियाँ रह गयी हैं?
- क्या आप राष्ट्रीय, राजकीय या स्थानीय स्तर पर उभरने वाले उच्च मानकों द्वारा स्थापित किन्हीं विशेष नीतियों की पहचान कर सकते हैं? (ग्लोबल कॉंपॅक्ट ऑफ माइग्रेशन के संबंध में जानकारी दें)
- महामारी के दौरान प्रवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नागरिक समाज संगठनों, प्रवासी-नेतृत्व समूहों और अन्य हितधारकों (राज्य अभिनेताओं सहित) के बीच क्या कोई नई साझेदारी हुई है? यदि हाँ तो कौन सी?
- क्या आपके संगठन नें इस अवधि के दौरान अन्य क्षेत्रीय संगठनों के साथ कोई साझेदारी या कार्रवाई की है?
- वास्थ रक्षा संबंधी संकट और आर्थिक संकट ने आपके मिशन को पूरा करने की आपके संगठन की क्षमता को कैसे प्रभावित किया है?
- या महामारी के परिणामस्वरूप आपके संगठन के धन अर्जित करने के स्रोत बदल गए हैं? अगर हाँ तो किस हद तक ओर किन तरीकों से?
- वर्तमान परिदृश्य में प्रवासियों और शरणार्थियों के पक्ष में, अंतराष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर क्या कुछ उपाय किए गये हैं जिससे आपके संगठन के नियमों पर प्रभाव पड़े?

अनुभाग 3: वर्तमान परिदृश्य और सुझाव

- सरकारें अपने मानवीय कार्यों का समर्थन और विस्तार करने के लिए तृतीय क्षेत्र के साथ कैसे जुड़ सकती हैं? (नीति के परिप्रेक्ष्य में सुझाव दें)
- वर्तमान परिदृश्य के अंतर्गत, देश में प्रवासियों के एकीकरण और समावेश की संभावनाओं को आप किस नज़र से देखते हैं?
- क्या कोई नया काम, नयी साझेदारी या नया कार्यक्रम है जो संक्रमण अवधि के दौरान और महामारी के बाद आपके संगठन के जारी रखने / बढ़ावा देने की संभावना है?

संदर्भग्रंथ सूची

ACNUR (2021) Conselhos e Comitês para refugiados no Brasil. [online] Available at: https://www.acnur.org/portugues/acnur-no-brasil/conselhos-e-comites-no-brasil/ [Accessed on 20 March 2021].

ACNUR (2020) Brasil se convierte en el país con el mayor número de refugiados venezolanos reconocidos en América Latina. [online] Available at: https://www.acnur.org/noticias/press/2020/1/5e34af654/brasil-se-convierte-en-el-pais-con-el-mayor-numero-de-refugiados-venezolanos.html [Accessed on 19 March 2021].

ACNUR (2020) Brazil Operation: Covid-19 Response. [online] Available at: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Brazil%20COVID-19%20Update%20-%20August%202020.pdf [Accessed on 19 March 2021].

Acosta, D. (2018). The National versus the Foreigner in South America: 200 Years of Migration and Citizenship Law. Cambridge: Cambridge University Press.

Acosta, D., Vera Espinoza, M. and Brumat, L. (2018) Brazil´s Migration Governance: Hidden Actors, the New Law and the 2018 Presidential Elections. Migration Policy Centre (EUI) [Blog] Available at: https://blogs.eui.eu/migrationpolicycentre/brazils-migration-governance-hidden-actors-new-law-2018-presidential-elections/ [Accessed on 23 Feb. 2021].

Alvim, R. P. (2018). Retrospectiva do Trabalho da Defensoria Pública da União na Defesa dos Direitos dos Migrantes Venezuelanos. In: Jarochinski, J.C.S. and Baeninger, R. (eds.). Migrações Venezuelanas. Campinas: Núcleo de Estudos de População Elza Berquó. pp. 206–216.

Avritzer, L. (2007). Sociedade Civil, Instituições Participativas e Representação: da Autorização à Legitimidade da Ação. Dados, 50(3), 443–464.

Baeninger, R. (2018). Governança das Migrações : migrações dirigidas de Venezuleanos e Venezuleanas no Brasil. In: Jarochinski, J.C.S. and Baeninger, R. (eds.). Migrações Venezuelanas. Campinas: Núcleo de Estudos de População Elza Berquó. pp. 135–138.

Baeninger, R. and Peres, R. (2017). Migração de Crise: a migração haitiana para o Brasil. Revista Brasileira De Estudos De População, 34(1), 119-143.

BAL Global (2020) Brazil: COVID-19: Immigration deadlines resume after pandemic suspension. Berry Appleman & Leiden LLP [online] Available at: https://www.balglobal.com/bal-news/brazil-covid-19-immigration-deadlines-resume-after-pandemic-suspension/ [Accessed on 19 March 2021].

Baviskar, B. S. (2001). NGOs and Civil Society in India. Sociological Bulletin, 1(50), 3-15.

BBC News (2020a) Coronavirus: India enters "total lockdown" after spike in cases. [online] Available at: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52024239 [Accessed on 19 March 2021].

BBC News (2020b) Coronavirus: Anger as migrants sprayed with disinfectant in India. [online] Available at: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52093220 [Accessed on 19 March 2021].

Bengochea, J., Cabezas, G., Gandini, L., Herrera, G., Luzes, M., Montiel, C., Prieto, V., Vera Espinoza, M. and Zapata, G.P. (in Press, 2021). COVID-19 y población migrante y refugiada. Análisis de las respuestas político-institucionales en ciudades receptoras de seis países de América Latina. In: Vera, F., Adler, V. and Toro, F. (eds.). Inmigrando: Comprender Ciudades en Transición. Buenos Aires: BID. pp 749-782.

Beteille, A. (1999). Citizenship, State and Civil Society. Economic and Political Weekly, 34(36), 2588-2591.

Bhagat, R. B., R.S., R., Sahoo, H., Roy, A. K. and Govil, D. (2020). The COVID-19, Migration and Livelihood in India: Challenges and Policy Issues. Migration Letters, 17(5), 705–718.

Biswas, N. (2006). On Funding and the NGO Sector. Economic and Political Weekly, 41(42), 4406-4411.

Brazil. (2017). Lei Nº 13.445. Brasília: Presidência da República.

Breman, J. (2008). Footloose Labour: Working in India's Informal Economy. Cambridge: Cambridge University Press.

Brum, E. (2021) Pesquisa revela que Bolsonaro executou uma estratégia institucional de propagação do coronavírus. El País [online] Available at https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-21/pesquisa-revela-que-bolsonaro-executou-uma-estrategia-institucional-de-propagacao-do-virus.html [Accessed on 19 March 2021].

Campanholo, B.G. (2019). Antes do Refúgio: a história não contada da Cáritas Brasileira (1976-1982). M.A Dissertation, Universidade Federal Fluminense.

Castro, F. R. (2020). A Atuação da Sociedade Civil no Processo Brasileiro de Refúgio. Revista Interdisciplinar Da Mobilidade Humana, 28(58), 147–165.

Cavalcanti, L. and de Oliveira, W.F. (2020). Um panorama da imigração e do refúgio no Brasil: Reflexões à guisa de introdução. In: Cavalcanti, L., Oliveira, T. and Macedo, M. (eds.). Imigração e Refúgio no Brasil. Relatório Anual 2020. Série Migrações. Brasília: OBMigra. pp. 8-16.

Chambers, T. (2020) . Network, Labour and Migration among Indian Muslim Artisans. London: UCL Press.

Chandhoke, N. (2003) A Critique of the Notion of the Civil Society as the 'Third Space'. In: Tandon, R. and Mohanty, R. Does Civil Society Matter? Governance in Contemporary India. London: Sage Publications. pp. 27-58.

Chandhoke, N. (2011) Civil Society in India. In: Edwards, M. (eds.). The Oxford Handbook of Civil Society. Oxford: Oxford University Press.

Chandreashekhar, J. (2018) Ascent of the Third Sector in the Indian Socio-Economic Grid. The CJR Journal [online] Available at: https://thecsrjournal.in/ascent-third-sector-indian-socio-economic-grid-wide-spectrum-ngos/ [Accessed 4 March 2021].

Chatterjee. P. (2020) Is India missing COVID-19 deaths? The Lancet, 396(10252), 657.

Choolayil, A. C. and Putran, L. (2021) Covid-19, the Local and the Global: Lessons from Kerala. South Asia Research, 41(1), 7-21.

Cornali, F (2021) La pandemia dejó al descubierto la cara más vulnerable de los inmigrantes en Brasil. Agência Anadolu [online] Available at: https://www.aa.com.tr/es/mundo/la-pandemia-dej%C3%B3-al-descubierto-la-cara-m%C3%A1s-vulnerable-de-los-inmigrantes-en-brasil/1999040 [Accessed on 19 March 2021].

Couto Soares M.C., Maharajh, R. and Scerri M. (2014). Inequality and Development Challenges: BRICS National Systems of Innovation. London: Routledge.

Da Silva, S. A. (2013). Brazil, a new Eldorado for Immigrants? The Case of Haitians and the Brazilian Immigration Policy. Urbanities, 3(2), 3–19.

Dash, S. P. (2001). the State, Civil Society and Democracy: A Note. The Indian Journal of Political Science , 62(2), 241-252.

De Oliveira, A.T. (2013). Um panorama da Migração Internacional a partir do Censo Demográfico de 2010. Revista Internacional de Mobilidade Humana, 21 (40), 195-210.

De Oliveira, E. M. M. and Sampaio, C. (2020). Estrangeiro, nunca mais! Migrante como Sujeito de Direito e a Importância do Advocacy pela Nova Lei de Migração Brasileira. São Paulo: Centro de Estudos Migratórios.

Dey, N. (2020) The role of Civil Society in times of crisis. India Development Review [online] Available at: https://idronline.org/the-role-of-civil-society-in-times-of-crisis/ [Accessed on 23 Feb. 2021).

Dhanagare, D. N. (2001). Civil Society, State and Democracy: Contextualizing a Discourse. Sociological Bulletin, 50(2), 167-191.

EEAS (2020) IOM doctors work in mobile offices in Roraima during the COVID-19 pandemic. [online] Available at https://eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso/79541/iom-doctors-work-mobile-offices-roraima-during-covid-19-pandemic_zh-tw [Accessed on 19 March 2021] .

EQUIDEM (2019) Uncertain Journeys – Migration from Kerala to the Arab Gulf. [online] Available at: https://www.equidemresearch.org/news/uncertain-journeys-migration-from-kerala-to-the-arab-gulf/ [Accessed 7 March 2021].

ET Government (2020) Civil Society: The Third pillar of strength in fight against coronavirus. [online] Available at: https://government.economictimes.indiatimes.com/news/governance/civil-society-the-third-pillar-of-strength-in-fight-against-coronavirus/75642349 [Accessed on 10 March 2021].

Ethiraj, G. (2020) Is Kerala ready for a wave of counter migrants? Indiaspend [online] Available at: https://www.indiaspend.com/is-kerala-ready-for-a-wave-of-counter-migrants/ [Accessed on 14 Feb. 2021].

Fernandes, D. (2015). O Brasil e a Migração Internacional no Século XXI – Notas introdutórias. In: do Prado, E. and Coelho, R. (eds.). Migrações e Trabalho. Brasília: Ministério Público do trabalho.

Fernandes, D. and de Faria, A. V. (2017). O Visto Humanitário como Resposta ao Pedido de Refúgio dos Haitianos. Revista Brasileira de Estudos de População, 34(1), 145–161.

Fischel, J. H. de A. and Marcolini, A. (2002). A Política Brasileira de Proteção e de Reassentamento de Refugiados: Breves Comentários sobre suas Principais Características. Revista Brasileira de Política, 45(1), 168-176.

Formici, G. (2019). The Role of the BRICS Group in the International Arena: A Legal Network under Construction. Third World Thematics: A TWQ Journal, 4(6), 459–74.

Ganguly, S. (2020) India's coronavirus pandemic shines a light on the curse of caste. The Conversation [online]. Available at: http://theconversation.com/indias-coronavirus-pandemic-shines-a-light-on-the-curse-of-caste-139550. [Accessed on 19 March 2021].

Geddes A. and Vera Espinoza, M. (2018). Framing Understandings of International Migration: How Governance Actors Make Sense of Migration in Europe and South America. In: Margheritis, A. (ed.). Shaping Migration between Europe and Latin America. New Approaches and Challenges. London: ILAS publications. pp. 27-50.

Government of India (2020) Vande Bharat Mission. Phase 1. [online] Available at: https://www.mea.gov.in/phase-1.html [Accessed on 18 March 2021].

Governo do Brasil (2020) Coronavírus: conheça as medidas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. [online] Available at: https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/03/medidas-do-ministerio-da-justica-e-seguranca-publica-para-combater-o-coronavirus [Accessed on 19 March 2021].

Governo do Estado do Amazonas (2020) Programa de Redução de Desperdício arrecada 1.100 quilos de alimentos nas feiras da Manaus Moderna e da Banana. [online] Available at: http://www.amazonas.am.gov.br/2020/03/programa-de-reducao-de-desperdicio-arrecada-1-100-quilos-de-alimentos-nas-feiras-da-manaus-moderna-e-da-banana/ [Accessed on 19 March 2021].

Governo do Estado de São Paulo (2020) CIC do Imigrante entrega 200 cestas básicas e milhares de máscaras e álcool em gel. [online] Available at: https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/cic-do-imigrante-entrega-200-cestas-basicas-e-milhares-de-mascaras-e-alcool-em-gel/ [Accessed on 19 March 2021].

Goyal, P. 2020. The Epidemic Diseases Act, 1897 Needs An Urgent Overhaul. EPW Engage, 55(45).

Guadagno, L. (2020). Migrants and the COVID-19 Pandemic: An Initial Analysis. Geneva: International Organization for Migration.

Haokip, T. (2021). From "Chinky" to "Coronavirus": racism against Northeast Indians during the Covid-19 pandemic. Asian Ethnicity, 22(2), 353–373.

Hugueney, V. and Godinho, L.F. (2021) COVID-19: ACNUR y sus socios apoyan a refugiados y comunidades de acogida en Brasil. ACNUR [online]. Available at: https://www.acnur.org/noticias/noticia/2020/3/5e7c54484/covid-19-acnur-y-sus-socios-apoyan-a-refugiados-y-comunidades-de-acogida.html# [Accessed on 19 March 2021].

Human Rights Watch (n.d) Kafala System. [online] Available at: https://www.hrw.org/tag/kafala-system#,%20https://www.cfr.org/backgrounder/what-kafala-system [Accessed on 3 March 2021]

IBGE. (2021). Projeção da população. [online] Available at: https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/box_popclock.php [Accessed on 19 March 2021].

IBSA - Trilateral (2020) About IBSA. [online] Available at: http://www.ibsa-trilateral.org/ [Accessed on 23 Feb. 2021].

Inamdar, N. (2020) Coronavirus lockdown: India jobless numbers cross 120 million in April. BBC News [online] Available at: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52559324 [Accessed on 19 March 2021].

IOM (2019). IOM Handbook on Protection and Assistance for Migrants Vulnerable to Violence, exploitation and abuse. Geneva: International Organisation for Migration.

Jarochinski, J. C.Jubilut, L. L. and Velásquez, M. Z. P. (2020). Proteção Humanitária no Brasil e a Nova Lei de Migrações. In: Ramos, A., Vedovato, L. and Baeninger, R. (eds.). Nova Lei da Migração no Brasil: primeiros três anos. Campinas: Núcleo de Estudos de População Elza Berquó. pp. 47–66.

Jatobá, D. and Martuscelli, P. N. (2018). Brazil as a leader in the Latin American Refugees' Regime. The Journal of International Relations, 4(1), 1–28.

Jubilut, L. L. (2006). Refugee Law and Protection in Brazil: a Model in South America? Journal of Refugee Studies, 19(1), 22-44.

Jubilut, L. L., and Apolinário, S. M. de O. (2008). Refugee Status Determination in Brazil a Tripartite Enterprise. Refuge, 25(2), 29–40.

Karasapan, O. (2020) Pandemic highlights the vulnerability of migrant workers in the Middle East. Brookings [online] Available at: https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/09/17/pandemic-highlights-the-vulnerability-of-migrant-workers-in-the-middle-east/ [Accessed on 5 March 2021].

Keshri, K. and Bhagat, R. B. (2010). Temporary and Seasonal Migration in India . Genus, 3(66), 25-45.

Kikon, D. (2020) The Long way Home: Tribulations of Migrants from Northeast India. Australia India Institute [online] Available at: https://www.aii.unimelb.edu.au/blog/covid-19-and-india/the-long-way-home-tribulations-of-migrants-from-northeast-india/ [Accessed on 5 March 2021].

Khadria, B. (2020) COVID-19: Why are migrant workers so desperate to move out?, Down to Earth [online] Available at https://www.downtoearth.org.in/blog/urbanisation/covid-19-why-are-the-migrant-workers-so-desperate-to-move-out--70482 [Accessed 15 March 2021].

Kode, D. and Jacob, M. (2017). India: Democracy Threatened by Growing Attacks on Civil Society. Delhi: CIVICUS.

Korobkov A. V. (2015). BRICS Members and the Migration Challenges. Tractus Aevorum, (2)2, 190-203.

Leivon, J., Deb, D. and Agarwala, T. (2020) Behind Northeast's Covid-19 surge, stranded migrants returning home. The Indian Express [online] Available at: https://indianexpress.com/article/north-east-india/behind-northeasts-covid-19-surge-stranded-migrants-returning-home-6457181/ [Accessed on 19 March 2021].

Lesser, S. and Wejsa, J. (2018) Migration in Brazil: The Making of a Multicultural Society. Migration Policy Institute [online] Available at: https://www.migrationpolicy.org/article/migration-brazil-making-multicultural-society [Accessed on 3 March 2021].

Lotta, G., Fernandez, M., Ventura, D., Rached H.D., Amorim, M., Barberia, L. G., Moraes De Sousa, T. and Wenham, C. (2020) Who Is Responsible for Brazil's COVID-19 Catastrophe? LSE Latin America and Caribbean Blog [Blog] Available at: https://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2020/11/13/who-is-responsible-for-brazils-covid-19-catastrophe/ [Accessed on 24 Feb. 2021].

Machado, I. J. de R. (2020). Securitization (Re)Turn: Analysis of the New Brazilian Migration Laws (2016-2019). Middle Atlantic Review of Latin American Studies, 4(2), 213-214.

Mamed, L. H. (2016). Haitianos na Amazônia: a Morfologia da Imigração Haitiana pelo Acre e o Horizonte de Inserção Precarizada no Brasil. Ruris, 10(1), 73–11.

Maraa, Media and Arts Collective (2020). Behind the Metro Pillars. [online] Available at: https://www.maraa.in/wp-content/uploads/2020/04/behind-the-metro-pillars_final.pdf [Accessed on 24 Feb. 2021].

Margolis, M. (2013). Goodbye, Brazil: emigrantes brasileiros no mundo. São Paulo: Editora Contexto.

Martuscelli, P. N. (2020). Fighting for Family Reunification: the Congolese Experience in São Paulo, Brazil. Journal of Refugee Studies, 0(00), 1–24.

Mehrotra, S. (2019). Informal Employment Trends in the Indian Economy: Persistent Informality, but growing positive development. Geneva: Employment Policy Department, ILO.

Milesi, R. and Coury, P. (2018). Acolhida, Proteção e Integração de Venezuelanos no Brasil : a Atuação do Instituto Migrações e Direitos Humanos. In: Jarochinski, J. C. S. and Baeninger, R. Migrações Venezuelanas. Campinas: Núcleo de Estudos de População Elza Berquó. pp. 72–77.

Milesi, R., Coury, P. and Rovery, J. (2018). Migração Venezuelana ao Brasil: discurso político e xenofobia no contexto atual. Aedos, 10(22), 53–70.

Milesi, R. and de Andrade, W. C. (2017). Fazendo Memória do Processo de Construção da Lei de Refugiados no Brasil. Refúgio, Migrações e Cidadania, 12(12), 47-75.

Ministério da Justiça (2021) Comitês Estaduais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. [online] Available at https://www.novo.justica.gov.br/sua-protecao-2/trafico-de-pessoas/redes-de-enfrentamento/comites-1 [Accessed on 24 March 2021].

Mohan, S. (2002). Role and Relevance of Civil Society Organizations . The Indian Journal of Political Science, 63(2/3), 193-211.

Mohanty, S. (2020). From communal violence to lockdown: hunger emergency responses by civil society networks in Delhi. Oxfam [blog] Available at: https://oxfamblogs.org/fp2p/from-communal-violence-to-lockdown-hunger-emergency-responses-by-civil-society-networks-in-delhi/ [Accessed on 23 Feb. 2021].

Moreira, J. B. (2010). Redemocratização e direitos humanos: a política para refugiados no Brasil. Revista Brasileira de Política Internacional, 53(1), 111–129.

Moulin C. and Magalhaes, B. 2020. Operation shelter as humanitarian infrastructure: material and normative renderings of Venezuelan migration in Brazil. Citizenship Studies, 24 (5), 642-662.

Moulin, C. (2012). Ungrateful subjects? Refugee protests and the logic of gratitude. In: Nyers, P. and Rygiel, K. (eds.). Citizenship, Migrant Activism and the Politics of Movement. London: Routledge. pp. 54-72.

Murshid, N. (2016). Assam and the Foreigner Within. Asian Survey, 56(3), 581-604.

Nair, P. (2020) India's internal migrants are citizens too: the Government Must Protect them, The Conversation, June 15th 2020 [online] Available at: https://theconversation.com/indias-internal-migrants-are-citizens-too-the-government-must-protect-them-140295 [Accessed on 1 April 2021].

Nair, P. and Vera Espinoza, M. (2021) Migration, Pandemic and Responses from the Third Sector. Global Policy Institute [blog] Available at: https://www.qmul.ac.uk/gpi/news-and-events/news/migration-pandemic-and-responses-from-the-third-sector---lessons-from-brazil-and-india.html [Accessed on 21 February 2021].

OIM (2020) A pesar de la pandemia, la reubicación y asistencia brindada a venezolanos en Brasil no se detiene. SPIC, Brasil [online] Available at: https://www.iom.int/es/news/pesar-de-la-pandemia-la-reubicacion-y-asistencia-brindada-venezolanos-en-brasil-no-se-detiene [Accessed on 19 March 2021].

Oommen, T. K. (2001). Civil Society: Religion, Caste and Language . Sociological Bulletin, 50(2), 219-235.

PAHO (2017) Brazil. [online] Available at: https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?p=4246 [Accessed on 19 March 2021].

Pannunzio, E. (2013). Pautas para o aperfeiçoamento do fomento público às OSCs no Brasil. In: Mendonça, P. M. E., Alves, M.A. and Nogueira, F. do A. (eds.). Arquitetura Institucional de Apoio às Organizações da Sociedade Civil no Brasil. São Paulo: FGV. pp 167-179.

Patel, C. (2020) COVID-19: The Hidden Majority in India's Migration Crisis. Chatham House [online] Available at: https://www.chathamhouse.org/2020/07/covid-19-hidden-majority-indias-migration-crisis [Accessed on: 19 March 2021).

Pethiyagoda, K. (2017) Supporting Indian workers in the Gulf: What Delhi can do. Brookings [online] Available at: https://www.brookings.edu/research/supporting-indian-workers-in-the-gulf-what-delhi-can-do/] [Accessed on 9 March 2021].

Prefeitura de São Paulo (2021) Conselho Municipal de Imigrantes. [online] Avaliable at: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/imigrantes_e_trabalho_decente/conselho_municipal_de_imigrantes/index.php [Accessed on 30 March 2021].

Press Information Bureau of India (2020) PM addresses nation on combating COVID-19. Prime Minister's office [online] Available at: https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1607248 [Accessed on 18 March 2021].

PRIA and VANI. (2020). Response of Indian Civil Society Towards COVID-19. Delhi: PRIA and VANI.

Rajan, I., Sivakumar, P. and Srinivasan, A. (2020). The COVID-19 Pandemic and Internal Labour Migration in India: A Crisis of Mobility. The Indian Journal of Labour Economics, 63(4), 1021–1039.

Ramachandran, B. (2020) Where India's government has failed in the pandemic its people have stepped in. The Guardian [online] Available at: https://www.theguardian.com/global-development/commentisfree/2020/may/05/where-indias-government-has-failed-in-the-pandemic-its-people-have-stepped-in-coronavirus [Accessed on 23 Feb. 2021].

Rao, N., Narain, N., Chakraborty, S., Bhanjdeo, A. and Pattnaik, A. (2020). Destinations Matter: Social Policy and Migrant Workers in the Times of Covid. The European Journal of Development Research, 32(5), 1639–1661.

Rastogi, N. and Wu, A. M. (2020) Indian civil society sidelined in a pandemic. East Asia Forum [online] Available at: https://www.eastasiaforum.org/2020/10/30/indian-civil-society-sidelined-in-a-pandemic/ [Accessed on 14 Feb. 2021].

Rawat, M. (2020) In 13 states NGOs fed more people that government during coronavirus lockdown. India Today [online] Available at: https://www.indiatoday.in/india/story/in-13-states-ngos-fed-more-people-than-govt-during-coronavirus-lockdown-1665111-2020-04-09 [Accessed on 14 Feb. 2021].

Reid, D. (2020) India confirms its first coronavirus case. CNBC [online] Available at: https://www.cnbc.com/2020/01/30/india-confirms-first-case-of-the-coronavirus.html [Accessed on 5 March 2021].

Rocha, E. (2008). A Constituição Cidadã e a institucionalização dos espaços de participação social: avanços e desafios. In: Vaz, F. T., Musse, J. S. and dos Santos, R. F. (eds.). 20 Anos da Constituição Cidadã. Brasília: Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. pp. 131–148.

Rustagi N & Wu, A.M. (2020) Indian Civil Society sidelined in a pandemic. East Asia Forum [online] Available at: https://www.eastasiaforum.org/2020/10/30/indian-civil-society-sidelined-in-a-pandemic/ [Accessed 3 March 2021].

Sahoo, A. K. (2015). Diaspora, Development and Distress: Indians in the Persian Gulf. Jaipur: Rawat Publications.

Sahoo, S. (2013). Civil Society and Democratization in India. London: Routledge.

Salle, V. S. K. (2020) COVID-19 crisis: Uncertainty ahead for migrant workers. EastMojo [online] Available at: https://www.eastmojo.com/news/2020/05/31/covid-19-crisis-uncertainty-ahead-for-migrant-workers/ [Accessed on 5 March 2021].

Shah, G. (2019). Democracy, Civil Society and Governance. New Delhi: Sage Publications.

Sharma, I. (2020) COVID-19 and Political Unrest in Northeast India. ACLED [online] Available at: https://acleddata.com/2020/10/26/covid-19-and-political-unrest-in-northeast-india/ [Accessed on 19 March 2021].

Singha, K. (2018). Migration, Ethnicity-based Movements and State's Response: A Study of Assam. International Studies, 55(1), 41-60.

Sircar, J. (2020) A Long Look at Exactly Why and How India Failed Its Migrant Workers. The Wire [Blog] Available at: https://thewire.in/labour/lockdown-migrant-workers-policy-analysis [Accessed on 24 Feb. 2021].

Sitlhou, M. (2020) Coronavirus in the UAE: Migrant workers from northeast India desperate to get home. Middle East Eye [online] Available at: http://www.middleeasteye.net/fr/node/175451 [Accessed on 19 March 2021].

Srivastava, S.S. and Tandon, R. (2005).How Large is India's Non-Profit Sector? Economic and Political Weekly, 40 (19), 1948-1952.

Statista Research Department (2020) Internal migrant population share in India 2001-2011 by type. [online] Available at: https://www.statista.com/statistics/1111480/india-internal-migrant-population-share/#statisticContainer] [Accessed on 9 March 2021].

Suresh R. and James J, R. (2020). Migrant Workers at Crossroads-The Covid-19 Pandemic and the Migrant Experience in India. Soc Work Public Health, 35(7), 633-643.

The Hindu (2020) COVID-19 lockdown: Migrant workers from Northeast feeling insecure to return to workplace, says AIMO. The hindu [online] Available at: https://www.thehindu.com/news/national/other-states/covid-19-lockdown-migrant-workers-from-northeast-feeling-insecure-to-return-to-workplace-says-aimo/article31299595.ece [Accessed on 5 March 2021].

The Lancet (2020) COVID-19 in India: the dangers of false optimism. The Lancet [online]. Available at: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32001-8/fulltext [Accessed on 5 March 2021].

The Wire (2020) Centre Says It Has No Data on How Many Migrant Workers Died in the COVID-19 Lockdown. The Wire [online] Available at: https://thewire.in/rights/centre-lok-sabha-migrant-worker-death-data [Accessed on 19 March 2021].

Tumbe, C. (2018). India Moving: A History of Migration. New Delhi: Penguin.

UNDESA. (2020). World Social Report 2020: Inequality in a Rapidly Changing World. New York: United Nations

UNHCR (2017) Migrants in Vulnerable Situations – UNHCR perspective. [online] Available at: https://www.refworld.org/docid/596787174.html [Accessed on 22 Feb. 2021].

Upadhyay, V. (2008). Ethnic Polarisation And Human Security: The Case Of Migrants In Northeast India. World Affairs: The Journal of International Issues, 12(1), 152-174.

Vera Espinoza, M., Prieto, V., Zapata, G., Gandini, L., Herrera, G., Reguera, A., Lopez, S., Zamora, C., Montiel, C., Cabezas, G. and Paella, I. (forthcoming). Migrants and Refugees in Latin America during COVID-19: An Inclusion/Exclusion Spectrum of Social Protection. Comparative Migration Studies.

Vera Espinoza, M., Zapata, G. Gandini, L. (2020) Mobility in Immobility: Latin American Migrants Trapped amid COVID-19. Open Democracy [Blog] Available at: https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/mobility-immobility-latin-american-migrants-trapped-amid-covid-19/ [Accessed on 19 Feb. 2021].

Vera Espinoza, M. (2018). The Politics of Resettlement: Expectations and Unfulfilled Promises in Chile and Brazil. In: Garnier, A., Jubilut, L. L. and Sandvik, K. B. (eds.). Refugee Resettlement. Oxford: Berghahn Books. pp. 223-243.

Vera Espinoza, M., (2018) The Limits and Opportunities of Regional Solidarity: Exploring Refugee Resettlement in Brazil and Chile. Global Policy, 9(1), 85-94.

Véran, J. F., Noal, D. and Fainstat, T. (2014). Nem Refugiados, nem Migrantes: A Chegada dos Haitianos à Cidade de Tabatinga (Amazonas). Dados, 57(4), 1007–1041.

Vinod, M. J. (2006). The Changing Dimensions of Civil Society in the Twenty-First Century: Theory Versus Reality . The Indian Journal of Political Science , 67(4), 783-792.

Waltrick, A. (2019) Letter to António Guterres. [online] Available: https://ungc-production.s3.us-west-2.amazonaws.com/commitment_letters/137611/original/Global_Pact_-_SPIC_Brasil.pdf?1570827115 [Accessed on 19 March 2021].

Weiner, M. (1983). The Political Demography of Assam's Anti-Immigrant Movement. Population and Development Review, 9(2), 279-292.

Wejsa, S. and Lesser, J. (2018) Migration in Brazil: The Making of a Multicultural Society. Migration Policy Institute [online] Available at: https://www.migrationpolicy.org/article/migration-brazil-making-multicultural-society [Accessed on 19 March 2021].

WHO (2021) Global Brazil, Brazil: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. [online] Available at: https://covid19.who.int/region/amro/country/br [Accessed on 19 March 2021].

Wordometer (2021) India Coronavirus: 11,514,331 Cases and 159,405 Deaths. [online] Available at: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/india/ [Accessed on 19 March 2021].

World Bank (2020) COVID-19 Crisis Through a Migration Lens. [online] Available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33634 [Accessed on 21 Feb. 2021].

Yasir, S. (2020) India's Covid-19 Death Toll Passes 100,000. The New York Times [online] Available at: https://www.nytimes.com/2020/10/03/world/asia/india-coronavirus-deaths.html [Accessed on 5 March 2021].

Youngs, E. (2020). Introduction. In: Youngs, E. (ed.). Global Civil Society in the Shadow of Coronavirus. Washington: Carnegie Endowment for International Peace.

Zapata, G. P. and Tapia, V. (forthcoming). Progressive Legislation but Lukewarm Policies: The Brazilian Response to Venezuelan Displacement. International Migration.

Zapata, G. P. and Fazito, D. (2018). Comentário: o significado da nova lei de migração 13.445/17 no contexto histórico da mobilidade humana no Brasil. Revista Da Universidade Federal de Minas Gerais, 25(1 e 2), 224–237.

Zapata, G. P. and Prieto Rosas, V. (2020). Structural and Contingent Inequalities: The Impact of COVID 19 on Migrant and Refugee Populations in South America. Bulletin of Latin American Research, 39 (1), 16–22.

Zortea, G. (2017). Benefício de Prestação Continuada – BPC em Favor de Imigrantes Residentes no País. In: Jarochinski, J. C. S. and Baeninger, R. (eds.). Refúgio, Migrações e Cidadania. São Paulo: Instituto Migrações e Direitos Humanos. pp. 47–74

Queen Mary
University of London

Prof Parvati Nair,
School of Languages, Linguistics and Film
email: p.nair@qmul.ac.uk

Dr Marcia Vera Espinoza,
School of Geography
email: m.vera-espinoza@qmul.ac.uk

@qmul
@qmul
officialqmul

qmul.ac.uk/gpi